



# LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

*The House met at Eleven of the Clock*

Monday, July 22, 2024 / Ashadha 31, 1946 (Saka)

**HON'BLE SPEAKER**

**Shri Om Birla**

**PANEL OF CHAIRPERSONS**

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

# LOK SABHA DEBATES

## PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, July 22, 2024 / Ashadha 31, 1946 (Saka)

<u>CONTENTS</u>	<u>PAGES</u>
MEMBER SWORN – Contd.	1
OBITUARY REFERENCE	1
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 1 – 5)	1A – 30
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 6 – 20)	31 – 50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 1 – 230)	51 – 280



सत्यमेव जयते

## **LOK SABHA DEBATES**

**(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)**

**Monday, July 22, 2024 / Ashadha 31, 1946 (Saka)**

# LOK SABHA DEBATES

## PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

*Monday, July 22, 2024 / Ashadha 31, 1946 (Saka)*

<u>C O N T E N T S</u>	<u>P A G E S</u>
RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	281
PAPERS LAID ON THE TABLE	281 - 96
ELECTION TO COMMITTEE	297
Central Building and Other Construction Workers' Advisory Committee	
MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	298 - 320
MATTERS UNDER RULE 377	321 - 37
Dr. Hemant Vishnu Savara	321
Shri Kripanath Mallah	321
Dr. Vinod Kumar Bind	322
Shri Jagdambika Pal	322
Shri Madhavaneni Raghunandan Rao	322
Dr. Rajeev Bharadwaj	323
Shri Rajkumar Chahar	324
Shri Yogender Chandolia	324
Shrimati Smita Uday Wagh	325
Dr. Jayanta Kumar Roy	325
Shri Gopal Jee Thakur	326
Shri V.K. Sreekandan	326

<b>Shri Ramasahayam Raghuram Reddy</b>	<b>327</b>
<b>Prof. Varsha Eknath Gaikwad</b>	<b>328</b>
<b>Shri Pradyut Bordoloi</b>	<b>329</b>
<b>Shri Anto Antony</b>	<b>329</b>
<b>Shri K.C. Venugopal</b>	<b>330</b>
<b>Shri Rajeev Rai</b>	<b>330</b>
<b>Shri Devesh Shakya</b>	<b>331</b>
<b>Shrimati Sajda Ahmed</b>	<b>331</b>
<b>Shri Khalilur Rahaman</b>	<b>332</b>
<b>Shri D. M. Kathir Anand</b>	<b>332</b>
<b>Shri Kesineni Sivanath</b>	<b>333</b>
<b>Dr. Alok Kumar Suman</b>	<b>333</b>
<b>Shri Anil Yeshwant Desai</b>	<b>334</b>
<b>Shri Abhay Kumar Sinha</b>	<b>334</b>
<b>Shri Maddila Gurumoorthy</b>	<b>335</b>
<b>Shri N.K. Premachandran</b>	<b>335</b>
<b>Shri Ananta Nayak</b>	<b>336</b>
<b>Dr. K. Sudhakar</b>	<b>337</b>
<b>RE: BUSINESS OF THE HOUSE</b>	<b>338</b>
<b>DISCUSSION RE: INDIA'S PREPAREDNESS FOR THE UPCOMING OLYMPIC GAMES (Inconclusive)</b>	<b>339 - 84</b>
<b>Dr. Sanjay Jaiswal</b>	<b>339 - 41</b>
<b>Shri Deepender Singh Hooda</b>	<b>342 - 47</b>
<b>Shri Neeraj Maurya</b>	<b>348 - 49</b>

<b>Shri Kirti Azad</b>	<b>350 - 52</b>
<b>Shri D.M. Kathir Anand</b>	<b>353 - 57</b>
<b>Shri G.M. Harish Balayogi</b>	<b>358 - 60</b>
<b>Shri Shrirang Appa Chandu Barne</b>	<b>361 - 62</b>
<b>Shri Abhay Kumar Sinha</b>	<b>363</b>
<b>Shri Rajiv Pratap Rudy</b>	<b>364 - 68</b>
<b>Md. Rakibul Hussain</b>	<b>369 - 70</b>
<b>Shri Malvinder Singh Kang</b>	<b>371 - 72</b>
<b>Shri Kaushalendra Kumar</b>	<b>373 - 74</b>
<b>Shri Chandan Chauhan</b>	<b>375 - 76</b>
<b>Shri Naveen Jindal</b>	<b>377 - 78</b>
<b>@ Shri Navaskani K.</b>	<b>379</b>
<b>Shri Karti P. Chidambaram</b>	<b>380</b>
<b>Shri N.K. Premachandran</b>	<b>381 - 82</b>
<b>Adv. Chandra Shekhar</b>	<b>383 - 84</b>

**XXXX**

---

**@ For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Navaskani K. in Tamil, please see the Supplement (PP 379A to 379B).**

# LOK SABHA DEBATES

## PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

*Monday, July 22, 2014 / Ashadha 31, 1946 (Saka)*

### S U P P L E M E N T

<u>CONTENTS</u>				<u>PAGES</u>
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Xxx	xxx	xxx	xxx
	Xxx	xxx	xxx	xxx
xxx		xxx	xxx	xxx
DISCUSSION RE: INDIA'S PREPAREDNESS FOR THE UPCOMING OLYMPIC GAMES				379A - 79B
xxx		xxx	xxx	xxx
	Shri Navaskani K.			379A - 79B
xxx		xxx	xxx	xxx



(1100/VB/PS)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

(राष्ट्र गान की धुन बजाई गई।)

माननीय अध्यक्ष : महासचिव।

**MEMBER SWORN – contd.**

SECRETARY-GENERAL: West Bengal - Shri Shatrughan Prasad Sinha.

**WEST BENGAL**

Shri Shatrughan Prasad Sinha (Asansol)

....

**निधन संबंधी उल्लेख**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यो, मुझे सदन को वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के माननीय महासचिव श्री गुयेन फु ट्रोंग के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री ट्रोंग का 80 वर्ष की आयु में हनोई में दिनांक 19 जुलाई, 2024 को निधन हो गया। महासचिव श्री गुयेन फु ट्रोंग पिछले 13 वर्षों से इस पद पर आसीन सबसे वरिष्ठ वियतनामी राजनेता थे और वियतनाम में उनका व्यापक सम्मान किया जाता था। इससे पहले उन्होंने वियतनाम के समाजवादी गणराज्य की नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष और देश में कई वरिष्ठ राजनीतिक पदों पर कार्य किया।

महासचिव श्री गुयेन फु ट्रोंग ने दशकों से वियतनाम की प्रगति और विकास में केन्द्रीय भूमिका निभाई। उन्होंने भारत-वियतनाम मित्रता और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीति और साझेदारी में योगदान भी दिया।

वे वर्ष 2013 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे और मुझे अप्रैल, 2022 में वियतनाम में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते समय उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

यह सदन दुख की इस घड़ी में वियतनाम के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता है और महामहिम श्री गुयेन फु ट्रोंग के निधन पर वियतनाम की सरकार, समाजवादी गणराज्य के नेतृत्व तथा वहाँ की मित्रवत जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।

सदन अब दिवंगत आत्मा की स्मृति में कुछ देर मौन रहेगा।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

(1105/VB/SMN)

**(प्रश्न 1 और 2)****माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न संख्या 1, श्री राहुल कस्वां।**श्री राहुल कस्वां (चुरु) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

महोदय, देश के अन्दर 15 दिसम्बर, 1963 को पहला केन्द्रीय विद्यालय खोला गया। उसके बाद आज तक देश में करीब 1253 स्कूल्स खोले गए हैं। मंत्री महोदय के जवाब के अनुसार, अगर मैं बीते पाँच सालों की बात करूँ, तो 48 नये स्कूल्स खुले, जिनमें से राजस्थान प्रदेश को मात्र दो स्कूल्स मिले हैं। पिछले 56 वर्षों में, जिस स्पीड से स्कूल्स खुले, करीब 22 स्कूल्स प्रति वर्ष खुलते गए और बीते पाँच वर्षों में मात्र दो स्कूल्स ही प्रति वर्ष खुले। एक तो यह स्पीड बहुत ही कम है और इसके लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई थी, वह गाइडलाइंस वर्ष 1963 के हिसाब से बनाई गई थी।

आज बदलता हुआ वक्त है और आपकी ही सरकार 'अमृत सिटीज' नाम से बड़े-बड़े शहरों को विकसित कर रही है, जिनकी एक लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है। सर, मैं आपकी मार्फत से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार अपनी नीति में परिवर्तन लाएगी ताकि एक लाख से अधिक की आबादी वाली जो सिटीज हैं, जैसे मेरे लोक सभा क्षेत्र का सुजानगढ़ शहर है, जिसकी पॉपुलेशन एक लाख से ऊपर है, नीति में परिवर्तन लाने के बाद क्या आप ऐसे शहरों में स्कूल्स खोलने का कोई प्रावधान करेंगे?

**श्री जयंत चौधरी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है। मैं समझ सकता हूँ कि यह लाजिमी है क्योंकि केन्द्रीय विद्यालय संगठन की जो साख है, उसे देखते हुए सभी सांसद चाहते हैं कि उनके क्षेत्रों में इसका विस्तार हो। पूरे देश में 1253 केन्द्रीय विद्यालय खुले हैं। छः दशकों में, चाहे एकेडेमिक परफॉर्मेंस हो, आप किसी भी मानक को देखेंगे, तो दूसरी संस्थाओं को सरपास कर रहा है।

माननीय सदस्य ने राजस्थान के संबंध में सवाल पूछा है, जिसमें मुख्य रूप से सुजानगढ़ के बारे में सवाल पूछा गया है। सुजानगढ़ के संबंध में हमारे पास अभी कोई प्रस्ताव पेश नहीं हुआ है। इसकी एक पुरानी प्रक्रिया है, नियम है, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है।

**श्री राहुल कस्वां (चुरु) :** माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यही बात पूछी है कि क्या पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज की तारीख में, जहाँ दूर-दराज में स्कूल्स हैं, आज चुरु में जहाँ पर केन्द्रीय विद्यालय है, वहाँ से सुजानगढ़ की दूरी 150 किलोमीटर है। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम 'अमृत सिटीज' के तहत, जहाँ एक लाख की पॉपुलेशन है, हम उसे तो टारगेट करें और सुजानगढ़ को भी इसमें प्रायोरिटी पर लें।

इसी तरह से, आपने उत्तर में कहा है कि पूरे देश भर में सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉयर लर्निंग के 12 स्कूल्स खोले गए हैं। इनमें से राजस्थान को एक भी स्कूल नहीं मिला है। यह जरूर एक अच्छा कांसेप्ट है, लेकिन इस कांसेप्ट में राजस्थान को इससे वंचित किया गया है। क्या आप इसकी शुरुआत सुजानगढ़ से करना चाहेंगे? मेरा आपसे यह निवेदन है।

**श्री जयंत चौधरी :** माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसकी एक प्रक्रिया है। उस नीति के तहत केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया जाता है। उसके कुछ मानक भी हैं। पहले तो हमें प्रस्ताव प्राप्त होना चाहिए। यह प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा होना चाहिए। वहाँ के मंत्रालय या विभाग इसकी स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ-साथ, प्रोजेक्ट मोड में भी केन्द्रीय विद्यालयों का निर्माण होता है। माननीय सदस्य जिन 12 केन्द्रीय विद्यालयों का जिक्र कर रहे हैं, वे प्रोजेक्ट मोड में हुए हैं। राजस्थान हमारी सरकार की प्राथमिकता में रहा है। आगे भी केन्द्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, वहाँ हमारी जो संस्थाएं हैं, उनकी देखरेख को लेकर, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर हम निरंतर काम करते हैं। हमारी नीति में मुख्य प्रावधान यह है कि किस हिसाब से केन्द्रीय विद्यालय स्थापित होगा, पहले तो प्रस्ताव आना चाहिए, जमीन आवंटित होनी चाहिए और टेम्परेरी एकोमोडेशन की सुविधा भी होनी चाहिए। उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** केन्द्रीय कर्मचारी भी होने चाहिए।

**श्री जयंत चौधरी :** जी हाँ।

**माननीय अध्यक्ष :** मैं माननीय सदस्यगण से आग्रह करना चाहता हूँ कि यह प्रश्नकाल का पहला दिन है। माननीय सदस्यगण प्रश्न संक्षेप में पूछें और माननीय मंत्री जी भी संक्षेप में जवाब दें। ऐसा करने से, हम ज्यादा प्रश्न ले सकते हैं। यह मेरा आग्रह है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** सभी माननीय सदस्यगण, जो प्रथम बार आए हैं, उनको हम पर्याप्त मौका देंगे। मैंने कनिमोजी जी को बता दिया है। मैंने वरिष्ठ सदस्यों से भी आग्रह किया है कि प्रथम बार चुनकर आए हुए सदस्यों को प्राथमिकता देने का मेरा आग्रह है, जिसे सदन मानेगा।

श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोला

(11110/SM/SPS)

SHRI GOVIND MAKTHAPPA KARJOL (CHITRADURGA): Hon. Speaker, Sir, my parliamentary constituency, Chitradurga is the most backward area in the country. More than 52 per cent of its population belong to SC, ST and Kadugolla community. They are very poor and their children are not getting quality education. So, I request the Government to kindly instruct the competent authority to accord the approval immediately.

**श्री जयंत चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, सवाल मुझे नहीं दिखा है, लेकिन एक मांग उठाई गई है। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि उनका जो प्रस्ताव है, अभी उस पर विचार हो रहा है और कई स्तरों पर उसको एग्जामिन किया जा रहा है।

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी, यहां प्रश्न काल में मांग ही उठती है। यदि मांग नहीं उठेगी तो प्रश्न काल में क्या उठेगा।

SHRI SHAFI PARAMBIL (VADAKARA): Hon. Speaker, Sir, I would like to know the expected timeline of the construction of the building of KV at Thalassery. The State Government has already allotted eight acres of land for the same.

We deserve one more KV in my constituency. It is a hugely populated area. It is a large constituency. We request you to allot one more KV in Vadakara region for my parliamentary constituency.

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी, आप बता दें कि यह प्रश्न काल है। इस विषय पर आप उनको चैम्बर में बुलाकर चर्चा कर लेंगे।

**श्री जयंत चौधरी :** अध्यक्ष जी, इन्होंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, उस बिंदू पर मैं इनको व्यक्तिगत तौर से पूरी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री टी. तमिलसेल्वन...

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** धीरे-धीरे नाम आ जाएगा। अभी कुछ कठिनाई होती है। यह स्वाभाविक है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अगर नाम शुद्ध न हो तो आप बोल दिया करें, ठीक कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

\*SHRI TAMILSELVAN THANGA (THENI): Hon. Speaker, Sir, *vanakkam*. During the previous Government, there was a news that a Kendriya Vidyalaya would be started in Theni parliamentary constituency. But there is no indication as of now in this regard. I wish to ask whether this Government would come forward to start a Kendriya Vidyalaya in Theni parliamentary constituency.

**श्री जयंत चौधरी :** अध्यक्ष जी, जैसा इन्होंने खुद कहा है कि अभी उसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। जब तक सैंक्शन नहीं होता है, तब तक उसकी घोषणा नहीं की जा सकती है।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, Question no. 2 may be clubbed with Question no. 1.

HON. SPEAKER: Okay.

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, can the Minister provide specific details on the measures being implemented to ensure the integrity of the examination process and prevent future incidents of paper leaks including any technological advancements or additional security protocols? Given the recurrence of such issues – it is 70 times in seven years – how does the Minister plan to restore trust in the system?

---

\* Original in Tamil

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Hon. Speaker, Sir, hon. Member has raised a question regarding question paper leaks for 70 times in the last seven years. With full responsibility, I would like to submit in the House through you, Sir, that there is no evidence of paper leak of any number in the last seven years ... (*Interruptions*)

There are incidents. This case is already in the Supreme Court... (*Interruptions*) All the things have come out. Every question has been put in front of the Supreme Court. CBI is investigating this matter ... (*Interruptions*) With full responsibility, I can say that more than 240 examinations have been conducted by NTA; more than five crore students have applied and more than 4 and half a crore students have successfully participated in the examinations. These are all facts in record.

(1115/RP/PC)

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, in light of the severe breach in the examination process and its significant impact over 24 lakh students, does the Minister accept the responsibility for these failures? Given the gravity of the situation and the accountability and integrity of the Office, will the Minister consider resigning?

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Speaker, Sir, I am here at the mercy of my leader, the hon. Prime Minister. ... (*Interruptions*) Whenever the question of accountability comes, my Government is collectively answerable to that. ... (*Interruptions*)

As far as anomalies and some information of malpractices are concerned, yes, out of 4700 centres, there is an incident of anomaly only at one place in Patna and surrounding points. Due to proactive approach of Bihar Police, ... (*Interruptions*) The Central Bureau of Investigation is getting into the details. Some action has also been taken. We are hiding nothing. Everything is on record. There is only one incident, that is, in or around Patna and the Bihar Police and the CBI are proactively taking action on that. ... (*Interruptions*)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, it is unfortunate that the hon. Prime Minister is not here for this discussion where an issue of national importance is being discussed. ... (*Interruptions*) The hon. Prime Minister should be here. He could have waited for five minutes. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप प्रश्न पूछ रहे हैं?

... (व्यवधान)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, the problem of NEET is being faced in all the States, especially, in Tamil Nadu. From its

inception, we have been objecting to NEET. We have said that the decision to implement NEET should be given to the States. The States should be allowed to decide whether NEET should be practised in an individual State or not. We have asked a question to know whether there is any proposal to scrap NEET or not. That question is loaded with deaths of so many students starting from Anitha. ... (*Interruptions*) So many students have died because of NEET and they come out with a single line: "At present, there is no proposal to scrap NEET-UG." We, probably, should write it on the students' death bed that the Government is saying that they have no proposal to scrap this thing. I request that this Government should scrap NEET. They are talking so much about the Constitution. They are talking about *samvidhaan* and other things during the Emergency period. ... (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Speaker, Sir, let me inform this august House about the background of NEET. I would like to inform this august House when this singular all India examination pattern has been decided. I am putting the facts in front of this august House. In 2010, for the first time, this decision had been taken by the then Government. ... (*Interruptions*) Everybody knows who was in the Government in 2010 and who had supported this Government. ... (*Interruptions*) Subsequently, twice, this issue had been raised before the hon. Supreme Court. Both the times, the hon. Supreme Court had recommended for a single examination at the all-India level. Initially, this examination was conducted by CBSE. ... (*Interruptions*) Subsequently, this new agency, the National Testing Agency, has been assigned to conduct this examination. This is a continuous process from 2010 onwards. ... (*Interruptions*) Those who had decided to conduct this examination in those days, due to political reasons, they are raising fingers today. ... (*Interruptions*) There is a categorical answer from the Government that due to Supreme Court's guidance and instruction, a single all-India pattern examination is going on very successfully. ... (*Interruptions*) (1120/NKL/CS)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, Question No. 16.... (*Interruptions*) Sir, the basic issue before us is that the credibility of competitive examinations has already been lost. About 24 lakh students appeared for the

NEET-UG this time. Corruption had started right from the date of registration. This time, the registration date and also the time-limit for correcting and updating other information was also extended. Moreover, the leakage of paper has also happened in Patna. After all these things, now, the future of students is in big danger. They are very much apprehensive, and all of them are approaching us as people's representatives.

Sir, the point is that CBI investigation is going on. So far, only one FIR has been registered. The CBI investigation is going on and a committee has also been constituted to look into the matter. Since it is a matter which is concerning the people at large, I think, this is the right forum in which this matter has to be discussed.

My question is regarding the Centres of Excellence like AIIMS, JIPMER.... *(Interruptions)* I would like to ask whether a separate competitive test will be conducted. Moreover, in order to examine in detail, would a Joint Parliamentary Committee be constituted to investigate into this matter? That is the specific question I am asking.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Hon. Speaker Sir, as I said in my previous reply, there is a background why this pattern of NEET examination is conducted. With utmost respect to this House, I am again politely saying that due to different views, the hon. Supreme Court has categorically said twice that this centralised pattern of examination has to be there. ... *(Interruptions)* Regarding some anomalies, the Government has nothing to hide. We have put all the facts before the Supreme Court. Right now, the Supreme Court is hearing that case. ... *(Interruptions)* It would be proper to just wait and watch what instructions the hon. Supreme Court will give. This House is open to any kind of discussion. ... *(Interruptions)*

**श्री अखिलेश यादव (कन्नौज) :** महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे प्रश्न पूछने का समय दिया है।

महोदय, यह सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए, न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी।

महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब, कैसे, किस संस्था को बनाया गया है? पूरे देश के छात्र इस विषय पर आन्दोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जाँच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सेंटरवाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या आप उसकी सूची जारी करेंगे? जहाँ कुल 30 हजार सीटें हैं, कई सेंटर्स ऐसे हैं, जहाँ 2-2.5 हजार बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें मात्र 30 हजार हैं। कई सेंटर्स पर 2 हजार से ज्यादा बच्चे पास हो गए हैं। कई प्रदेशों में कुछ ऐसी जगहें हैं, जहाँ के कुछ सेंटर्स से बच्चों के सबसे ज्यादा, 650 से ज्यादा नंबर हैं। अगर वह संस्था इतनी क्रेडिबल थी, तो जिन सेंटर्स पर यह परीक्षा हुई, उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने इस बात की जानकारी प्राप्त की थी?

महोदय, मेरा आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि अगर ये मंत्री जी बने रहेंगे तो बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। धन्यवाद।

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान :** महोदय, आदरणीय अखिलेश जी के प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूँगा। यह केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो अभी-अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि विद्यार्थियों की पूरी सूची को वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाए। पिछले 3 दिन से देश भर के सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। यह सारी चीज खुले में है और कई प्रकार की चर्चा आ चुकी है। उसमें केरल के विद्यार्थियों ने भी अच्छा किया है। क्या हम यह कहेंगे कि वहाँ भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है। देश का ग्रामीण इलाका, देश के एस.सी., एस.टी.ज ने इस बार, ... (व्यवधान) इस बार सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश के एसटी, एससी, ग्रामीण बैकग्राउंड, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं। क्या हम उनकी मेधा को चुनौती देते हैं?

(1125/IND/VR)

महोदय, इसके अलावा क्वैश्चन पेपर लीक की जो बात है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा शुरू से स्टैंड रहा है और मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ लेकिन जब अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश का दायित्व लिया था, मेरे पास सूची है कि उस समय कितनी बार क्वैश्चन पेपर लीक हुए थे... (व्यवधान)  
**माननीय अध्यक्ष :** राहुल गांधी जी, क्या आप क्वैश्चन पूछना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

**SHRI RAHUL GANDHI (RAEBARELI):** Speaker, Sir, it is obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the Minister has blamed everybody except himself. I do not even think that he understands the fundamentals of what is going on here. ....(Interruptions)

**माननीय अध्यक्ष :** यह प्रश्न काल है। आप केवल प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

**SHRI RAHUL GANDHI (RAEBARELI):** The issue is that there are millions of students in this country, who are extremely concerned about what is going on, and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. ....(Interruptions) And, by the way, that



is the same feeling that the people in the Opposition have. That is why we are asking some very simple questions from the hon. Minister.

One, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? That is the first question.

**माननीय अध्यक्ष :** मंत्री जी, आप शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। मैं भी इस विषय पर एक बात कहूंगा।

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान :** अध्यक्ष जी, मेरी जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार हैं और मेरा जो सामाजिक जीवन है, मुझे मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार का सर्टिफिकेट मुझे किसी से नहीं चाहिए। देश के प्रजातंत्र ने, जनता ने मेरे नेता मोदी जी को प्रधान मंत्री की भूमिका दी है और मैं उनके निर्णय से यहां सदन में उत्तर दे रहा हूं... (व्यवधान) चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाता है... (व्यवधान) यह जो कहा गया कि देश की अभी की एग्जामिनेशन रबिबिश है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बयान देश के नेता प्रतिपक्ष का कुछ और नहीं हो सकता है। मैं कठोर शब्दों से इसकी निंदा करता हूं... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से देश के सामने एक तथ्य रखता हूं कि जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई हैं, वे वर्ष 2010 में शिक्षा सुधार के लिए तीन बिल लाए थे... (व्यवधान) इन्हीं की पार्टी के नेता श्री कपिल सिब्बल तीन बिल सदन में लाए थे। उनमें से एक बिल प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रेक्टिस बिल, 2010, जिसका उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मॉल प्रेक्टिस को बंद करना था... (व्यवधान)

महोदय, हमारी सरकार की हिम्मत है कि हम पब्लिक एग्जामिनेशन की इर्रैगुलेरिटीज में बिल लाए और कानून बनाया... (व्यवधान) कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी थी, नेता प्रतिपक्ष की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने बिल विदड्रा किया, किसके दवाब में बिल विदड्रा किया? क्या निजी मेडिकल विश्वविद्यालय के दवाब में, उनकी घूसखोरी के दवाब में उन्होंने उस बिल को विदड्रा किया था?... (व्यवधान) इनमें सच सुनने का साहस नहीं है। मैं किसी की विद्वता पर प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन वर्ष 2010 में शिक्षा सुधार का बिल इनकी सरकार लाई थी और दवाब में इस बिल को विदड्रा किया और आज यह हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं... (व्यवधान)

(इति)

**माननीय अध्यक्ष :** मैंने आपको मौका दिया है और सबको बोलने का मौका दूंगा। माननीय सदस्य आप एक मिनट बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

(1130/RV/SAN)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट रुकिए।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** कल्याण जी, कृपया बैठ जाइए। मैं सबको मौका दूंगा।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, विषय महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने सबको एलाउ किया। लेकिन, इस सदन के अन्दर एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए।

यह प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित था। आप सबको पता है कि देश में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें रहीं। उनमें आपके दल की सरकार भी रही, अन्य दलों की भी सरकारें रहीं। वहां भी कई बार प्रश्न-पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, आप मेरी पूरी बात सुनिए। कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** हमारा सवाल है कि यहां हम यह चिंता करने के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई सवाल न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का एक बेहतर सिस्टम कैसे डेवलप करें, इसके लिए सबके सुझाव आए। उनमें से जो उत्तम सुझाव होंगे, सरकार भी उसे मानेगी। लेकिन, अगर हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकारें हैं, जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती हैं। अगर हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो उन परीक्षाओं में जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं, उनके भविष्य पर, भारत की परीक्षाओं पर और पूरे विश्व में भारत की शिक्षण-व्यवस्था पर एक गम्भीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** इसके लिए सभी राज्यों ने अपने-अपने यहां कानून बनाए हैं, संसद ने भी कानून बनाए हैं। कानून बनाने के अलावा, इस विषय की जांच एजेंसी कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रही है। हमारा यह सवाल होना चाहिए कि कैसे हम सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को बेहतर कर सकें। सदन केवल आरोप-प्रत्यारोप से नहीं चलता है, आप एक बेहतर सिस्टम डेवलप कीजिए। सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। यह सदन उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न काल में मैंने सबको सवाल उठाने दिया। एक बार सवाल उठाने के बाद दोबारा सवाल उठाने नहीं दिया जाता है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** संसद नियम-प्रक्रियाओं से चलती है और मैंने नियम-प्रक्रियाओं से चलाया।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मैंने सदन की चिंता सरकार को बता दी है और आप सबको भी बता दी है।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: No.

Question No. 3 – Shri Daggumalla Prasada Rao.

... (Interruptions)

1133 hours

(At this stage, Shri Rahul Gandhi and some other hon. Members left the House.)

**(Q.3)**

SHRI DAGGUMALLA PRASADA RAO (CHITTOOR): Hon. Speaker, thank you so much for allowing me to speak on this important Question. I am Prasada Rao from Chittoor constituency of Andhra Pradesh.

Our beloved hon. CM, Chandrababu Naidu *garu* has requested for substantial financial support from the Centre to help reconstruct and rebuild Andhra Pradesh.

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, पहले आप प्रश्न संख्या - 3 बोलिए।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कई माननीय सदस्य पहली बार आए हैं।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, अब आप प्रश्न पूछिए।

SHRI DAGGUMALLA PRASADA RAO (CHITTOOR): Sir, thank you very much for allowing me to speak on this very important Question. I am Prasada Rao from Chittoor constituency of Andhra Pradesh.

Our beloved hon. CM, Chandrababu Naidu *garu* has requested for substantial financial support from the Centre to help reconstruct and rebuild the Andhra Pradesh which is facing acute financial challenges to continue the stalled infrastructure projects. In this context, hon. Speaker, I would like to know from the hon. Minister about the Centrally-Sponsored Schemes and the projects that have been stopped or discontinued in the State of Andhra Pradesh along with the reasons for the same. I would also like to know the current state of the stalled or delayed schemes in the State and the reasons behind the halting and slowdown of these projects. It has been stated in the reply given to the Question that Utilisation Certificate was not furnished. It is a general reply. I request the hon. Minister to furnish the details of the funds allotted to the Andhra Pradesh in the last five years for which utilisation certificate has not been furnished.

Thank you very much.

(1135/GG/SNT)

**श्री पंकज चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी आए थे, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस आशय का पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार को प्रस्तुत किया है। भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के सभी अनुरोधों का परीक्षण कराने के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई करती है। आंध्र प्रदेश के अनुरोध का भी इसी प्रकार से समुचित परीक्षण कर के निर्णय किया जाएगा। जहां तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं का सवाल है, इस संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न में पूछा है, मैं उनको बताना चाहता हूँ केंद्र प्रायोजित योजनाएं सभी राज्यों के लिए होती हैं और केंद्र सरकार की तरफ

से किसी योजना को राज्य विशेष के लिए बंद नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार का आग्रह मात्र यही होता है कि संबंधित योजनाओं को दिशानिर्देश के अनुपालन के तहत कार्यान्वित किया जाए।

**SHRI DAGGUMALLA PRASADA RAO (CHITTOOR):** Respected Sir, despite the release of Rs. 62,500 crore by the Central Government, there have been cases of corruption and diversion of funds by the previous State Government of Andhra Pradesh. As a result, the benefits of the Centrally-Sponsored Schemes implemented over the past five years have not reached the people of the State. This is highlighted in the White Paper released by our hon. Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu Garu, especially relating to Polavaram Irrigation Project and the development of our capital Amravati.

In light of this, I would like to ask this question to the hon. Minister. Have there been any reported issues of fund diversion or misallocation related to these funds in the State of Andhra Pradesh in the past five years? If such issues have been reported, the detailed information on these instances and the measures taken to address them may be furnished.

**श्री पंकज चौधरी :** माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी बताया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में कहीं न कहीं भारत सरकार का यह मत होता है कि जो दिशानिर्देश हैं, उनका पालन किया जाए। जहां तक पोलावरम और राजधानी के विषय में माननीय सदस्य ने जो बात कही है, आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2024 के माध्यम से, जो आंध्र प्रदेश की आर्थिक सहायता के लिए बना था, उसके लिए भारत सरकार की तरफ से अब तक रिसोर्स गैप के मद में 1678.76 करोड़ रुपये, रायलसीमा क्षेत्र, जो आंध्र प्रदेश का पिछड़ा हिस्सा है, उसके लिए 1750 करोड़ रुपये, राजधानी अमरावती के लिए 2500 करोड़ रुपये, पोलावरम नेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 15,147 करोड़ रुपये और विशेष सहायता उपाय के लिए 15.81 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अब तक लगभग 35,492 करोड़ रुपये भारत सरकार आंध्र प्रदेश सरकार को दे चुकी है।

**SHRI KESINENI SIVANATH (VIJAYAWADA):** Respected, Speaker Sir, despite the fact that Rs. 62,500 crore were given by the Central Government, these funds have been diverted and case of corruption has been noticed. It was clearly mentioned by our Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu in the White Paper released on Polavaram Irrigation Project and the capital Amravati. In light of this, I would like to ask the hon. Minister if any issues have been reported. If so, please give the detailed information on these instances, and the measures taken to address them. Thank you.

**श्री पंकज चौधरी :** माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी उत्तर में बताया है कि भारत सरकार ने राशि दी है। ऐसी कोई सूचना प्राप्त होगी तो अवश्य ही जाँच की जाएगी।

**SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR):** Hon. Speaker, Sir, it is very strange that in Chennai, and suburban Chennai, a very big project has been going on from 2019 onwards. The PAB has approved the project in 2019 but for the past five years, the

Central Government has not even spent or even invested a single penny in the CCS scheme. For the past five years, the work is going on. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu is working hard. He is getting the market funding with higher interest rate. (1140/AK/MY)

He is investing in it, and it is progressing by leaps and bounds on a day-to-day basis. Almost 60 per cent of the project has been completed. But so far, the Central Government has not come forward to invest even a single paisa. ... (*Interruptions*)  
Are we in the federal setup or not? This is what I want to know. ... (*Interruptions*)

**श्री पंकज चौधरी:** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न उठाया है, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। यह केंद्रीय प्रायोजित योजना आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रश्न था, बाकी अगर उनको जानकारी चाहिए और वह भेजेंगे तो जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी।

**SHRI C. M. RAMESH (ANAKAPALLE):** Is there any monitoring mechanism in the Ministry to oversee the funds disbursed to the State Government for the Centrally-Sponsored Schemes? Have they been utilized for the intended purpose? Have officials of the Ministry undertaken any field visits in this connection? If any field visit was done, then have they found any fault with it? What action is going to be taken on it?

**श्री पंकज चौधरी:** अध्यक्ष महोदय, जहां तक व्यवस्था का सवाल है, अभी जल्दी ही पीएफएमएस की पूरी प्रक्रिया क्रियाशील होने के बाद, राज्य सरकारों को दी जानी वाली धनराशि का अंतिम उपयोग इसमें प्रदर्शित होती है। इस रूप में पीएफएमएस द्वारा पारदर्शी तरीके से धनराशि का व्यय सुनिश्चित हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी जारी करने और उपयोग प्रमाण पत्र देने के बाद ही योजना पर धनराशि जारी की जाती है। (इति)

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न संख्या 4, श्रीमती कृति देवी देबबर्मन।

... (व्यवधान)

**SHRIMATI KRITI DEVI DEBBARMAN (TRIPURA EAST):** Hon. Speaker, I have three questions. ... (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, सबसे पहले आप प्रश्न संख्या बोल दें।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** कोई बात नहीं। आप हँसे नहीं। कुछ माननीय सदस्य नये हैं।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, हमारे कई माननीय सदस्य नये भी हैं। ऐसे तो पुराने माननीय सदस्य भी चूक कर जाते हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि प्रश्न काल में सबसे पहले प्रश्न संख्या बोली जाती है, जैसे प्रश्न संख्या 3, 4 बोली जाती है। फिर माननीय मंत्री जी सदन के पटल पर अपनी बात रखते हैं, उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है। एक माननीय सदस्य एक मूल प्रश्न और एक सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ सकते हैं।

माननीय सदस्य।

**(प्रश्न 4)**

SHRIMATI KRITI DEVI DEBBARMAN (TRIPURA EAST): What are the steps taken by the Government for reducing the number of pending litigations under the Companies Law?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, she is reading out the question from the Question List itself. ... (*Interruptions*)

SHRI HARSH MALHOTRA: Respected Speaker Sir, ... (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष:** दादा, आप इतने सीनियर हैं, लेकिन रोज इस सदन की कार्यवाही को बाधित करते हो न?

... (व्यवधान)

SHRI HARSH MALHOTRA: Respected Speaker Sir, the Ministry of Corporate Affairs has taken several steps to review pending prosecutions in various courts. In 2017 and later in 2022, a Committee of Senior Officers of MCA was set up to give recommendations regarding withdrawal of prosecutions. The objective was to free judicial courts from dealing with offences that are of procedural and technical nature. ... (*Interruptions*) So, the answer of the question is this. ... (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय मंत्री जी, कभी भी इस तरह से किसी सदस्य का जवाब नहीं देते हैं। आप सीधे जवाब दीजिए।

... (व्यवधान)

SHRI HARSH MALHOTRA: Sir, the answer is already laid on the Table. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI KRITI DEVI DEBBARMAN (TRIPURA EAST): What is the data regarding the number of cases withdrawn or reduced as part of the efforts of the Government to reduce the litigation burden? I would like to ask this question.

SHRI HARSH MALHOTRA: In 2017, 14,247 prosecutions were withdrawn in Special Drive-I. A written statement has already been given. ... (*Interruptions*) (1145/UB/NK)

There is a decision taken by the Ministry to withdraw 7,338 compoundable offences which have been identified, and among them, 6,294 applications for withdrawal have been filed before the various courts.

**श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मंत्री जी ने इस प्रश्न का जवाब बहुत विस्तार से दिया है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि

कंपनी एक्ट के अंदर वर्षों से जो लिटिगेशन्स पड़े हुए हैं, उनकी पेन्डेंसी को रिड्यूस करने के लिए 2017 में एक कमेटी बनायी और 2022 में भी एक कमेटी बनायी गई।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की जो कमेटी बनी और 2022 में जो कमेटी बनी, उसकी सिफारिश क्या थी और किन-किन सिफारिशों को उन्होंने लागू किया? इस पर सरकार स्वयं चिंतित है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस से हमारा एफडीआई बढ़ा है, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, केवल सवाल का जवाब चाहता हूँ। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सेबी ने इस संबंध में जो कदम उठाये हैं, like strengthening corporate governance framework for the listed entities in the last one year through measures like introduction of Business Responsibility and Sustainability Report for rationalising disclosure of material events or information by listed entities empowering shareholders as listed entity. सेबी के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, सरकार ने काफी कदम उठाये हैं। केसेज के रिडक्शन और केसेज के पेन्डेन्सी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, please allow me to answer this question. Hon. MoS, Harsh ji, is trying to come up with answers. Maybe, he will take a while to be able to articulate it orally to give a comprehensive answer. However, I just want to add something which is important from the point of view of the lady Member who asked this question first, and also Shri Jagdambika Pal.

The Ministry of Corporate Affairs has taken a lot of steps towards reducing pending cases and, as was mentioned earlier, there was a Special Drive phase-I and a Special Drive phase-II. Special Drive phase-I and phase-II were implemented in 2017 and in 2023 respectively. Till 15<sup>th</sup> July, 2024, 6,294 applications for withdrawal had been filed before the various courts. Now, specifically, on ease of doing business, a lot of steps have been taken. Nearly eleven steps have been mentioned in the written reply, which are being specifically mentioned in the reply. ... (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, प्रश्न काल में बैठे-बैठे नहीं बोला जाता है, टिप्पणी नहीं की जाती है।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: But most importantly, 63 major offences have been decriminalised, as a result of which, the companies today are able to carry on their functions without the worry of compliance. There was a

Central Processing Centre which has been set up so that specified non-STP e-forms related questions can also be taken up. The most important part of this is that 'zero fee' for incorporation has been brought in for companies with authorised capital of up to Rs. 15 lakh which means, for small companies, which have small capital with which they start their business, there is no fee charged. These steps are also taken for ease of doing business other than simultaneously acting on reducing the pendency in the courts. Therefore, this question which relates to ease of doing business and reduction of pendency also has both sides on which the hon. Minister of State is trying to answer.

(1150/SRG/SK)

Sir, with regard to the most important question which Shri Jagdambika Pal raised about the SEBI, I want to underline the fact that the reforms, which have been brought by the SEBI, particularly within the timelines which have been given for settlement of claims are remarkable steps taken forward, and the markets and the companies have also benefited from it. In fact, we are far ahead of the very many other countries where similar company law operates. They are still not able to settle claims within even T+6, T+5 or even T+4 days. We have even come to T+1 which is effectively being run today. So, let me assure the hon. Member that SEBI related reforms are coming up with Ease of Doing Business, and treating all the stakeholders with great comfort.

This question pertains to a large area of reforms in company matters, both related to pendency reduction and Ease of Doing Business. So, the question that was getting answered by our new MoS actually had a larger context on which the written answer is far more comprehensive than what the hon. Minister has tried to start answering with, but the new Ministers will take a bit of while, but we should listen to them, and I would request all of us to kindly accommodate their attempt to answer.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, the hon. Minister has given us a kind of laundry list of initiatives, but she has overlooked a very crucial issue which is that 67 per cent of the pending litigation cases relating to insolvency have exceeded the 270-day time frame, precisely because there has been no attention paid to the staffing levels of the NCLAT. For example, in all the five Southern States and two UTs, we have one NCLAT in Chennai.



According to media reports, there the Bench has one Stenographer who doubles up as PA to the Technical Member, and the Registrar sits in Delhi. This is a preposterous situation. So, I would like to ask this question to the hon. Minister. What is the Ministry doing about giving some attention to the staffing crisis in the NCLATs, and in particular, for the Southern States? Would she be able to consider a separate NCLAT for a State like Kerala where our cases are pending for so long?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: It sounds very interesting to say that I have given a laundry list, but we have done so many reforms. So, we need to list it all. And I appeal to the hon. Member to read it so that he can differentiate between a typical laundry list and the list of actions taken for reforming the process. Hon. Member, Shri Shashi Tharoor should actually differentiate between a typical laundry list and the list of reforms undertaken by us.

So, with that said, I quite agree with the hon. Member. Staffing and filling up the vacancies of NCLT and NCLAT is a challenge which we are trying to meet. We are certainly conducting periodical interviews and also advertising positions and working with the Supreme Court, so that we get the right members to appoint them in the various company law Tribunals. Yes, it is a truth that there is only one NCLAT and that is located in Tamil Nadu. I am sure that the Southern States would find that it is not located in the North, but it is in Chennai and therefore, for now at least, the NCLAT in Chennai would serve the purpose. However, I do appreciate that we need to have greater number of Appellate Tribunals but this is not something which I can just do ... (*Interruptions*). Sir, my mic is off. So, it is not only the Opposition Members' mics which are getting off, even mine is off, if that satisfies you! ... (*Interruptions*) Sir, but my answer is not complete. Both NCLT and NCLAT appointments are being taken up seriously by all of us. We are trying to fill it up speedily. Let me assure the hon. Member that filling up these positions is happening with greater sense of urgency.

(ends)

(1155/RCP/MK)

**(Q. 5)**

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Speaker Sir, promoting libraries is crucial for fostering a culture of lifelong learning. The National Mission on Libraries was formulated by the Central Government in 2014. The main intention of this particular scheme was to enhance the accessibility to knowledge and resources across India. Since 2014, the year in which this scheme was grounded, till today, we would like to know as to what kind of initiatives have been taken by the Ministry of Culture, Government of India, to raise awareness among the people regarding the benefits of the scheme. What is the nature of the community engagement and the community outreach? I would request the hon. Minister of Culture to enlighten us.

**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया है, वह निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण है और समाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है तथा व्यक्ति के जीवन में जुड़ी हुई शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालता है। लेकिन, हम सब जानते हैं कि लाइब्रेरी एज- पर सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कांस्टिट्यूशन स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट का सब्जेक्ट होने के नाते प्राइमरी रेस्पॉसिबिलिटी, लोगों को इसके साथ जोड़ना, लोगों का लाइब्रेरी के साथ जुड़ाव हो, लोगों में अध्ययन करने की अध्ययनशीलता बढ़े, यह जन-जागरण करने की रेस्पॉसिबिलिटी राज्य सरकारों के साथ है। भारत सरकार नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी के माध्यम से राज्यों को उनके एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने के लिए धनराशि और संसाधन मुहैया कराती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या और सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि लाइब्रेरीज के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ-साथ राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के माध्यम से विभिन्न लाइब्रेरीज को स्टेट्स में ग्रांट सप्लीमेंट करके, राज्यों के द्वारा किए गए निवेश के अनुरूप ग्रांट सप्लीमेंट करके, वे अपने यहां पर लाइब्रेरी एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकें, रीडिंग मेटेरियल को बढ़ा सकें, उसके लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ-साथ

नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी सेटअप करके हमने लाइब्रेरी में लाखों की संख्या में पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं, ताकि आज की इस तकनीकी युग में अधिकतम लोग उसका लाभ उठा सकें।

मैं आग्रह करूंगा, माननीय सदस्यगण जितने भी यहां उपस्थित हैं, वे सब अपने क्षेत्र में जिस तरह से लाइब्रेरीज को, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज को भारत सरकार के एफर्ट से स्टेट्स ने स्ट्रेंथेन किया है, कुछ जगह पर ग्रामीण लाइब्रेरीज को भी हमने स्ट्रेंथेन किया है और स्टेट लेवल लाइब्रेरीज को भी स्ट्रेंथेन किया है, यदि उसके बारे में अपने क्षेत्र में अधिकतम जागरूकता बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे तो निश्चित ही उसके माध्यम से हम लाइब्रेरीज को लोगों तक पहुंचाने में और अधिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

**SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR):** Speaker Sir, Odisha is known for its rich cultural heritage with diverse traditional systems of knowledge. I would request the hon. Minister of Culture to tell us as to how the National Mission on Libraries is helping the preservation and dissemination of traditional systems of knowledge. Thank you.

**माननीय अध्यक्ष :** एक नये मेम्बर का प्रश्न आ रहा है, इसलिए मैं उनसे पूछवा लेता हूं, उसके बाद आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा।

डॉ. राजीव भारद्वाज जी ।

**डॉ. राजीव भारद्वाज (कांगड़ा) :** अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी आदरणीय मंत्री जी का वक्तव्य सुना। क्वेश्चन नम्बर-5.

**माननीय अध्यक्ष :** आपको प्रश्न संख्या नहीं बोलना है। आपको प्रश्न पूछना है। आप केवल प्रश्न पूछिए। जो नये मेम्बर होते हैं, उनका प्रश्न होता है।

**डॉ. राजीव भारद्वाज (कांगड़ा) :** मुझे अपने लोक सभा क्षेत्र के संदर्भ में माननीय संस्कृति मंत्री जी से जानना है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में, जो दो जिलों में विभक्त है, जिला कांगड़ा और चम्बा, में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के अंतर्गत कितनी लाइब्रेरीज हैं और उनके संदर्भ में कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई गई है?

**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि हिमाचल प्रदेश के लोक सभा क्षेत्र में, स्पेसिफिक लोक सभा क्षेत्र में कितनी लाइब्रेरीज हैं और उन पर कितनी धनराशि मुहैया कराई गई है? नेशनल मिशन ऑफ

(pp. 20-30)

लाइब्रेरी एक राज्य में एक लाइब्रेरी और एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को मॉडल लाइब्रेरी बनाने के लिए फंड देती है। उसके अतिरिक्त छोटी लाइब्रेरीज ग्रामीण स्तर पर भी बनती हैं।

(1200/SJN/PS)

महोदय, मैं खुशी के साथ यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही छोटा प्रदेश है। रूरल लाइब्रेरीज के अपग्रेडेशन के लिए भारत सरकार ने लगभग 800 से भी ज्यादा लाइब्रेरीज को धनराशि मुहैया कराई है।

माननीय सदस्य ने अपने जिले और अपने लोक सभा क्षेत्र की कुछ स्पेसिफिक जानकारी मांगी है। यदि माननीय सदस्य मेरे कार्यालय से संपर्क करेंगे, तो उनको निश्चित रूप से वह स्पेसिफिक जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी।

(इति)

**माननीय अध्यक्ष :** आप ही उनको वह जानकारी दे देना।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** दादा, अगर आप न हों, तो सदन में अच्छा न लगे।

**प्रश्न काल समाप्त**

### स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1201 बजे

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** सबको सीखते रहना चाहिए। आप भी बताएं, तो मैं सीखता रहूंगा। प्रशिक्षण, सीखना एक नियमित प्रक्रिया है।

... (व्यवधान)

**आर्थिक समीक्षा की प्रतियां मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने के बारे में घोषणा**

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग-दो के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री जी द्वारा आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् उसकी प्रतियां मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएंगी।

-----

### सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

**माननीय अध्यक्ष :** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर - 3, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी।

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

1. Economic Survey 2023-24.
2. Economic Survey 2023-24 - Statistical Appendix.

-----

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, kindly provide hard copy of the Economic Survey. It is very difficult to read. ... (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, हम पर्यावरण के प्रति चिंतित हैं, इसलिए कागज बचाना हम सबका कर्तव्य है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप मेरे चैंबर में आकर सुझाव दे देना।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आइटम नंबर - 4, श्री जयंत चौधरी जी।

**कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) :** अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
  - (दो) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
  - (तीन) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

-----

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, मैं एक और विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। कई नए माननीय सदस्य आए हैं, ताकि उनको जानकारी हो जाए। जब सभा पटल पर पत्र रखे जा रहे हों, तब बीच में टिप्पणी नहीं करते हैं। अगर आपको कोई सुझाव देना है, तो दे दें। अगर आपका सुझाव उचित होगा, तो माना जाएगा।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप सीनियर मेंबर हैं, आपका सुझाव मेरे ध्यान में है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आइटम नंबर - 5, श्री पंकज चौधरी जी।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) :** अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (एक) सा.का.नि.902(अ) जो दिनांक 20 दिसंबर, 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तमिलनाडु के कुछ जिलों में पंजीकृत व्यक्तियों के लिए नवंबर, 2023 के माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3ख में रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सा.का.नि.5483(अ) जो 28 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168क के अधीन दी गई शक्तियों के प्रयोग में निर्दिष्ट अनुपालन की तारीख बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि.30(अ) जो दिनांक 05 जनवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तमिलनाडु के कुछ जिलों में पंजीकृत व्यक्तियों के लिए नवंबर, 2023 के माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3ख में रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2024 जो 05 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.31(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) का.आ.84(अ) जो 05 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2023 की अधिसूचना सं. का.आ. 3424(अ) को निरसित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) का.आ.85(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उसमें उल्लिखित कतिपय वस्तुओं के निर्माण में लगे किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि.77(अ) जो दिनांक 30 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 609(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) का.आ.818(अ) जो दिनांक 22 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 158A की उप-धारा (2) के अधीन "आसान ऋण हेतु सार्वजनिक तकनीकी मंच" को एक प्रणाली के रूप में अधिसूचित करना है जिसके द्वारा सहमति के आधार पर सामान्य पोर्टल द्वारा जानकारी साझा की जा सकती है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) का.आ.1642(अ) जो दिनांक 8 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय विनिर्दिष्ट कर अवधि के लिए विनिर्दिष्ट पंजीकृत व्यक्तियों के लिए ब्याज माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) का.आ.1663(अ) जो दिनांक 10 अप्रैल, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय दिनांक 5 जनवरी, 2024 की

अधिसूचना संख्या का.आ.85(अ) के कार्यान्वयन की समयसीमा को 1 अप्रैल, 2024 से बढ़ाकर 15 मई, 2024 करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (ग्यारह) सा.का.नि.246(अ) जो दिनांक 12 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च 2024 के माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने की नियत तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सा.का.नि.296(अ) जो दिनांक 29 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19.06.2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.609(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सा.का.नि. 297(अ) जो दिनांक 30 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19.06.2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.609(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (2) शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों पर संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्रवाई पर 42वें प्रगति प्रतिवेदन,– जुलाई 2024 की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि.183(अ) जो दिनांक 12 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क में संशोधन करना है ताकि चिकित्सा, शल्य दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली एक्स-रे मशीनों के विनिर्दिष्ट भागों पर लागू बीसीडी दर को बदला जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि.53(अ) जो दिनांक 22 जनवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क में संशोधन करके प्रयोग किए गए उत्प्रेरक और कीमती धातु युक्त राख पर बीसीडी को बढ़ाकर 10% करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि.54(अ) जो दिनांक 22 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 02.02.2018 की अधिसूचना



संख्या 11/2018-सीमा शुल्क में संशोधन करके समाज कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस) से कतिपय प्रविष्टियों में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चार) सा.का.नि.55(अ) जो दिनांक 22 जनवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 01.02.2021 की अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क में संशोधन करके उसमें उल्लिखित टैरिफ शीर्षों के अधीन आने वाली प्रविष्टियों पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पाँच) सा.का.नि.72(अ) जो दिनांक 29 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 मार्च, 2024 को व्यपगत होने वाली छूटों की वैधता को 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ाने के लिए 50/2017-सीमा शुल्क में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि.73(अ) जो दिनांक 29 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 मार्च, 2024 को व्यपगत होने वाली छूटों की वैधता को 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ाने के लिए विभिन्न अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि.78(अ) जो दिनांक 30 जनवरी, 2024 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि.79(अ) जो दिनांक 30 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेलुलर मोबाइल फोन के विनिर्दिष्ट पुर्जो/उप-पुर्जो पर लागू बीसीडी दर को बदलने के लिए दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा.का.नि.115(अ) जो दिनांक 19 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 का संशोधन करना है ताकि विनिर्दिष्ट फ्रोजन टर्की मांस, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, उनके प्रसंस्कृत उत्पादों और एक्सट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास के आयात पर मूल सीमा शुल्क को कम किया जा सके/छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा.का.नि.116(अ) जो दिनांक 19 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 11/2021-सीयूएस दिनांक 01.02.2021 में संशोधन करना है ताकि टैरिफ मद 5201 00 25 के

तहत आने वाले वस्तुओं पर एआईडीसी की छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

- (ग्यारह) सा.का.नि.121(अ) जो दिनांक 21 फरवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 55/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 31.10.2022 और अधिसूचना संख्या 64/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 07.12.2023 में संशोधन करना है ताकि पारसेला चावल पर निर्यात शुल्क की अंतिम तिथि को हटाने और पीले मटर के आयात पर विनिर्दिष्ट शर्त निर्धारित करने के लिए कि उक्त आयात को 30.04.2024 को या उससे पहले जारी किए गए बिल ऑफ लैंडिंग के विरुद्ध अनुमति दी जाएगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (बारह) सा.का.नि.158(अ) जो दिनांक 6 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 में संशोधन करना है ताकि 07.03.2024 से निर्धारित शर्तों के अध्यक्षीन, मांस और खाद्य ऑफल, बतख, फ्रोजन के आयात पर मूल सीमा शुल्क को 30% से घटाकर 5% किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (तेरह) सा.का.नि.180(अ) जो दिनांक 12 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सोने के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) के भुगतान से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (चौदह) सा.का.नि.192(अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 में संशोधन करना है ताकि कतिपय स्मार्ट पहनने योग्य उपकरणों पर बीसीडी दरों को संशोधित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (पन्द्रह) सा.का.नि.196(अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 25/2021-सीमा शुल्क दिनांक 31.03.2021 में संशोधन करना है ताकि भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के अनुसार विनिर्दिष्ट वस्तुओं के मॉरीशस से आयात किए जाने पर प्रशुल्क रियायतों को बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (सोलह) सा.का.नि.206(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 'भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना' के अनुसार इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की पूरी तरह से निर्मित इकाइयों के आयात पर रियायती बीसीडी को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

- (सत्रह) सा.का.नि.207(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 'भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना' के तहत आयातित इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की पूरी तरह से निर्मित इकाइयों पर समाज कल्याण अधिभार (एसडबल्यूएस) से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) सा.का.नि.213(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 22/2022-सीमा शुल्क दिनांक 30.04.2022 में संशोधन करना है ताकि भारत-यूई व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के अनुसार यूई से विनिर्दिष्ट वस्तुओं के आयात किए जाने पर प्रशुल्क रियायतों को बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) सा.का.नि.236(अ) जो दिनांक 2 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन, 1000 मीट्रिक टन से अनधिक काला नमक चावल के निर्यात पर लागू लगने वाले शुल्क पर पूरी छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) सा.का.नि.244(अ) जो दिनांक 5 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 64/2023-सीमा शुल्क, 07.12.2023 में संशोधन करना है ताकि 30.06.2024 को या उससे पहले जारी किए गए बिल ऑफ लैंडिंग के साथ पीली मटर की शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) सा.का.नि.269(अ) जो दिनांक 3 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिसूचनाओं में संशोधन करना है ताकि 04.05.2024 से 31.03.2025 तक देसी चना (एचएस 0713 20 20) के आयात पर लागू आयात शुल्क की छूट दी जा सके; प्याज (एचएस 0703 10) के निर्यात पर 40% का प्रभावी निर्यात शुल्क लगाया जा सके; 31.10.2024 को या उससे पहले जारी किए गए लदान के बिल में पीले मटर (एचएस 0713 10 10) के आयात के लिए विनिर्दिष्ट शर्त या छूट का विस्तार किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बाईस) सा.का.नि.270(अ) जो दिनांक 6 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 के क्रम संख्या 359क की सूची 34क और सूची 34ख में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेईस) सा.का.नि.352(अ) जो दिनांक 27 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रक्षा मंत्रालय या रक्षा बलों या रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) या अन्य पीएसयू या रक्षा बलों के लिए किसी अन्य इकाई द्वारा विनिर्दिष्ट रक्षा उपकरणों और पुर्जों के आयात पर 05 साल की अवधि के

लिए अर्थात् 30 जून, 2024 तक सीमा शुल्क और एकीकृत कर पूर्ण छूट का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (4) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182(अ) जो दिनांक 12 मार्च, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 90 में विशिष्ट टैरिफ मदों में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (5) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 143 (अ) जो दिनांक 28 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 14/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 25.03.2019 में संशोधन करना है ताकि डीजीटीआर की सिफारिश के अनुसरण में निर्माता का नाम 'मेसर्स मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड' से मैसर्स आईएनईओएस फेनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 197 (अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर की अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्ष के लिए चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग से आयातित मुद्रित सर्किट बोर्डों (पीसीबी) पर एडीडी अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 198 (अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित "पैरा-तृतीयक ब्यूटाइल फिनोल (पीटीबीपी)" पर 5 वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 199 (अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से आयातित "एथिलीन विनाइल एसिटेट (ईवा) शीट फॉर सोलर मॉड्यूल" पर 5 वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पाँच) सा.का.नि. 200 (अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से आयातित "स्वयं चिपकने वाला विनाइल (एसएवी)" पर 3 वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (छह) सा.का.नि. 209(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 17/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 9 अप्रैल, 2019 के तहत अधिरोपित चीन जनवादी गणराज्य में उत्पन्न या निर्यात किए गए "कास्ट एल्युमिनियम मिश्र धातु सड़क पहियों" के आयात पर और पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क (एडीडी) का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि.278(अ) जो दिनांक 16 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य, सऊदी अरब और ताइवान से आयातित "पेंट्राएरिथ्रिटोल" पर 5 वर्षों के लिए प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि.323(अ) जो दिनांक 13 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पॉली विनाइल क्लोराइड रेजिन पेस्ट के आयात पर छह महीने की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा.का.नि. 348(अ) जो दिनांक 27 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपियन संघ, जापान, और कोरिया गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम साइनाइड" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा.का.नि. 349(अ) जो दिनांक 27 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "पूरी तरह से संयोजित स्थिति में मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण और हाइड्रोलिक रॉक बीकर(एचआरबीसी)" पर 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सा.का.नि.350(अ) जो दिनांक 27 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित टिन प्लेट जिसका आयाम 401 व्यास (99एमएम) और 300 व्यास (73एमएम) हो, के आसानी से खुलने वाले सिरों" पर 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (बारह) सा.का.नि.351(अ) जो दिनांक 27 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित, "टेलीस्कोपिक चैनल डॉअर स्लाइडर" के आयात पर छह माह की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (तेरह) सा.का.नि.171(अ) जो दिनांक 11 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय(डीजीटीआर) के अनुरोध पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित " बसों और लॉरियों/ट्रकों में उपयोग किए जाने वाले नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर जिनमें ट्यूब और/या रबर का फ्लैप हो (ट्यूबलेस टायर सहित), जिनका सांकेतिक रिम व्यास 16" से अधिक हो" के आयात पर दिनांक 24 जून, 2019 की अधिसूचना संख्या 01/2019/सीमाशुल्क(सीवीडी) द्वारा अधिरोपित प्रतिकारी शुल्क को 23 जुलाई 2024 तक की अवधि के लिए बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (चौदह) सा.का.नि.294(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से आयातित 'सभी रूपों में साकारीन' पर प्रतिकारी शुल्क के उद्ग्रहण को 28 फरवरी, 2025 तक बढ़ाने के लिए 30 अगस्त, 2019 की अधिसूचना संख्या 2/2019-सीमा शुल्क (सीवीडी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि.71(अ) जो दिनांक 25 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय अमिश्रित डीजल हेतु अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की प्रयोज्यता का विस्तार करने के लिए दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017-के.उ.शु. में और संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (दो) सा.का.नि. 111(अ) जो दिनांक 15 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (तीन) सा.का.नि. 112(अ) जो दिनांक 15 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-के.उ.शु. में और संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

- (चार) सा.का.नि. 148(अ) जो दिनांक 29 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (पांच) सा.का.नि. 149(अ) जो दिनांक 29 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-के.उ.शु. में और संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (छह) सा.का.नि. 204(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (सात) सा.का.नि. 241(अ) जो दिनांक 3 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (आठ) सा.का.नि. 247(अ) जो दिनांक 15 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (नौ) सा.का.नि. 267(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (दस) सा.का.नि. 273(अ) जो दिनांक 15 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-18/2022-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

- (ग्यारह) सा.का.नि.300 (अ) जो दिनांक 31 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सा.का.नि. 328(अ) जो दिनांक 14 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(क) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि.65(अ) जो दिनांक 24 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 01.02.2022 से 27.04.2023 तक की अवधि के लिए पहनने योग्य वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क नहीं लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि.66(अ) जो दिनांक 24 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 01.02.2022 से 27.04.2023 तक की अवधि के लिए श्रवण योग्य वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क नहीं लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 158 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) समुद्री कार्गो मैनीफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (पहला संशोधन) विनियम, 2024 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 28 मार्च, 2024 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 235(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) समुद्री कार्गो मैनीफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 30 जून, 2024 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (9) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.834(अ) जो दिनांक 23 फरवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मेसर्स एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (आकासा एयर) जिसका पंजीकृत कार्यालय 12वां तल, उर्मि एस्टेट, 95 गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल



(पश्चिम), मुम्बई, महाराष्ट्र-400013 में है, को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (5) के प्रयोजनार्थ "नामित भारतीय वाहक" के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

-----

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972:-
- (i) The Living Animal Species (Reporting and Registration) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.145(E) in Gazette of India dated 29<sup>th</sup> February, 2024.
  - (ii) The Captive Elephant (Transfer or Transport) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.191(E) in Gazette of India dated 14<sup>th</sup> March, 2024.
  - (iii) The Wild Life (Protection) Licencing (Additional Matters for Consideration) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.46(E) in Gazette of India dated 18<sup>th</sup> January, 2024.
  - (iv) The Wild Life (Transactions and Taxidermy) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.47(E) in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> January, 2024.
  - (v) The Scheduled Specimen (Conditions and Procedure for exemption), Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.130(E) in Gazette of India dated 23<sup>rd</sup> February, 2024.
- (2) A copy of the Notification No. S.O.943(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 29<sup>th</sup> February, 2024, authorizing the Chief Wild Life Wardens of all States and Union territories, in their respective jurisdictions, to perform the functions of the Management Authority issued under Section 49M of the Wild Life (Protection) Act, 1972 Act and the rules made thereunder.

- (3) A copy of the Notification No. S.O.944(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 29<sup>th</sup> February, 2024, authorizing the Officers of the Wild Life Crime Control Bureau, not below the rank of Head Constable in relation to the specimens of species listed in Schedule IV to the said Act, to exercise the powers and perform functions under Section 50 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 issued under Section 50 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 Act.

-----

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुकान्त मजूमदार) :** अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) तीसरा संशोधन विनियम, 2024, जो दिनांक 3 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. 1-5/2024 (डीईबी-1) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रिंट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रिंट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रिंट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रिंट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रिंट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रिंट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (16) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।  
(तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
(दो) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।  
(तीन) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

-----

**ELECTION TO COMMITTEE**  
**Central Building and Other Construction Workers'**  
**Advisory Committee**

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT; AND MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (DR. MANSUKH MANDAVIYA):

Hon. Speaker, Sir, I beg to move the following:

“That in pursuance of section 3(2)(b) of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 read with Rule 11(2) of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Services) Central Rules, 1998, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves, to serve as members of the Central Building and Other Construction Workers' Advisory Committee, subject to the other provisions of the said Act and the Rules made thereunder.”

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

“कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 11(2) के साथ पठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 3(2)(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यक्षीन केन्द्रीय भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

-----

(1205/SMN/SPS)

**\*MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, even though this matter was raised today in the Question Hour, I would like to draw the attention of the House to the most important matter that is regarding NEET which has happened recently. It is not just about NEET but for all competitive examinations which the country is carefully looking upon.

Sir, the motto of the Government of India and the Education Department in the New Education Policy, 2020 is to educate, encourage and enlighten.

Sir, in the recent years, India has witnessed a troubling rise in competitive exam paper leaks undermining the integrity and credibility of the education and the recruitment system.

Sir, as per the Government data, a total of 70 examination papers have been leaked in the last seven years across 15 States raising a doubt on the integrity of these competitive exams in the country.

States like Tamil Nadu and many regional parties have raised concern about the integrity of these examinations and they want these competitive exams to be cancelled. सर, अभी शुरू ही किया है और बैलेट में मिला है, कंटीन्यू करने दीजिए। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** बैलेट में मिला है, इससे मतलब थोड़े ही है।

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, 24,06,079 candidates wrote the NEET examination. The NTA on 4<sup>th</sup> June, 2024 faced widespread allegations of irregularities and paper leaks. Notably, 67 top ranking candidates scored 99.99 percentile including six from a single examination centre in Haryana. Who owns these centres in Haryana?

In Gujarat, the National Testing Agency had selected a school in Godhra as an examination centre despite the fact that the Gujarat High Court has imposed a fine of Rs. 35 lakh on the organisation that runs these schools. So, what credibility does these examinations have?

The Gujarat schools and Haryana schools are under scrutiny. This is one of the biggest scams the country has seen. The country has to constitute a high-level fact-finding Committee about these allegations.

---

\* Please see pp. 320 for List of Members who have associated

**माननीय अध्यक्ष :** आप सुनिए, इसमें सर्वोच्च न्यायालय जांच कर रहा है, सीबीआई जांच कर रही है, केन्द्र सरकार बिल लेकर आ गई है, सारे विषयों पर सब चीजें हो चुकी हैं। हमारा सिस्टम सबसे बेहतर है। दुनिया के अंदर भारत का एजुकेशन सिस्टम और हमारी परीक्षा प्रणाली सबसे बेहतर है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

**DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (PONNANI):** Sir, through you and through this august House, I would like to draw the attention of the Government to the alarming issue of increase in sea turbulence causing serious coastal erosion along the Arabian sea coast in Kerala.

It is a very serious phenomenon which deserves urgent attention and very powerful and effective measures of solutions. This serious phenomenon has resulted in the loss of several metres of shoreline in places like Palappetti, Ajmer Nagar, Veliyamkode etc.

Protection measures are urgently needed in various other places including Thannithura, Pathumuri and Padinjarekkara near Koottayi, Meenangadi, Kothavarapu, Kashmir Beach, Vaadikkal, Pallivalappu, Vaakkad, Edakkadappuram, Puthiyakadappuram, Anchudi, Cheeraan Kadappuram, Chaappapadi, Alungal Beach, Saddam Beach and many other areas belonging to my Constituency Ponnani.

(1210/SM/MM)

This threatens the livelihoods of fishermen as fishing and other local businesses have been adversely affected along with infrastructure such as roads, bridges, public utilities etc.

1210 hours (Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

Madam, this problem affects Kerala's entire Arabian sea coast. I urge upon the Government to do the needful to conduct an authentic and scientific study, involving experts in oceanography, environmental science and coastal engineering to identify the root causes of this increased sea turbulence and coastal erosion.

Immediate steps need to be taken to implement the safety measures such as construction of permanent protection like breakwater tetrapod system etc. Furthermore, special funds and package have to be formulated and declared by the Government for assisting the poor fishermen with compensation for damaged houses and loss of livelihood.

Madam, it is a very serious problem. Year by year, land is being taken by the sea and nothing is being done to prevent this situation and protect the fishermen. The poor fishermen are suffering. This year, during the monsoon season, especially in Kerala, sea erosion took place at various places and sea turbulence created a catastrophe. Its consequences are very serious.

So, I urge upon the Government, through you, Madam, to take urgent steps to undo the situation and solve the problem being faced by the fishermen. Thank you.

**श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) :** माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र के रेवती और बनकटा रेलवे स्टेशनों की समस्याओं की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

अध्यक्ष जी लोकसभा क्षेत्र बलिया-छपरा रेलखंड के मध्य स्थित रेवती रेलवे स्टेशन को वर्ष 2023 से हाल्ट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है, जिसके बाद यह स्टेशन सुविधा विहीन हो गया है। छपरा-बलिया के बीच सुरेमनपुर व सहतवार रेलवे स्टेशन के बाद यह तीसरा सर्वाधिक आय देने वाला स्टेशन था। यहां छपरा-दुर्ग, सारनाथ एक्सप्रेस, बलिया - सियालदह एक्सप्रेस, छपरा-लखनऊ, उत्सर्ग एक्सप्रेस, छपरा - वाराणसी इंटरसिटी के अलावा चार-चार एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होने के बावजूद भी यहां अप-साइड का प्लेटफार्म नंबर एक समाप्त किए जाने से वृद्ध, विकलांग और महिलाओं को ट्रेन में चढ़ने-उतरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कंप्यूटर के टिकट की जगह ठेका पर टिकट देने का काम दे दिया गया है। ट्रेनों का संचालन रेवती रेलवे स्टेशन की जगह सुरेमनपुर-सहतवार से किया जाता है।

सभापति जी, इसी प्रकार छपरा रेलखंड के बीच स्थित बनकटा रेलवे स्टेशन को भी हाल्ट स्टेशन बनाया जा रहा है, जिस कारण यहां भी यात्री सुविधाओं की घोर कमी है। वर्तमान में इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या दो को तो ऊंचा कर दिया गया, जबकि प्लेटफार्म संख्या एक अब भी काफी नीचे है। साथ ही, पेयजल, शौचालय, यात्री विश्रामालय, कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र भी खोला जाना चाहिए। बनकटा में गाड़ी संख्या 15027 मौर्य एक्सप्रेस और 15203 बरौनी- लखनऊ एक्सप्रेस का ठहराव बनकटा रेलवे स्टेशन पर हमारे क्षेत्र की जनता मांग रही है। यहां पर गंगा और सरयू के बीच का दोआबा का रेलवे स्टेशन है। इसी स्टेशन से बलिया के लोग बिहार को टच करते हैं और बिहार के लोग यहां आते हैं। रेवती रेलवे स्टेशन बहुत पुराना है। वहां अस्पताल, डिग्री कॉलेज और थाना है। दोआबा के दो लाख लोग वहां जाते हैं और यही हाल बनकटा रेलवे स्टेशन का है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे इलाके की जनता पर, सलेमपुर की जनता पर कृपा करें और इन दोनों रेलवे स्टेशन को पुनः बहाल करें। आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY):** Madam, I am standing here to bring to your attention the pressing matter of heavy rainfall casualties in the State of



Kerala. The State of Kerala is in a grave situation where unprecedented floods have caused havoc in the State, resulting in extensive loss of lives and properties, displacement of thousands of people and substantial damage of crops, livestock and infrastructure. The latest State-wise rainfall distribution data from the Indian Meteorological Department indicates that Kerala experienced the second highest percentage of rainfall during the last week with an accumulation of 8.45 centimetres of rain.

(1215/RP/YSH)

I am deeply saddened to report that last week six individuals tragically lost their lives in various rain-related incidents across the State.

As on July 17<sup>th</sup>, around 474 individuals from 143 families have been shifted to 31 relief camps across the State. Besides, power voltage and other infrastructural damages have been affecting the lives of several people in the State. According to the Kerala State Electricity Board, more than a thousand electric poles and several transformers have collapsed during the heavy rain. This has caused a loss of lakhs of rupees.

Keeping in view the magnitude of this disaster, I urge the Central Government to provide immediate assistance to Kerala State to support rescue and relief operations and further allot necessary resources for rehabilitation and reconstruction efforts. Also, a comprehensive package should be considered to support the State of Kerala.

Thank you.

**डॉ. हेमंत विष्णु सवरा (पालघर) :** सभापति महोदया, मैं पालघर जिले में ग्रामीण पर्यटन, समुद्री तट, खूबसूरत बीच, किले और पुरातन मंदिर जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग करता हूँ। ग्रामीण पर्यटन प्रकृति आधारित पर्यटन है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य स्थान होता है।

महाराष्ट्र के पालघर लोक सभा क्षेत्र में सागरीय, नगरीय और डोंगरी जैसे क्षेत्र हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता के साथ जीवन की हलचल से दूर शांतिपूर्ण विश्राम की तलाश करने वाले पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। खास तौर पर ग्रामीण पर्यटन और समुद्री तट, जो कि लगभग 84 किलोमीटर का है और खूबसूरत बीच विदेशी पर्यटकों और अपने देश के पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। यहां का शांत समुद्र तट, जो अपनी सुनहरी रेत और शांत माहौल के लिए जाना जाता है, विश्राम और पानी के खेल के लिए भी आदर्श है। यह शहर और क्षेत्र पर्यटकों को ट्रैकिंग, कैंपिंग और समृद्ध वनस्पतियों के खोज का अवसर प्रदान करता है। पालघर प्राचीन गुफाओं और किलों सहित ऐतिहासिक स्थलों का भी घर है, जो उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। पालघर में कई गढ़ हैं जैसे वसई किला, अर्नाला किला, कोहोज किला, भूपतगढ़ किला और डहाणू किला है।

इसके अलावा कई वाटरफॉल्स हैं जैसे दभोसा, हिरडपाडा और कलमंडवी, जो कि जव्हार तालुका में आते हैं। इसके अलावा काफी पुरातन मंदिर भी हैं जैसे जिवदानी माता, महालक्ष्मी माता, वाघोबा, शीतलादेवी, वज्रेश्वरी, गणेशपुरी तथा परशुराम मंदिर, जो कि गुंज-काटी तालुका में स्थित है।

इसके अलावा इस्कॉन सेंटर है, जो गलतरे में स्थित है। पुरातन शिवमंदिर है, जो कि बालकापरा जव्हार में स्थित है। कावडा विक्रमगढ में है और देहरे जव्हार में है। यहां पर दहनु बिच महोत्सव होता है, जो कि काफी सालों से पर्यटकों का आकर्षक स्थान बन चुका है। शिरपामल है, जहां पर छत्रपति महाराज के चरण है। पालघर लोक सभा क्षेत्र में ऐसे 15 आइडेंटिफाइड प्लेसेस हैं और 15 अनडेवलपड विलेज हैं, जिनको हम डेवलप कर सकते हैं।

सभापति महोदया, हम सभी जानते हैं कि पर्यटन के इस रूप के विकास के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। आने वाले समय में ग्रामीण पर्यटन इस पालघर क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरेगा।

मेरा माननीय पर्यटन मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह है कि पालघर जिले के सम्पूर्ण पर्यटन विकास, खास तौर पर ग्रामीण पर्यटन और सुंदर समुद्री तट एवं समुद्र बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उचित कार्यक्रम बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें। I can say that it can increase employment and self-employment and reduce migration as well as malnutrition. हमें विश्वास है कि आपके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और उचित वित्तीय सहायता से पालघर के पर्यटन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

(1220/RAJ/NKL)

**डॉ. राजीव भारद्वाज (कांगड़ा) :** सभापति महोदया, मैं पहली बार चुन कर देश की सर्वोच्च पंचायत लोक सभा में पहुंचा हूँ, इसके लिए मैं आपका एवं अपने क्षेत्र की जनता का, जिसे मैं अपना भगवान मानता हूँ, उनका कोटि-कोटि वंदन करता हूँ। मुझे शून्य काल के अंतर्गत बोलने का मौका दिया गया है, तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी से कहना चाहता हूँ कि कांगड़ा लोक सभा क्षेत्र दो भागों में विभक्त है - जिला कांगड़ा और जिला चम्बा। ये दुर्गम क्षेत्र हैं। यहां दुर्घटना की संभावना हर समय बनी रहती है। इसके लिए मेरे लोक सभा क्षेत्र में बहुत बड़ा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल नहीं है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिला कांगड़ा में नूरपुर विधान सभा क्षेत्र और जिला चम्बा में बाथरी क्षेत्र, जो बिल्कुल नेशनल हाइवे से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहां पर दो आधुनिक ट्रामा सेंटर्स स्थापित करने की कृपा करें, क्योंकि दुर्घटना की स्थिति में हमें साथ के प्रदेश पंजाब में जाना पड़ता है। गंभीर दुर्घटना की स्थिति में मरीज वहां तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। मेरी यह प्रार्थना है कि जिला कांगड़ा के नूरपुर में और

जिला चम्बा के बाथरी में सुपर स्पेशियलिटी ट्रामा सेंटर स्थापित करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा।

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Madam, the move, as reported, to bifurcate the Palakkad Railway Division to create a new Division will not be and cannot be accepted by the people of Kerala. The jurisdiction of Palakkad Division has already been reduced to create the Salem Railway Division by carving it out. Palakkad Division is one of the highest revenue earning divisions in the country. The railway development is not taking place under Palakkad Division proportionate to the earnings. Therefore, the proposed bifurcation plan should be withdrawn, and instead, action should be taken to implement developmental plan under Palakkad Division. Thank you.

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): Madam, I would like to draw the urgent attention of the Government to the recurring accidents and human casualties occurring at Muthalappozhi fishing harbour in my constituency Attingal, Kerala. More than 75 fishermen have lost their lives due to accidents in Muthalappozhi harbour. This year itself, a dozen accidents occurred in this harbour in which four fishermen have died. Continuous accidents are happening due to faulty construction of the breakwater. The local people and fishermen are alleging that the unscientific construction is the main reason for accidents there.

Madam, since 2019, I have been continuously raising the issue of Muthalappozhi harbour in Parliament and also with the Union Ministry of Fisheries, and have been demanding a scientific solution to the problem. But it is unfortunate that corrective measures are getting delayed while such tragedies occur frequently.

Madam, it is also necessary to enhance the safety measures and deploy permanent a rescue operation team at Muthalappozhi. Around 25,000 fishermen from the region depend upon the Muthalappozhi harbour for their livelihood. Therefore, immediate measures are required to find out a permanent solution to avoid further tragedies. I request the Union Government to implement a special project for ensuring safety of this harbour. Thank you.

(1225/VR/KN)

[SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Hon. Chairperson, Vanakkam. I wish to raise an important issue in this august House. My Vellore parliamentary constituency had played a significant role in the national freedom struggle. The first revolt of Indian Independence was started in Vellore. There is an empty ground surrounding the Vellore Fort where great leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and K. Kamaraj had addressed the public gatherings. Many public events were organised in the past. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu *Thalapathi* Shri M.K. Stalin has implemented several welfare schemes for the people from this very important fort ground. You are aware that even the present Prime Minister attended an election meeting at this venue, at the fort ground. But more recently, just 10 days ago, the Archaeological Survey of India has grabbed this land and issued a circular putting a ban on organising public gatherings / events at this venue. The Archaeological Survey of India has also made fencing of this venue. This is a public ground that belonged to the Vellore Fort where all the public events / programs were organised till now. I put before you my request to permit public use of this ground, belonging to the ASI, as it was before. A circular was issued in this regard urgently by the Archaeological Department very recently, saying that this ground should be converted as a lawn with grass besides undertaking archaeological activities. I urge upon this Government that the Fort ground of Vellore should be allowed for public use. There should be a permanent dais or platform to be set up at this place for organising public gatherings. I also urge that the ASI should permit organising exhibitions and entertainment-related functions at this venue free of cost.]

The hon. Minister is here. If he can intervene, he can also give reply.

**माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) :** माननीय सदस्य, आपकी बात आ गई है।

डॉ. धर्मवीर गांधी जी।

**डॉ. धर्मवीर गांधी (पटियाला) :** महोदया, मैं आपके द्वारा सरकार एवं सदन के सभी सदस्यों का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। अभी-अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर उन सारे रूट्स पर खान-पान की सभी दुकानों, ठेलों, रेहड़ियों तथा दूसरी जो शॉप्स हैं, उन पर नाम लिखने का ऑर्डर दिया गया है। यह एक विभाजनकारी कदम है। उस एरिया में शांति से जो लोग रह रहे हैं, वहां एक नए तरह का तनाव पैदा होगा। यह अन-कॉन्स्टीट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है और गैर लोकतांत्रिक है।

उसके बाद उत्तराखंड में भी हरिद्वार के एसएसपी ने एक ऐसा ही ऑर्डर पास किया है कि सभी संस्थान, खान-पान की दुकानें, ठेले, रेहड़ियों पर कांवड़ यात्रा के सभी रूट्स पर अपना नाम लिखें। मुझे लगता है कि यह एक विभाजनकारी एजेंडा है और इसको लागू करके भाजपा पार्टी अपना राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करना चाहती है, जो एक समाज को बांटने का यत्न है। इसे बंद करने के लिए मैं सरकार से विनती करता हूँ। देश के नागरिकों में आपसी सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए और देश की एकता को कायम रखने के लिए इन ऑर्डर्स को वापस लिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तराखंड सरकार ने अभी जो नीतियां बनाई हैं, उनको वापस लिया जाए। समाज में जो शांतिप्रिय लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, उनको सद्भावना से और प्यार से रहने दिया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा पश्चिम) :** महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय को त्रिपुरा से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय से अवगत कराना चाहता हूँ।

(1230/PC/SAN)

त्रिपुरा राज्य माता त्रिपुर सुंदरी की भूमि है, माता की 51 शक्तिपीठ में से एक है। राज्य के उदयपुर शहर में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर के रूप में स्थापित है। वहां प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। पूरे भारत से मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के लिए 'प्रसाद योजना' के अंतर्गत माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर का विकास किया जा रहा है।

माताबारी मंदिर विकास परियोजना उत्तर पूर्व भारत में अध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सबसे प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगी और त्रिपुरा का विकास सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही साथ भारत की अध्यात्मिक चेतना को भी मजबूती प्रदान करेगी। पूर्व में मंदिर के विकास के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 37.8 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई थी। इस परियोजना का कार्य शुरू हुआ, तो पाया गया कि श्रद्धालुओं के लाभ और स्थान के बेहतर उपयोग के लिए और आवश्यक कार्य करने के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत है।

इस अतिरिक्त विकास कार्य के लिए 17.61 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय आवश्यक हो गया है। इस विषय पर तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री को दिनांक 21 दिसंबर, 2023 को उक्त धनराशि जारी करने के लिए मैंने पत्र भी लिखा था, परंतु अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से उक्त धनराशि जारी करने का आग्रह करता हूं, जिससे मंदिर की विकास परियोजना को समय से पूरा किया जा सके।

धन्यवाद।

**श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) :** सभापति महोदया, मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव में वर्तमान प्रशासक पद पर नियुक्त श्री प्रफुल पटेल जी इस पद पर पिछले आठ वर्षों से कार्यरत हैं, जबकि किसी भी यूटी में प्रशासक का कार्यकाल सिर्फ तीन साल का होता है। राज्यपाल, उप-राज्यपाल, सबका कार्यकाल पांच साल का होता है। यहां तक कि राष्ट्रपति जी का कार्यकाल भी पांच साल का ही होता है। ऐसे में प्रशासक श्री प्रफुल पटेल जी का आठ साल का कार्यकाल हमारी समझ से परे है। हमारी सरकार की नीति रही है कि प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियत समय पर बदली होनी चाहिए, जिससे पारदर्शिता से कार्य हो सके। इस कारण प्रशासक का ऐसे पद पर पांच साल से ज्यादा का कार्यकाल सही नहीं है।

वर्तमान प्रशासक के कार्यकाल में प्रदेश में जो भी कार्य हुआ है, उसमें चरम पर भ्रष्टाचार हुआ है। आमजन दुखी और परेशान हैं। इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी इस पद पर वे नियुक्त हैं, जबकि इस पद के लिए नियुक्ति के मापदंड भी वे पूरे नहीं करते हैं।

महोदया जी, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि वर्तमान प्रशासक महोदय को हटाकर इस पद पर किसी ईमानदार सीनियर आईएएस अधिकारी को लगाया जाए, जिससे

आमजन को भ्रष्टाचार से राहत मिल सके और हमारी सरकार की हो रही बदनामी से भी बचाया जा सके।

महोदया जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

धन्यवाद।

**डॉ. संबित पात्रा (पुरी) :** नमस्ते माननीय महोदया जी, आपने मुझे यहां अपना विषय रखने का मौका दिया है।

जैसा कि विदित है, मेरे लिए यह गर्व का विषय है कि मैं जगन्नाथ पुरी धाम से पहली बार सांसद बनकर आया हूँ।

महोदया जी, आप सभी ने देखा होगा, गणमान्य के माध्यम से देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि सात और आठ तारीख को रथयात्रा थी। लगभग 25 लाख श्रद्धालुओं का आवागमन पुरी में हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि पुरी एक ऐसा शहर है, ऐसा धाम है, जहां लाखों लोग महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं।

मेरा प्रश्न आज स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर केंद्रित है और मैं स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ। एक अनहोनी 29 मई, 2024 को घटी थी, जब जगन्नाथ जी की यात्रा से पहले एक नीति चल रही थी, जिसे चंदन यात्रा कहते हैं। नरेन्द्र पोखर में प्रभु स्नान करने आए थे। उसे 'चाप खेलना' कहते हैं, उस समय आए थे, तो वहां आगजनी की एक दुर्घटना में लगभग 17 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का एक मुख्य कारण यह भी रहा कि सबसे नजदीकी अस्पताल, जहां 'बर्न्स यूनिट' अवेलेबल है, डेडिकेटेड बर्न्स यूनिट अवेलेबल है, वह लगभग 70 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर में स्थित है। जगन्नाथ पुरी धाम में कोई भी बर्न्स यूनिट नहीं होने के कारण 17 लोगों की जान गई और कई लोग अभी भी अस्पताल में खराब हालत में हैं।

(1235/SNT/CS)

वही कारण रहा कि 4 तारीख को जब नतीजे आये, हमारी जीत हुई, हमारे कई विधायकों की भी जीत हुई, हम लोगों ने नम आँखों से उन लोगों को उस दिन विदाई दी।

आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय को अपील करना चाहता हूँ कि श्री जगन्नाथ धाम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो कि केन्द्रीय मंत्रालय के अवदान से वहाँ खोला गया है, वहाँ 308 बेडेड हॉस्पिटल है, अनुदान केन्द्रीय मंत्रालय का है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि वहाँ एक डेडिकेटेड बर्न्स यूनिट खोली जाए। केवल डेडिकेटेड बर्न्स यूनिट ही नहीं, उस अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी यूनिट भी खोली जाए, क्योंकि पुरी कोई साधारण स्थान नहीं है। वहाँ लाखों लोगों का आवागमन होता है। कई बार हमने देखा है कि वहाँ रथ यात्रा के समय अगर लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है तो गोल्डन फेज, गोल्डन पीरियड, जो कुछ घंटों का होता है, उसके अंदर डॉक्टरखाना या अस्पताल नहीं पहुँचने के कारण वे मृत्यु को वरण करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से धारण किया जाए और एक डेडिकेटेड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल उस मेडिकल कॉलेज में खोला जाए। धन्यवाद।

**श्री सुरेश कुमार कश्यप (शिमला) :** महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मेरे संसदीय क्षेत्र में बच्ची, बरोटीवाला, नालागढ़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत फोर लेन की स्वीकृति हुई है। वर्ष 2021 में इसका कार्य प्रारम्भ हुआ है। लगभग 469 करोड़ रुपया इसके लिए स्वीकृत हुआ है। वर्ष 2024 में ही इस कार्य को पूर्ण होना है, लेकिन अभी तक इसका मात्र 30 से 35 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ है। यह जो फोर लेन है, यह हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दो राज्यों से होकर जाने वाला है। आद्यौगिक क्षेत्र होने के कारण और जब आज इसका कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है तो वहाँ ट्रैफिक की भारी समस्या हो रही है, बार-बार ट्रैफिक अवरुद्ध हो रहा है, जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा भूतल परिवहन मंत्री जी और केन्द्र सरकार से यह निवेदन रहेगा कि इसका कार्य शीघ्रताशीघ्र पूरा किया जाए ताकि लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को जिस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उससे उन्हें निजात मिल सके।

महोदया, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI):** Thank you for giving me an opportunity to speak today in the Parliament.

Madam, through you, I would like to put forward a request for Kalahandi district for executing a very old project which was surveyed and put up for execution connecting Rahul and Utei river under the National River Linking Project for irrigation purposes at Karlamunda and Madanpur Rampur blocks of Kalahandi district. This will solve the drought situation which affects the poor farmers and their families because of water shortage. It will also improve irrigation and provide water to villages which are completely rice-farming areas and totally dependent on rain water and river water. It will increase the ground water level and allow people to fill the water tanks which stay dry for most of the year causing major water problems and shortages in villages. Irrigation water is a big problem of the farmers in both the blocks of Karlamunda and Madanpur Rampur of Kalahandi. As you all know, Kalahandi was once very infamous as the poor and famine-stricken district of India. But today Kalahandi has worked very hard and developed, and it is wanting to become the highest rice-producing district of Odisha but a few blocks still face water insufficiency.

Hence, I would request you once again to please sanction this project as it would irrigate two big blocks of Kalahandi – Karlamunda and Madanpur Rampur. Thank you, Madam.

(1240/IND/AK)

**श्री जुगल किशोर (जम्मू) :** महोदया, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय एवं रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र साम्बा की ओर ले जाना चाहता हूँ। साम्बा एक बड़ा शहर है और यहां एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहां जो ट्रेनें चला करती थीं, कोरोना काल के बाद उनका ठहराव बंद हो गया है। कोरोना काल से पहले यहां काफी ट्रेनें रुका करती थीं जैसे कि जम्मू मेल, मालवा, झेलम, हेमकुंड आदि। लेकिन आज की तारीख में केवल हेमकुंड रेल ही साम्बा में रुकती है। इन ट्रेनों का ठहराव कोरोना काल में बंद हुआ था और आज तक इनका ठहराव बंद है। मेरी आपके माध्यम से रेलवे मंत्रालय से प्रार्थना है कि इस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें रेल पकड़ने के लिए या तो पठानकोट जाना पड़ता है या जम्मू जाना पड़ता है। जो लोग इन दिक्कतों का सामना करते हैं, उनका कहना है कि इतनी परेशानी से बेहतर यह है कि हम बस द्वारा ही सफर करें क्योंकि रेलवे का कोई लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है।

मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि जिन रेलों का यहां कोरोना काल से पहले ठहराव होता था, उनका ठहराव जारी किया जाए जैसे जम्मू मेल, मालवा, झेलम और सम्पर्क क्रांति आदि। धन्यवाद।

**\*SHRI OMPRAKASH BHUPALSINH ALIAS PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD):** Hon. Chairperson, first of all, I would like to thank all the people of Dharashiv Lok Sabha constituency for electing me to Lok Sabha for the second consecutive term just to serve them and solve their problems.

I would like to raise the issue related to crop insurance in Maharashtra. Whether this scheme is being run for the benefit of the farmers or for the insurance companies is the question.

Under the Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme, during the years 2016-2023 from my Maharashtra State, Rs 33,060 crore has been paid to various companies. The insurance companies have paid Rs 23,874 crore to farmers as crop insurance compensation, out of which the net profit of Rs 9,186 crore has accrued to the insurance companies during 2016-2020. This scheme is not being run for the benefit of the farmers but for the benefit of the companies.

So, I would like to request the Union Government that some policy related changes should be made. We are paying around Rs. 18,000 per hectare as a premium to the insurance companies, including the shares of State, Central Government as well as the farmers.

In Dharashiv district, around 7, 53,382 farmers insured their crops in the year 2023. But out of this, around 5,19, 273 farmers are still deprived of insurance benefits. In Barshi Tehsil, 88,560 farmers chose the insurance scheme but all of them are still waiting for compensation. In Ausa Tehsil, out of 1,27,381 farmers 33605 farmers are still deprived. In Nilanga Tehsil, out of 1,46,716 farmers, around 49,185 farmers have not received insurance benefits yet.

A circular dated 30/04/2024 issued by the office of Ministry of Agriculture during the General Elections clearly shows that the Central Government is completely supporting the insurance companies. I would like to draw your attention towards the fact that this circular was issued in the middle of the election process. This circular is discriminatory and unjust and barring the farmers from availing the insurance benefits.

I have written to the hon. Agriculture Minister in this connection and I would like to request Union Government through you, to withdraw this circular and also to make some changes in the crop insurance scheme. Instead of paying this amount of Rs. 18,000 to insurance companies, the Government should pay it to the farmers directly. Thank You.



(1245/RV/UB)

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा)** : सभापति महोदया, शून्य प्रहर में माननीय रेल मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे संसदीय क्षेत्र में हावड़ा-राजगीर फास्ट पैसेंजर राजगीर से हावड़ा के लिए चलती थी, जिसे कोरोना काल में बंद कर दिया गया था। इस ट्रेन से यात्री और सैलानी, जिनमें बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी थे, वे तीर्थयात्रा के लिए नालंदा आना-जाना करते थे। मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा के आस-पास से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उस ट्रेन से देवघर भी जाते थे। बाबा भोले को जल चढ़ाने का श्रावण मेला आज से ही शुरू हुआ है।

महोदया, मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि ट्रेन संख्या 53043, जो कोलकाता से राजगीर के लिए चलती थी, उसे शुरू किया जाए।

श्रमजीवी एक्सप्रेस का ठहराव कोविड के समय में सिलाव स्टेशन और पावापुरी स्टेशन पर बंद कर दिया गया था। उसको भी चालू किया जाए, जिससे वहां के स्थानीय लोगों के आवागमन में सुविधा हो सके।

उसी तरह से, कोरोना काल से पहले मेमू ट्रेन, दानापुर से तिलैया के बीच सभी हॉल्ट्स पर रुकती थी, पर अभी उसे बंद कर दिया गया है। माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इसको भी चालू किया जाए।

कोरोना के समय में बंद हुई जितनी भी ट्रेनें हैं, अगर उन्हें चालू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों को काफी खुशी होगी। हम लोग चुनावों में यह वादा करके आए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वहां जो काम हो रहा है और देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वहां जो काम हो रहा है, इन सबके बीच हम लोग अच्छे कामों को करके आए हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस कार्य को करें।

**SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR):** Madam, I wish to draw the attention of the House to the severe flooding in Kerala. Relentless heavy rainfall has led to devastating floods and landslides, claiming more than 25 lives and displacing thousands of people. The entire State of Kerala is worst affected. The State Government's resources are stretched thin necessitating immediate Central financial assistance. I urge the Central Government to provide financial aid of minimum Rs. 1000 crore, deploy additional NDRF teams, supply essential medical and food supplies, and offer technical and financial assistance for infrastructure reconstruction. This disaster demands our urgent and collective action to alleviate the suffering of the people of Kerala.

\*[SHRI G. LAKSHMINARAYANA (ANANTAPUR): I thank the Chairperson for allowing me to speak here for the first time. I thank our leader and Chief Minister Nara Chandrababu Naidu, Nara Lokesh and Nandamuri Balakrishna for giving me an opportunity to become an MP.

I also thank the people of my constituency for electing me as an MP by giving a thumping majority in the elections. I would like to raise the following matter.]  
(1250/SRG/GG)

Madam, I wish to raise an urgent issue in this august House regarding resumption and completion of NH-67 from Karnataka-Andhra Border to Gooty Section. The upgradation of NH-67 from the Karnataka-Andhra Border to Gooty section, sanctioned under NHDP-IV with an investment of Rs. 995.09 crores, has faced severe delays. Originally scheduled for completion by October 2018, the project has been stalled for over one and a half years, impacting road safety and regional development. The incomplete section, particularly between Guntakal and Gooty, is plagued with potholes, unmarked debris and inadequate drainage. These hazardous conditions have led to frequent accidents, including fatalities and have severely disrupted daily commutes. The ongoing delays are not only compromising safety, but are also impeding economic growth in the region.

There is one more proposal pending regarding upgradation of the existing State Highway road from Yemmiganur on NH-167 at km 94/400 connecting Yemmiganur, Pattikonda, Uravakonda, Kalyandurg, Pavagada and terminating at its junction with NH 544 E near Madakasira at km 60/200 in the State of Andhra Pradesh. The proposal for upgradation of the NH submitted to the MoRT&H, New Delhi on 21.6.2022. The length included 69.237 kms in Kurnool district.

There is one more proposal pending for upgradation of existing State Highway 410 Bellary- Bommanahal - N. Gundlapalli via Veparalla road from km 14.640 to km 52.673 in the State of Andhra Pradesh and MDR from km 2.550 to km 14.640 in the State of Karnataka. The proposal dated 24.4.2022 was submitted to the Principal Secretary to the Government of India, MoRT&H.

The timely completion of these projects is crucial for meeting the infrastructure needs and improving connectivity in the region. Our people's lives, safety, and economic well-being depend on it. Let us not fail them. Let us act with urgency and responsibility which this situation demands.

---

\* [ ] Original in Telugu

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Madam, thank you for affording me an opportunity to speak on one of the very important Constitutional issues in the country. Recently, the Kerala Government has issued an order on 15.7.2024 whereby Dr. Vasuki, an IAS officer, has been appointed as the Foreign Secretary. She was required to perform all the matters relating to the external affairs, external cooperation, coordination and supervision, and incidental thereto. I would like to submit that on matters relating to external coordination, cooperation and supervision meant to deal with various nations, Indian Embassies and Missions abroad, the function can only be performed as per the Constitutional mandate by the Government of India as per the Business Rules through the Ministry of External Affairs. So, the action on the part of the Kerala Government issuing such type of order and appointing one of the IAS officers as Foreign Secretary to deal with the external affairs matters is nothing but unconstitutional.

(1255/RCP/MY)

It is an encroachment on the subject which has been given to the Union Government under the Union List. This is a blatant outreach. Is the Kerala Government treating itself as a separate nation? So, my submission is that it is expected from the Kerala Government at least to see List I that pertains to the Union subjects from item Nos. 10 to 14. I would like to read these subjects so that the Kerala Government can read again these subjects which are related to List I, that is the Union List. These subjects and these matters are mandated for the Government of India. These functions are to be performed by the Ministry of External Affairs, not by the Kerala Government. The Kerala Government is not competent to issue such types of orders. I would like to read List I—Union List from item Nos. 10 to 14:

“10. Foreign affairs; all matters which bring the Union into relation with any foreign country. 11. Diplomatic, consular and trade representation. 12. United Nations Organisation. 13. Participation in international conferences, associations and other bodies and implementing of decisions made thereat. 14. Entering into treaties and agreements with foreign countries and implementing of treaties, agreements and conventions with foreign countries.”

So, the order issued by the Kerala Government appointing one of the IAS officers as Foreign Secretary is unconstitutional.

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you, Madam, for giving me an opportunity. This issue is one of the most serious issues which is concerning the human life of the people of Kerala. Invasion by wild animals in human habitation is happening day by day in Kerala. There is an alarming rise in human-animal conflicts, especially involving elephants, tigers and wild boars. Last year itself, these conflicts claimed

around 100 lives. Over 10 fatalities have already been reported this year. In Wayanad district alone, four people have been killed within the past three-four months. Almost the entire agriculture plantation has been disturbed due to this man-animal conflict. In response, the Kerala Cabinet has declared this situation as a State-level disaster.

The situation in Kerala is not a unique situation. The national data reveals that there have been over 1500 deaths from elephant attacks and 125 deaths from tiger attacks between 2019 and 2022 that happened in Kerala. We are not against animals. But there is value of human life. We are asking for a proactive action from the Centre for the last so many years. The entire population of Kerala is asking for rescue from the Central Government. But there is no response at all. In February, the Kerala Assembly called for amendments to the Wildlife Protection Act. Of course, the Wildlife Protection Act was passed with a progressive mind. We agree. But now the problem is to see whether human life is important or not. Everyday people are in a great distress. People from the entire Kerala especially people who are residing near the forest area are greatly concerned about their livelihood and their lives. We need to intervene in that. Therefore, my submission is this. The Government of India is not taking any action. People are telling that the State Government is also not taking any action. Smart early warning system is not much effective. Strategic Rapid Reforms Teams have not been effective at all.

Regarding cutting-edge equipment and training, there is no sufficient equipment. Same is the case with community involvement through Jana Jagratha Samithies. These are all there for namesake only. But in effect, in reality what is happening is that everyday, human life is in danger. Therefore, the Kerala Assembly unanimously passed a Resolution. I am quoting that Resolution:

“To amend the Wildlife Protection Act, 1972 including sub-section (2) of Section 5 delegating all the powers of Chief Wild Life Warden conferred under clause (a) of sub-section 1 of Section 11 of the Wildlife Protection Act, 1972 to the Chief Conservator of Forests so as to enable them to take immediate action.”

The Government of India has to make amendments immediately to the Forests Act.

**माननीय सभापति:** माननीय सदस्य, आपकी बात आ गई है।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, you allow for a political issue for whatever time they want. Madam Chairperson, this is a human issue. Everyday people are ... (*Interruptions*) At least, allow us to raise this issue. The Government has to come forward to change the law. That is what I want to say. Thank you very much.

(1300/NK/PS)

**माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय):** माननीय सदस्यगणों, मैं अभी कुछ नये सांसदों को मौका दे रही हूँ, उसके पश्चात् कुछ अन्य सदस्यों को मौका दिया जाएगा। समय की कमी है इसलिए कृपया अपने विषय को एक मिनट के अंदर रखें।

**श्री रविंद्र दत्ताराम वाइकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) :** माननीय सभापति, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं इस सदन में पहली बार अपने विचार रखने जा रहा हूँ। कल हम लोग इस सदन में आने को निकले थे, बारिश का मौसम है, एयरपोर्ट पर प्लेन 1235 बजे का प्लेन था, मगर 1235 बजे प्लेन उड़ नहीं सका क्योंकि हैवी रेन हो रही थी, एक कारण तो यह है, लेकिन दूसरा कारण यह है।

**माननीय सभापति:** माननीय सदस्य आप अपने विषय को रखें।

**श्री रविंद्र दत्ताराम वाइकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम):** सभापति महोदय, सांताक्रुज एयरपोर्ट के लिए दो रनवे होने की जरूरत है, एकचुअली वहां दो रनवे हैं। इसकी कम्पलेंट भी की गई है, वह कम्पलेंट यह है कि Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai is equipped with two crossing runways which are called 09/27 and 14/32. Runway 14/32 (2,925 metre, 9,596 feet) is the one that runs between terminals 1 and 2. The main runway 09/27 intersects 14/32 just south of the terminal buildings. At first, it was considered to construct a second parallel runway as part of its master plan. मगर वह अभी तक हुआ नहीं है, इसके लिए मास्टर प्लॉन बनाने की जरूरत है। वहां आजू-बाजू में झोपड़पट्टी है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाजू में जो झोपड़पट्टी है, उसका डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। उसके अंदर जो कचरा है, उस कचरे के माध्यम से वहां पशु-पक्षी होते हैं। पक्षी विमान को भी लग सकता है, इस कारण उसका डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है।

**माननीय सभापति:** माननीय सदस्य आपकी बात आ चुकी है, आपका विषय पटल पर आ चुका है।

**\*PROF. VARSHA EKNATH GAIKWAD (MUMBAI NORTH CENTRAL):** Hon'ble Chairperson, thank you very much for allowing me to speak. Today, I demand to accord the classical language status to Marathi language. "We are really fortunate that we speak Marathi, we are thankful that we listen Marathi, Our religion, sect and caste is only Marathi. We regard Marathi as our mother. Our minds and hearts are filled with love and respect for Marathi and it is flowing through our veins too. Our Marathi language is an ancient and prosperous language. It is thousands of year old language and you can trace the historical footprints of literature and religious books written in Marathi. This contribution is very important in Indian culture. As of now, Tamil, Sanskrit, Telugu, Kannada, Malayalam, and Odia languages have been identified as Classical language by Union Government. First written text in Marathi, 'Gaatha Saptashati' is a compilation of 700 poems of the people. Satavahana King Haul of paithan had compiled 50 poems in Marathi 2000 years ago. The state language of Satavahan Empire was Marathi and the copies of this text have been found at different locations under the Satvahana Empire. It was spread throughout India and the period is around 230 AD to 500 AD approximately. So, it is proved that Marathi language is more than 2000 years old. It also has got an original and continued literary tradition. Prof. Ranganath Pathare Committee had concluded that Marathi fulfills all the parameters to be recognised as a classical language and the classical language status should be granted to Marathi language.

---

\* Original in Marathi

(1305/SK/SMN)

SUSHRI SAYANI GHOSH (JADAVPUR): Madam, thank you so much for letting me speak in this august House and I also thank the people of Jadavpur Parliamentary Constituency for electing me as their representative.

Madam, metros are the fastest and the most convenient and the cheapest mode of urban commuting and there have been several ongoing projects to extend the Kolkata Metro. However, the Baruipur Kavi Subhash also known as the Garia metro extension was proposed in the Railway Budget of 2011-2012 but there has been no positive movement since then. Baruipur is a fast-developing town which is about 25 kilometres from Kolkata with a growing population of more than five lakh people. Thousands of people utilize the train facility daily to commute for work, for education and other essential activities. Since Kavi Subhash is becoming a key junction for the residents of Baruipur, a metro station is the need of the hour. In 2017, the tentative plan was to build the tracks along the Adi Ganga but nothing has happened since. Despite the completion of the feasibility study for extending Kavi Subhash to Baruipur link as a part of the east-west metro extension, it still awaits approval from the Railway Board.

Our leader hon. Chief Minister Ms. Mamata Banerjee was repeatedly raising the issue highlighting the ongoing delays by the Railway Ministry. Several letters have been written to the Ministry including letters from the Speaker of West Bengal Legislative Assembly who is also the MLA of Baruipur Paschim for construction of this key metro expansion but to no avail.

Madam, I request the Government to expedite the Baruipur Kavi Subhash metro extension proposed for more than 12 years. It is extremely crucial for the people of both rural and urban Baruipur. लोग लाखों की तादाद में कोलकाता आते हैं इसलिए यह मेट्रो स्टेशन जितनी जल्दी बनेगा, उतना अच्छा होगा।

माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं यही दरखास्त करना चाहती हूँ।

**श्री मनोज कुमार (सासाराम):** माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सासाराम, बिहार क्षेत्र से चुनकर आया हूँ, वहाँ की जनता मेरे लिए भगवान है।

माननीय सभापति जी, आपको मालूम होगा कि सासाराम पार्लियामेंट की सुरक्षित सीट है, यहाँ एससीज़ और एसटीज़ की संख्या बहुत तादाद में है। जब मेरे पिताजी पाँच साल के थे, तब मैंने अपने दादा-दादी को खोया था। मेरी एक बहन थी, उसे भी मैंने खोया है। मेरा सवाल स्वास्थ्य समस्या को लेकर है। यहाँ कैमूर पहाड़ी है और यह पहाड़ी हिमालय से भी पुरानी है। पहाड़ पर एससी और एसटी समाज के लोग रहते हैं। आज भी दवा के अभाव में हर साल हजारों लोग दम तोड़ते हैं। मेरा आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि यहाँ बेस्ट ट्रामा सेंटर और एम्स की स्थापना हो जाए तो हजारों लोगों को हर साल बचाया जा सकता है। सवाल इस प्रकार से है कि यदि छोटी सी बीमारी हो जाए तो लोगों को बनारस या पटना जाना पड़ता है। आज भी 80 प्रतिशत ऐसे गरीब लोग हैं, जो पैसे के अभाव में न ही पटना जा पाते हैं और न ही बनारस जा पाते हैं। वे इस कारण रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं।

मेरा एक और अनुरोध है कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो हमारा उत्थान हो सकता है।

(1310/MK/SM)

\*SHRIMATI BAG MITALI (ARAMBAG): Greetings, Madam. I thank you for giving me the opportunity to speak. I pay my respects to Shri Shri Ramkrishna, Maa Sarada, Taraknath from Tarakeswar and Ghonteswari. The people from the Arambagh constituency has elected me for the first time and sent me to the Parliament with their blessings. I am a woman from the SC community. My question concerns a very important issue. Since a long time, the hardworking people of West Bengal have worked with their blood and sweat under the 100 days work scheme. Yet the central government has been trying to push them to the brink of starvation. The government should release their due funds immediately. We have faced many questions in this Parliament House, and we have recurrently heard many statements which said that the agricultural sector has improved, the lives of workers have improved, the lives of SC, ST community have improved. But in reality, we, the poor daily wagers are still being deprived. Since you have granted me the permission to speak, I will once again repeat my demand of the reinstatement of the rights of the deprived section of Bengal. At the same time, I will also state that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Bandyopadhyay when she was the Railway Minister, initiated the Arambag to Bishnupur rail project which has now been stalled. The Lok Sabha constituencies- Arambag and Bishnupur are both tourist attractions, and to help people commute, I demand the reconstruction of Bhabhadighi Railway Station. I reiterate this demand in front of you. Another minor issue- due the rising prices of the essential commodities, those aren't reaching the kitchens of the people of Bengal. They are in severe distress. If the central government looks into their plight, I would be deeply thankful to them. I am concluding my speech. Many thanks to you for letting me speak.

---

\* Original in Bengali

**माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) :** कुमारी सुधा आर. – उपस्थित नहीं।

**श्री महेश कश्यप (बस्तर) :** माननीय सभापति महोदया, आपकी अनुमति से मुझे बोलने का अवसर मिला। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बस्तर लोक सभा क्षेत्र से हूँ, जो केरल राज्य से बड़ा है और इसका क्षेत्रफल इजरायल और बेल्जियम से बड़ा है।

महोदया, बस्तर की जनता ने लोक सभा में मुझे सांसद बनाकर इस लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है। हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। वहां बैलाडीला का लोहा खदान है। लोहा खदान से लोहा ले जाने के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई है और इसका विस्तार भी हुआ है। लेकिन, बस्तर के लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी रेल लाइन नहीं है।

महोदया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में दिल्ली-राजहरा रेल लाइन का विस्तार रावघाट तक हुआ है। केवटी तक रेल लाइन का विस्तार हुआ है। माननीय रेल मंत्री जी से मेरी भेंट हुई है। अभी रावघाट से जगदलपुर तक रेल लाइन का विस्तार नहीं हुआ है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि पहले किसी कंपनी को टेंडर दिया गया था। उस कंपनी ने असमर्थता व्यक्त करते हुए काम को छोड़ दिया है। अब नया डीपीआर तैयार हुआ है। वह कब तक पूरा होगा, यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ?

दूसरा, रायपुर से धमतरी तक एक बड़ी रेल लाइन का विस्तार हो रहा है। उस रेल लाइन का केशकाल, कोण्डागाँव और जगदलपुर तक विस्तार किया जाए। तीसरा, एक और रेल लाइन की मांग है कि हमारे बैलाडीला लोहा खदान से जो खनन हो रहा है, उसके लिए रेल लाइन है, लेकिन हमारे यहां के लोगों के लिए रेल लाइन का विस्तार नहीं हुआ है। उस रेल लाइन को गीदम से लेकर बीजापुर होते हुए, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र तक जोड़ा जाए, ऐसा मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी के पास प्रस्ताव रखता हूँ। इस विषय में, मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि उसका काम कब तक प्रारंभ होगा? मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

**माननीय सभापति :** सुश्री एस. जोतिमणि – उपस्थित नहीं।

**श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) :** सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मेरा जो विषय है, वह यह है कि पिछले पाँच सालों के अंदर वन विभाग की जो भूमि है, जहां खनन के लिए केंद्र सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को अनुमति दी है।

(1315/SJN/RP)

महोदया, बड़े दुख की बात है कि पिछले पांच वर्षों के अंदर 18,922 हेक्टेयर वन भूमि 179 कंपनियों को दी गई है। आज देश पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है। आज देश में प्रदूषण काफी हद तक बढ़ रहा है। हम पेड़-पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियों को खनन के लिए वन विभाग की भूमि दी गई है। यह बड़े दुख की बात है। अगर इससे सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ है, तो आदिवासी समुदाय प्रभावित हुआ है।

ये जो आंकड़े आए हैं, जो 18,922 हेक्टेयर जमीन है, उसमें से 16,490 हेक्टेयर जमीन सिर्फ राज्यों में है। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा हैं। अगर हम उसमें भी हिस्सा देखें, तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों से 90 प्रतिशत लोग प्रभावित हुए हैं।

माननीय सभापति महोदया, हम देखते हैं कि जंगलों में जो आदिवासी समुदाय रहता है, वह पेड़-पौधों को भगवान के रूप में मानता है। अगर वह उसकी पत्तियां और छोटी टहनियों को अपने जीवन में



उपयोग के लिए लेता है, तो वन विभाग दिक्कत पैदा करता है। अगर सिर्फ पांच वर्षों के अंदर ही 18,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं, तो इससे आदिवासी समुदाय परेशान हुआ है। विशेषकर बांसवाड़ा के अंदर केलामेला और दांता...(व्यवधान)

**माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) :** माननीय सदस्य, आप अपनी बात पूरी करें। आपको बोलते हुए एक मिनट से ज्यादा का समय हो गया है।

**श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) :** महोदया, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे प्रतापगढ़ जिले के तहत जो बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र है, वहां पर केलामेला और दांता में आदिवासी समुदाय बैठा हुआ है। केन्द्र सरकार ने परमीशन दी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसकी जांच करके उसको रुकवाया जाए और आदिवासियों को विस्थापित होने से रोका जाए।

**श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल (फतेहपुर) :** सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका प्रदान किया है। मैं जनपद फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) से पहली बार यहां चुनकर आया हूं।

महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र में कम वर्षा होने की वजह से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है। नहरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। किसानों को फसलों का भारी नुकसान हो रहा है, इसके लिए मैं सरकार से कुछ मांग करता हूं। फतेहपुर लोक सभा क्षेत्र में 6 विधान सभाएं हैं और 13 ब्लॉक्स हैं। वहां नहरें हैं, लेकिन पता नहीं किन कारणों से बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। आज से कुछ साल पहले तक विद्युत की आपूर्ति होती थी। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार के जमाने में किसानों को पूरी बिजली मिलती थी। इस समय विद्युत आपूर्ति न होने की वजह से किसानों की जो धान की फसल, गन्ने की फसल या जितनी भी फसलें हैं एवं जिन फसलों को जल चाहिए, उन फसलों को भारी नुकसान हो रहा है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि फतेहपुर लोक सभा क्षेत्र बुंदेलखंड से लगा हुआ है। बुंदेलखंड भी सूखे से प्रभावित है। मैं यही कहना चाहता हूं कि फतेहपुर लोक सभा क्षेत्र को सूखा घोषित करके किसानों की मदद की जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

**श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) :** माननीय सभापति महोदया, मेरे चुनाव क्षेत्र में मीरा भाईंदर महानगरपालिका है। वहां पर रोड बनाने के लिए और नागरिक सुविधा देने के लिए सॉयल विभाग की एक जमीन को ट्रांसफर करने की जरूरत है। बढ़ते नगरीकरण की वजह से उस जगह की बहुत जरूरत है।

\*(We have met the soil department in this regard many times. But, the Government is not responding positively. This department decided to sit with the Central Government, Municipal Corporation and Government of Maharashtra but the date has not been finalised yet.)

महोदया, नागरिक सुविधा देने के लिए हमें उस जमीन की बहुत जरूरत है। जल्द से जल्द वह जमीन हमें उपलब्ध कराई जाए, जिसके कारण लोगों को सुविधाएं मिलेंगी।

**श्रीमती कमलजीत सहरावत (पश्चिम दिल्ली) :** सभापति महोदया जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं दिल्ली से आती हूँ और मेरे क्षेत्र का नाम पश्चिमी दिल्ली है। दिल्ली शहर आज एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, जहाँ ट्रैफिक जॉम से बहुत दिक्कत होती है।

(1320/SPS/NKL)

मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, वह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का एक कॉम्बिनेशन है तथा इसका आखिरी गांव ढांसा बॉर्डर है, जो हरियाणा से लगता है। दिल्ली में जॉब करने के लिए बहुत से लोग बादली झज्जर क्षेत्र और ढांसा गांव से भी आते हैं। अभी तक दिल्ली में जो मेट्रो है, मेरे क्षेत्र में उसका आखिरी स्टेशन नजफगढ़ में है। मैं कंसर्न्ड मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर इस क्षेत्र को ढांसा गांव से नजफगढ़ और नांगलोई तक मेट्रो से जोड़ दिया जाए तो पश्चिमी दिल्ली और हरियाणा से जो लोग आते हैं, उनको बहुत राहत होगी। मेरा आदरणीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि वह इस बात को अपने ध्यान में रखें। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली की स्थिति के बारे में यह कहना चाहती हूँ कि मोनो रेल एक ऐसा कंसेप्ट है, जो कि हमें कम स्थान में सुविधा दे सकता है। दिल्ली के हम सात सांसद हैं और हम सबकी आपस में बात हुई कि सभी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या है। मैं आपके माध्यम से कंसर्न्ड मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वह मोनो रेल के कंसेप्ट को दिल्ली में इंटीग्रेट करे। दिल्ली सरकार इस विषय पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और दिल्ली की जनता भुगत रही है।

**श्री जयन्त बसुमतारी (कोकराझार) :** मैडम, आपने मुझे अपने क्षेत्र की समस्या को यहां रखने की सुविधा दी है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा क्षेत्र असम का कोकराझार कॉन्स्टीट्यूएन्सी है। उसमें एक रूपसी एयरपोर्ट है, जिसको 49 साल के बाद ऑपरेशनल किया गया है। वर्ष 2021 के बाद इसको ऑपरेशनल किया गया, लेकिन 7 नवंबर, 2023 से यहां पर फ्लाइट नहीं चल रही है। इसको फ्लाइबिग नाम की एक कंपनी ने ऑपरेशनल किया था, लेकिन वर्ष 2023 से यह बंद पड़ा है। यह क्यों बंद पड़ा है, इसका परसिविबल रीजन नहीं दिया गया है। अब इसको फिर से चालू करना है। अगर फ्लाइबिग इसको चालू नहीं कर पाती है तो इसको एयर इंडिया या इंडिगो कंपनी को चलाने के लिए विभागीय मंत्री से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। गुवाहाटी, रूपसी और कोलकाता चलता था, लेकिन अभी यह बंद पड़ा हुआ है। मैं मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको तुरंत चालू किया जाए।

**\*SHRI VISHWESHWAR HEGDE KAGERI (UTTARA KANNADA):** Honble Speaker sir, thank you for allowing me to raise a matter under Rule 377. Karnataka state has been progressing very well in various sectors in the country. Capital of Karnataka Bengaluru has also been achieving many milestones in IT-BT sector in the entire world. I would like to draw the kind attention of the Union government about serious irregularities by the State Government in our Karnataka. There are many issues including administrative negligencies in the various Departments of the state government. However, don't want mention all those issues in this occasion. I would like to mention one of the serious financial irregularities committed by the state government in the Valmiki Nigam, it's a Corporation which is functioning under the department of Welfare of Scheduled Castes. The Corporation is facing the allegations of its involvement in a major scam of Rs. 187 crores. The huge money was transacted from Valmiki Nigam and deposited in benami accounts. The fund of Rs.187 crores meant for welfare of my brothers and sisters of Scheduled caste and Scheduled Tribes. Rs. 187 crore rupees have been deposited in benami accounts through the Treasury of the Corporation. This money is collected from people in the form of taxes. Scheduled society as such huge amount of money is misappropriated in benami accounts without any use for them. The chief minister of Karnataka itself looking after the finance department. So it is an abuse of a system of governance. Because the government has agreed that the money has been transferred through the Treasury. Since the Chief Minister and his cabinet ministers of the government involved in the scam and money is transferred through banks, I request that the central government should take serious action against the culprits and give appropriate directions to bring administrative reform in the state of Karnataka.

(1325/VR/MM)

**श्री सुखदेव भगत (लोहरदगा) :** सभापति जी, यह अत्यंत संवेदनशील और आदिवासी अस्मिता का प्रश्न है।

महोदया, भारत में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं, जिनकी धार्मिक परम्परा, पहचान, आस्था और उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा हनन किया जा रहा है। क्योंकि जनगणना कॉलम में, जैसे अन्य धर्मों के लिए कॉलम दिया गया है, आदिवासी जो कि प्रकृति के पुजारी होते हैं, उनकी धार्मिक आस्था और परम्परा के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। एक तरफ तो सरकार जंगली जानवरों की, बाघ और शेरों की गिनती करती है, लेकिन आदिवासियों की धार्मिक पहचान, जो कि प्रकृति के पुजारी हैं, उनकी गणना नहीं करती है। इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है? इसलिए आपके माध्यम से देश की सर्वोच्च पंचायत से निवेदन करता हूँ कि आदिवासियों की पहचान, उनकी धार्मिक अस्मिता की रक्षार्थ जनगणना कॉलम में सरना धर्म को अंकित किया जाए। मैं पहली बार झारखंड के लोहरदगा से निर्वाचित होकर आया हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आसन का आभार प्रकट करना चाहता हूँ।

**CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA):** Thank you, hon. Chairperson, for giving me an opportunity to speak on this very important matter of urgent public importance. I am a first-time Member of Parliament from South Goa. The whole world knows Goa as the most beautiful place, a paradise on earth. But in the last few years, we have seen that a conspiracy is being done by thrusting several projects on Goa without taking the people into confidence. In 2016, they took our six rivers in the name of nationalization. Thereafter, during COVID-19 lockdown, they brought railway line projects, like double-tracking project, expansion of roadways and the Tamnar Transmission project. We have with us the documentary proof that the purpose behind all this is to bring out coal and convert Goa into a coal hub. Madam, after liberation of Goa in 1961 from the Portuguese rule, the only organized sector which is remaining today is the tourism sector because ban on mining in the State took place in 2012. The Agriculture Department is not doing that well. There have been efforts by youth, the private players to revive agriculture in the State. A humble request to this Government is to take the people of Goa into confidence, and not to convert Goa into a coal hub because the only sector which is giving employment to the people of Goa is tourism. Converting Goa into a coal hub will destroy Goa completely. Thank you, Madam.

(1330/YSH/SAN)

**\*SHRI JAGADISH CHANDRA BARMA BASUNIA (COOCHBEHAR):** Honourable Chairperson, through you I would like to raise a matter before the Honourable Railway Minister. Our Cooch Behar is the deemed as the city of kings. New Coochbehar Railway Station is operational in the service of the commuters. The rail line that connects New Coochbehar Railway Station with Alipuraduar- adjacent to the Alipuraduar Main Road has a level crossing where commuters get stuck for many hours. To address this issue, the Railway department had initiated the work to construct a Railway overbridge, but the work has been stalled for a long time. If the Railway Ministry informs us why the work has been stalled and can take measures to escalate the work, that would suffice. I am making this appeal to the Honourable Railway Minister to look into this matter. Secondly, there is a railway line that starts from Coochbehar and goes to Rangpur, Bangladesh via Dinhat and via Bamanhat. After the independence of Bangladesh in 1971, the Rail line has been non-functional and a part of the rail bridge has broken down as well. If the Honourable Railway Minister reconstructs the railway route and if it can be extended to Kolkata via Rangpur, Bangladesh- the distance between Kolkata or Southern India or Western India from the Eastern part of India will be reduced by 300-400 kilometres. Thus, I request the Honourable Railway Minister to conduct an overhaul of the said railway line so that it becomes possible to commute through Bangladesh via Sealdah, Kolkata to Southern and Western parts of India.

---

\* Original in Bengali

**LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Omprakash Bhupalsinh <i>Alias</i> Pavan Rajenimbalkar	Shri Shrirang Appa Chandu Barne
Prof. Varsha Eknath Gaikwad	Shri Omprakash Bhupalsinh <i>alias</i> Pavan Rajenimbalkar Shri Shrirang Appa Chandu Barne
Shri Rajkumar Roat	Shri Omprakash Bhupalsinh <i>Alias</i> Pavan Rajenimbalkar
Shrimati Kamaljeet Sehrawat	Shri Jagdambika Pal
Dr. Dharamvira Gandhi	Adv. Chandra Shekhar
Shri Hibi Eden	Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Shri D. M. Kathir Anand	Kumari Sudha R. Dr. T. Sumathy <i>alias</i> Thamizhachi Thangapandian Shrimati Supriya Sule

**माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) :** माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि बहुत सारे नए सदस्य बोलना चाहते थे, काफी सदस्यों का सूची में नाम था, लेकिन समय की कमी के कारण उनको आगे अवसर दिया जाएगा।

सभा की कार्यवाही दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

1333 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

(1430/RAJ/SNT)

1430 बजे

लोक सभा चौदह बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।  
(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुई)

### नियम 377 के अधीन मामले

1430 बजे

माननीय सभापति : नियम 377 के अधीन मामले।

#### Re: Various railway related issues in Maharashtra

**डॉ. हेमंत विष्णु सवरा (पालघर) :** सभापति महोदया, मैं मुंबई से वसई विरार और दहानु तक रेलवे विकास कार्यों में तेजी लाने का निवेदन करना चाहता हूँ। मुंबई से वसई, विरार और दहानु तक लोकल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में मुंबई और दहानु के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन की फ्रिक्वेंसी 1-1 घंटे के बाद की है। इसे कम से कम 30 मिनट के अंतराल में या इससे कम किया जाना चाहिए। बोरिवली से विरार के बीच तीसरी और चौथी लेन का काम शुरू हो चुका है, परंतु इसकी रफ्तार बहुत ही धीमी है। इन कामों में तेजी लाया जाना चाहिए। मुंबई से वसई - विरार और दहानु तक कई जगहों पर एफओबी, आरओबी, सबवे और रेलवे क्रॉसिंग बनाने की आवश्यकता है। इसका सर्वे करवा कर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाना चाहिए। पालघर रेलवे स्टेशन को रेलवे मंत्रालय द्वारा 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के लिए चुना गया था। इसका मास्टर प्लान जल्द से जल्द तैयार कर यात्री सुविधाओं का काम शुरू किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ की पालघर रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्यों पर अब तक कितनी प्रगति हुई है और सभी कार्यों को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है... (व्यवधान) (इति)

**माननीय सभापति :** श्री जगदम्बिका पाल – उपस्थित नहीं।

श्री कृपानाथ मल्लाह।

#### Re: Need to start new train services between Bairabi to Guwahati in Karimganj Parliamentary Constituency

**SHRI KRIPANATH MALLAH (KARIMGANJ):** In my Parliamentary Constituency Karimganj, the people living in the remote area of the Hailakandi district bordering Mizoram are totally deprived from getting the cheapest and safest transportation facilities of train. As this is the only transportation for the people residing there, it will be a very big benefit for students, patients and daily workers who travel for their daily needs. Further, it is felt very much necessary for a new train service one day/two days in a week from Guwahati to Bairabi and Bairabi to Guwahati. Therefore, I urge upon the hon. Minister of Railways to arrangements to make consider the commencement of one new train service from Bairabi to Guwahati and Guwahati to Bairabi respectively. (ends)

**माननीय सभापति :** श्री अनन्त नायक जी – उपस्थित नहीं।

डॉ. विनोद कुमार बिंद जी।

**Re: Expansion of platform of Gyanpur Road Railway Station and construction of railway underpasses**

**डॉ. विनोद कुमार बिंद (भदोही) :** सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र भदोही के अंतर्गत ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर एक छोटा है। ट्रेन प्लेटफार्म से बाहर तक पहुंच जाती है जिससे रेल यात्रियों को ट्रेन में बैठने और उतरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन से दिल्ली मुंबई और कोलकाता सहित कई क्षेत्रों के लिए ट्रेनों का आवागमन है। ऐसे में प्लेटफार्म का विस्तारिकरण होना आवश्यक है और ककराही रेलवे क्रॉसिंग पर अंडर पास बनना है। अतः इस रेलवे क्रॉसिंग से होकर रोजाना बड़ी संख्या में देश-विदेश के श्रद्धालु माँ विन्ध्यवासिनी धाम और मैहर धाम आते जाते हैं। साथ ही हजारों की संख्या में प्रत्येक दिन स्थानीय लोगों का आवागमन भी जनपद मिर्जापुर समेत मध्य प्रदेश की तरफ का होता है। ककराही रेलवे क्रॉसिंग से होकर बड़ी संख्या में ट्रेन गुजरती है। ऐसे में क्रॉसिंग अधिकतर बंद रहती है जिससे लंबा जाम लग जाता है। अगर ककराही रेलवे क्रॉसिंग पर अंडर पास बनता है तो रोजाना कई हजार वाहन चालकों के आवागमन में समय की बचत होगी और सराय कंसराय, हरदुआ रेलवे क्रॉसिंग पर अंडर पास सराय कंसराय और हरपुर यह गांव ऐसे हैं जहां रेल पटरी के किनारे बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में रेलवे क्रॉसिंग जो बनाई गई है वह काफी दूर है जिससे ग्रामीणों को रेलवे पटरी क्रॉस करने के लिए कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता है आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शिक्षा का अध्ययन करने रोजाना जाते हैं और बहुत मरीज अस्पतालों की तरफ जाते हैं। अतः आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि तीनों जगह शीघ्र कार्य करने की कृपा करें।

(इति)

(1435/VB/AK)

**Re: Need to create flood control centres in all districts of Uttar Pradesh**

**श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) :** आज मैं सदन का ध्यान उत्तर-प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित 22 जनपदों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बाढ़ के कारण आम लोगो के जीवन, खेत-खलियान, श्रम, शिक्षा आदि पर नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। अगर सिद्धार्थनगर की बात करे तो अब तक 400 से ज्यादा गाँव बाढ़ से प्रभावित है, जैसे कि खजूरडाड, लाउखाई, कालभीरोना आदि। इन सब के अलावा बाढ़ से हुए जनहानि के कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर जोखिम के आधार पर देखें तो- • उच्च = 51-100, • मध्यम = 11-55 तथा • कम जोखिम में = 10 से कम पिछले पांच वर्षों में बाढ़ के कारण जनहानि दर्ज की गई है। इसमें राज्य सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा तथा प्रभावित लोगों से मुलाकात करना किया गया है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि राज्य में केंद्र की तरफ से सर्वे करवाया जाये जो कि बाढ़ के मूलभूत कारणों व समाधानों का एक विस्तृत विवरण दे, राज्य में प्रत्येक जिले में 'Flood Control Centres' का गठन किया जाये तथा सभी बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाये ताकि वे इस आपदा कारण विकास की इस दौड़ में अपने आप को पिछड़ा महसूस ना करे।

(इति)

**Re: Upgradation of immigration and other facilities at Shamsabad Airport**

SHRI MADHAVANENI RAGHUNANDAN RAO (MEDAK): Shamsabad airport is located near Hyderabad and it serves Telangana, parts of Karnataka and Andhra Pradesh. It is an international airport which serves multiple States. There are lakhs of workers from Telangana in the Gulf and Middle East. There is intense traffic between Hyderabad and the Gulf. Hyderabad is also one of the most important centres of software development and exports from India. Air Traffic has been increasing steadily from Hyderabad. There is a need to upgrade immigration and other facilities at Shamsabad airport to reduce delays and crowding. Traffic volumes have increased and comparable immigration counters and personnel are needed. The Government should also consider over-night facilities for the Telangana Gulf workers who get stranded at night due to delays.

(ends)

(1440/PC/UB)

**Re: Need to promote tourism in Kangra Parliamentary Constituency**

**डॉ. राजीव भारद्वाज (काँगड़ा) :** मैं काँगड़ा लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचित हो कर आया हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे नियम 377 के अंतर्गत मेरे लोक सभा क्षेत्र काँगड़ा-चम्बा में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अपना विषय सदन के समक्ष रखने का अवसर दिया।

खूबसूरत घाटियाँ स्वर्ग से कम नहीं हैं, इसकी सुंदर घाटियाँ पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। पहाड़ों से गिरते झरने सबका मन मोह लेते हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। यह देव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भारी संख्या में देश एवं विदेशों से सैलानी आते हैं। ज़िले की अधिकतर आबादी टूरिज्म पर निर्भर है।

सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन का प्रत्यक्ष योगदान 2025 तक 7.2% प्रति वर्ष बढ़कर आईएनआर 5,339.2 बिलियन (जीडीपी का 2.5%) होने की उम्मीद है।

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि:-

1. पर्यटन की दृष्टि से पर्यटकों के लिए हेली टैक्सी के सेवा शुरू होनी चाहिए जिसके लिए रक्कड़ हेलीपोर्ट को विकसित करना आवश्यक है।
2. काँगड़ा घाटी रेल जो कि पठानकोट से जोगिंदर नगर तक चलती है, इसका ब्रॉडगेज करना तथा पठानकोट से डलहौजी-खजियार-चम्बा तक के लिए एक नयी रेलवे ब्रॉडगेज लाइना।
3. काँगड़ा-चम्बा ज़िलों में स्थित प्रसिद्ध मंदिरों-शक्तिपीठों को जोड़ने हेतु एक धार्मिक कॉरिडोर बनवाया जाये।
4. धौलाधार हिम शृंखला लैप तक पहुंचने के लिए रोपवे का निर्माण।
5. डलहौजी-खजियार-चम्बा के लिए टू-लेन रोड कनेक्टिविटी।
6. वंदे भारत ट्रेन के लिए अंब रेलवे स्टेशन से धर्मशाला-पालमपुर के लिए से पर्यटक वॉल्वो बसें।
7. पर्यटक स्थल जैसे भागसुनाग, मैक्लोडगंज, नड्डी, चर्च, डल झील, इंद्रुनाग, धर्मकोट में सार्वजनिक सुविधाएं विकसित करनी बेहद जरूरी हैं।
8. भारी संख्या में लोग यहाँ चामुंडा देवी मंदिर, ज्वाला जी मंदिर, दर्शन करने हेतु आते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि मंदिरों को शक्तिपीठ के नाम से विकसित करवाया जाए।
9. पर्यटन की दृष्टि से ज़िले में स्थित पौंग बांध में जल खेल पर्यटन, शिकारा/सौर हाउस बोट शरू करने से पर्यटकों कि संख्या में भारी इजाफा होगा।

अतः मेरा माननीय पर्यटन मंत्री जी से अनुरोध है कि ज़िले में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विचार कर शुरू करने कि कृपा करें।

(इति)

**माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) :** डॉ. के. सुधाकर – उपस्थित नहीं।  
श्री राजकुमार चाहर जी।

... (व्यवधान)

**Re: Development of Bateshwar in Agra as a tourist destination.**

**श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) :** आगरा का बाह तहसील क्षेत्र, जो यमुना नदी के किनारे व चम्बल नदी किनारे के मध्य में बटेश्वर बसा है, वह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे मार्ग से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर्यटन की दृष्टि से चम्बल में पक्षी व घड़ियाल पर्यटकों के लिये आकर्षण का केंद्र है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेई जी का पैतृक गाँव बटेश्वर है, जो यमुना नदी के किनारे भगवान ब्रह्मलाल महाराज शिव मंदिर (जो तीर्थों के भांजे) माने जाते हैं। वहीं 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमीनाथ जी जो कि भगवान कृष्ण के पिता श्री बासुदेव जी के चचेरे भाई का गाँव व तीर्थ क्षेत्र बटेश्वर (शौरीपुर) भी यहीं है। बटेश्वर में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की विशाल और दर्शनीय प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। इस प्रतिमा का उद्देश्य न केवल बाजपेयी जी की स्मृति को संजोना है, बल्कि एक आकर्षण का केंद्र बनाना भी है। जिससे इस ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगी। बटेश्वर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को संरक्षित करते हुए इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत को भी जीवंत रखेगी। (इति)

(1445/CS/SRG)

**Re: Problem of water logging in NCT of Delhi**

**श्री योगेन्द्र चांदोलिया (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) :** महोदया, दिल्ली में जल निकासी व्यवस्था और जल जमाव की बिगड़ती स्थिति और इसके परिणामस्वरूप हमारी राष्ट्रीय राजधानी में जल निकासी व्यवस्था बदहाल है, नालियाँ जाम हैं, सीवेज ओवरफ्लो हो रहा है और जलजमाव एक स्थायी समस्या बनती जा रही है। बारिश के समय जलजमाव की स्थिति और भी विकराल रूप ले लेती है। हाल ही में जलजमाव के कारण ही दिल्ली के व मेरे ही उत्तर पश्चिम लोक सभा संसदीय क्षेत्र में कई लोग जान गवां चुके हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के किराड़ी में जलजमाव के कारण करंट लगने से हादसा हुआ और एक नौजवान की मृत्यु हो गयी।

मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस मामले को गंभीरता से लें क्योंकि दिल्ली सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल रही है। दिल्ली के लोग असुरक्षित और अस्वस्थ परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं। इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई ठोस कार्रवाई करने की अनुकंपा करें।

(इति)



**Re: Inclusion of banana in the category of fruits.**

**श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) :** महोदया, मैं आज जलगांव लोकसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों, महाराष्ट्र राज्य और हमारे महान राष्ट्र के संपूर्ण कृषक समुदाय की सामूहिक मांग को आवाज़ देने के लिए खड़ी हुई हूँ।

बहुत लंबे समय से, लाखों भारतीयों के लिए एक मुख्य फल, केले को फलों की श्रेणी में उसका उचित स्थान नहीं दिया गया है। इस अनदेखी के कारण हमारे मेहनती किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जो हमारे खाने की मेज पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए अथक परिश्रम करते हैं।

भारत के लोग अपने किसानों के लिए न्याय की मांग करते हैं! हम मांग करते हैं कि केले को एक फल के रूप में मान्यता दी जाए और अन्य फलों के समान लाभ और समर्थन दिया जाए।

यह मान्यता केवल शब्दार्थ का मामला नहीं है, इसके वास्तविक दुनिया के निहितार्थ हैं। केले को फलों की श्रेणी में शामिल करने से हमारे किसानों को बेहतर बाज़ार, मूल्य और प्रोत्साहन मिलेंगे। इससे उनकी आजीविका में सुधार होगा, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और हमारे राष्ट्र के विकास में योगदान मिलेगा।

मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि वह लोगों की आवाज़ सुनें और केले को फलों की श्रेणी में रखने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। आइये हम सब मिलकर अपने किसानों को सशक्त बनाने और देश की रीढ़ - कृषि को मजबूत करने के लिए काम करें। धन्यवाद।

(इति)

(1450/RCP/IND)

**Re: Need to constitute DISHA Committees in the Districts and convene regular meetings under the Chairmanship of Members of Parliament**

DR. JAYANTA KUMAR ROY (JALPAIGURI): Madam, the District Development Coordination and Monitoring Committees (DISHA committees), which are essential for monitoring various Government of India programmes and promoting synergy and convergence among stakeholders, have not been constituted in several districts. According to the DISHA guidelines of 2022, district-level DISHA meetings should be held at least once every quarter. However, it has come to light that no such meetings have been convened in many of the districts of West Bengal. In a letter dated January 1, 2024, from the SRD to the Chief Secretaries of the States and UTs, it was noted that 22 districts in West Bengal have not held a single DISHA committee meeting since April 2022. The absence of these meetings hinders the collaboration between local and national representatives and authorities, negatively affecting the review of public works, quality expenditure, optimization of public funds, and programme implementation monitoring. Therefore, I request the hon. Minister of Rural Development to issue strict instructions to the concerned District Collector/Magistrate/Deputy Commissioner to take the necessary steps to constitute DISHA committees in the districts and convene regular meetings under the Chairmanship of Members of Parliament.

(ends)

### **Re: Measures undertaken to check floods**

**श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा) :** महोदया, ना सिर्फ मेरा संसदीय क्षेत्र दरभंगा अपितु उत्तर बिहार की आठ करोड़ आबादी को प्रति वर्ष बाढ़ की भीषण समस्या का सामना करना पड़ता है।

महोदया, सर्वप्रथम मैं देश के आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु आवश्यक पहल प्रारंभ हो चुकी है और केन्द्रीय जल आयोग के द्वारा कमिटी का गठन भी किया गया है। बाढ़ से स्थायी समाधान हेतु पड़ोसी देश नेपाल सरकार का इस विषय पर सकारात्मक रुख आवश्यक है और इस दिशा में हमारी सरकार ने आवश्यक पहल भी की है। नेपाल से आने वाली नदियों के उदगम स्थानों पर हाई डेम निर्माण ही इस समस्या का स्थायी समाधान होगा। हम सभी को इस वाक्य पर पूर्ण भरोसा है "मोदी है तो मुमकिन है" निश्चित रूप से उत्तर बिहार बाढ़ की समस्या से मुक्त होगा।

(इति)

(1455/PS/GG)

### **Re: Need to fill up the vacancies of loco pilots in various railway zones**

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): The loco pilots drive trains over long distances, far from home, and are often pressed into duty without adequate breaks and this causes great stress and lapses in concentration which is a major cause of train accidents in the country and this has been acknowledged by the Railways in multiple reports. The loco pilots have been demanding a weekly rest of 46 hours. They also demand that two consecutive nights of duty should be followed by one-night rest and trains should have basic amenities for drivers. Over the past four years, the Railways Recruitment Board has not recruited even a single loco pilot despite tens of thousands of vacancies. Shockingly, the country has been witnessing frequent train accidents, and the recent one occurred was on 17.6.2024, killing more than 15 people on board, near Jalpaiguri. This happened just one year after a major train accident involving three trains at Balasore, which killed more than 300 people on 02.6.2023. Therefore, I urge upon the Government to fill up thousands of vacancies of loco pilots on a time-bound basis as well as all other vacant posts of all Railway Zones relating to the safe running of trains in the country.

(ends)

## **Re: Development of new airports in Telangana**

SHRI RAMASAHAYAM RAGHURAM REDDY (KHAMMAM): Presently, Telangana has only one functional airport – Rajiv Gandhi International Airport at Shamshabad on the outskirts of Hyderabad. The Telangana Government is actively pursuing the development of three new greenfield airports and the revival of three existing brownfield airports. The three new airports are proposed to be established at Bhadradri Kothagudem, Jakranpally in Nizamabad District and Mahabubnagar. Similarly, the existing airports in Warangal Urban District (Mamnoor village), Basanthnagar in Peddapally District, and Adilabad District are being revived.

Currently, the international airport at Shamshabad on the outskirts of Hyderabad is Telangana's primary civil aviation facility. Demands for some more airports have arisen due to the long distance of the State capital from the proposed districts. The Airports Authority of India (AAI) had conducted a Techno-Economic Feasibility Study (TEFS), an Obstacle Limitation Surfaces (OLS) survey, soil testing and other tests for all the six sites and submitted the reports. The construction work on these sites would begin once the AAI and the Ministry of Civil Aviation give all the necessary clearances. Hence, I would like to request the hon. Minister for Civil Aviation to issue the necessary clearances and to expedite the works of the proposed six airports in Telangana.

(ends)

## Re: Utility of smart meters for Mumbai

**प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुंबई उत्तर-मध्य) :** केंद्र सरकार ने बिजली वितरण संगठनों को आरडीएसएस योजना अर्थात् रीवैम्प डेवलपमेंट सेक्टर स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी के रूप में धनराशि स्वीकृत की है। मैं मुंबई शहर का प्रतिनिधित्व करती हूँ। यह 120 साल पुरानी B.E.S.T. मुंबई नगर निगम की एक पहल है। आरडीएसएस योजना के तहत BEST को 3500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। BEST मुंबई शहर को बिजली की आपूर्ति करती है। इसे स्वचालित और आधुनिक बनाया जाना चाहिए। इसके लिए फंडिंग उचित है।<sup>1</sup>

मुंबई के लिए स्मार्ट मीटरिंग कितना जरूरी है, अगर BEST के आंकड़ों पर नजर डालें तो बिजली बिल रिकवरी 99% है और बिजली लॉस 5% से कम है। दोनों नंबर पूरे देश में सर्वोत्तम हैं। बिजली लीकेज, बिजली चोरी रोकने और बिजली बिल वसूली में तेजी के लिए स्मार्ट मीटर की जरूरत है। लेकिन BEST की रिकवरी अच्छी है और बिजली लीकेज कम है, तो जरूरत न होने पर भी स्मार्ट मीटर लगाना उचित है? स्मार्ट मीटर की कीमत 13,000 रुपये है। भारत सरकार इस पर केवल 15% सब्सिडी देगी। सिंगल फेज उपभोक्ता मीटर 1300 का है। तो क्या इतना महंगा मीटर लगाना उचित है? स्मार्ट मीटर लगाने का 1800 करोड़ का ऑर्डर अडानी ग्रुप को दिया गया है। BEST के कर्मचारी स्वयं मीटर लगाने और बदलने में सक्षम हैं।

(इति)

(1500/MY/SMN)

**Re: Rising cases of Anaemia among women and children**

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NAGAON): There has been a concerning rise in anaemia amongst women and children in recent years. According to NHFS-5 data, anaemia amongst women aged between 15 and 49 has risen by nearly 20 percentage points, compared to NHFS-4. Nagaon and Morigaon districts in my constituency too have witnessed steep rises in the prevalence of anaemia amongst women in this age group. In pregnant women, anaemia can lead to premature deliveries and higher maternal and infant mortality rates. Overall, it reduces individuals' productivity, increases susceptibility to infections and hampers one's recovery from illness.

I therefore urge the Government to address this matter immediately and adopt a wide approach to this issue. Since anaemia is more prevalent amongst women than men, I urge upon the Government to conduct studies into whether this arises from gender inequalities in household food consumption and access to iron-rich foods. I also urge upon the Government to include targeted social interventions for women and girls in Assam, under the community mobilisation activities through the Anaemia Mukht Bharat scheme. Lastly, the Government should strengthen surveillance systems for the collection of anaemia-related data to ensure a regular flow of information to policy-makers.

(ends)

**Re: Development of Greenfield airport at Sabarimala  
in Kottayam District, Kerala**

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): I request the Government to kindly expedite the procedures for granting approval to the Greenfield Airport near Sabarimala, Kottayam District, Kerala. It is learned that the environmental clearance is pending before the Central Government. Sabarimala, one of the largest pilgrim centres, is located adjacent to the proposed airport, where more than four crore devotees of Lord Ayyappa pay homage every year. The proposed airport will be a blessing to NRIs as well. A large chunk of the NRI population from Kerala is within a radius of 30 kilometers from the proposed airport. The proposed airport will be a boost for the transportation and export of commercial and agricultural crops and will also help in the promotion of tourism destinations in Idukki, Kottayam, Kollam and Pathanamthitta Districts. Therefore, I request the Government to kindly expedite the procedures to grant all required clearances to the Sabarimala airport in Kerala.

(ends)

(1505/NKL/CP)

**Re: Implementation of Coastal Regulation Zone (CRZ) in Kerala**

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): I would like to point out a serious concern affecting one of the most marginalized sections of our country: the fishermen, in relation to the complex and inconsistently enforced Coastal Regulation Zone (CRZ) regulations in coastal regions particularly in Kerala. The regulations limit fishermen's access to traditional fishing grounds and restrict activities essential for their livelihood. There is widespread anxiety within these communities about potential displacement due to CRZ norms. Fishermen, who have lived in coastal areas for generations, are worried about being forced to relocate if their homes and settlements are deemed illegal under the new regulations. Additionally, infrastructure development in coastal areas is being severely hampered by these regulations. The construction of necessary facilities like fish landing centres, storage units, and processing units, which are crucial for the fishing industry, is being affected. They face potential fines and the need to invest in alternative, compliant infrastructure, which adds to their financial burden. For a community already struggling with various challenges, these additional costs can be overwhelming. It is imperative that we address these concerns and work towards a more balanced approach that protects the environment while also safeguarding the livelihoods of our fishermen.

(ends)

**Re: Problems faced by weavers in Eastern Uttar Pradesh**

**श्री राजीव राय (घोसी) :** उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा अपनी बुनाई उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। सैकड़ों वर्षों से अधिक चली आ रही बारीक और जटिल बुनाई की विरासत है। इस क्षेत्र के अधिकांश लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए बुनाई के पेशे से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में बुनकरों की स्थिति दयनीय है, और उनके लिए अपने जीवन यापन की आवश्यकताओं को पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। पिछले 6 से 7 वर्षों में सरकारी नीतियों ने बुनकरों को किनारे पर ला दिया है। अत्यधिक और कठोर श्रम, पूंजी निवेश और विशेषज्ञता के बावजूद, बुनकरों को उनके कठिन परिश्रम के लिए अपर्याप्त प्रतिफल मिलता है। जीएसटी के लागू होने से बुनकर समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वे जीएसटी का भुगतान करते हैं, लेकिन उन्हें इसके बदले में पर्याप्त बुनियादी ढांचा और अन्य सरकारी समर्थन नहीं मिलता है। बिजली की आपूर्ति अत्यधिक अपर्याप्त और अत्यधिक अनियमित है। फ्लैट स्लैब दर की समाप्ति के साथ, कुछ बुनकरों का बिजली बिल लगभग दस गुना बढ़ गया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बुनकर समुदाय की दुर्दशा पर ध्यान दें और उनकी कठिनाइयों और पीड़ाओं को कम करने के लिए उन्हें पर्याप्त सहायता और समर्थन प्रदान करें।

(इति)

(1510/VR/NK)

**Re: Desilting of Ganga river in Kasganj district, Uttar Pradesh**

**श्री देवेश शाक्य (एटा) :** महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र एटा (उ०प्र०) के जनपद कासगंज के तहसील पटियाली में गंगा नदी के किनारे लगभग 15-20 किलोमीटर के दायरे में बसे गांवों जैसे शहबाजपुर बरौना बरी बगबास, कादरगज पुख्ता इदा मिहौला नरदोली और मूंज खेडा, राजेपुर कुर्रा गांव जो प्रतिवर्ष बाढ़ और कटान से प्रभावित होते रहते हैं। वहां के सभी किसानों के लिए यह गंभीर समस्या है। बाढ़ के समय किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। कटान से भी किसानों एवं ग्रामवासियों को भारी आर्थिक क्षति होती है। यह समस्या मुख्य रूप से गंगा नदी के पेटी में गाद सिल्ट का जमा होना है। जिसके कारण गंगा नदी का रास्ता बरसात के समय रिहायशी इलाके की तरफ मुड़ जाता है। स्थानीय प्रशासन एवं सिंचाई विभाग रेत की बोरियां डालकर अस्थाई बचाव का प्रयास करती आ रही है जो समस्या का समाधान नहीं है। किसानों के प्रतिवर्ष काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस क्षेत्र में प्रभावित गांवों को स्थाई समाधान के लिए डीसिल्टिंग और बड़े पत्थरों की ठोकरी की व्यवस्था होनी चाहिये और गंगा नदी में प्रतिवर्ष आ रही बाढ़ और कटान से निदान दिलाने के लिए जल्द कोई कार्य योजना की अनुमति देने की कृपा करें।  
(इति)

**Re: Completion of Shyampur to Bagnan railway line in Uluberia Parliamentary Constituency**

SHRIMATI SAJDA AHMED (ULUBERIA): I would like to draw the kind attention of the Government towards a long-pending demand of the people of my Parliamentary Constituency, which pertains to the Ministry of Railways. The proposal for a new railway line from Shyampur to Bagnan has been pending for a significant period, despite a survey conducted by the previous Government. I have raised this issue several times in the Parliament, yet no action has been taken by the current government. Shyampur, located in the territorial area of my constituency, currently relies solely on road connectivity. Residents are forced to travel 40 to 50 kilometres to reach the nearest railway station, causing considerable hardship. Moreover, the region includes notable tourist spots such as Gadiara and Garchumuk which would greatly benefit from improved railway access. The establishment of this railway line would not only alleviate the daily struggles of the local population but also promote tourism in the area, thereby contributing to the region's economic development.

I earnestly request the Government to prioritize this issue and expedite necessary actions for the completion of the Shyampur to Bagnan railway line.

(ends)

**Re: Soil erosion caused by Ganga River**

SHRI KHALILUR RAHAMAN (JANGIPUR): Ganga, the major river that flows through Murshidabad district, plays a major role in the financial and agricultural sectors. Ganga erosion is a major concern for the people of Murshidabad district, especially of Lalgola, Raghunathganj-II, Suti-1 and Samserganj Block. The most affected areas in Samserganj Block are Nurpur GP and Giria GP of Suti -1 block. Lots of houses, schools, temples, mosques, and crematoriums on the bank of the river have no trace left. In August 2020, nearly after 50 years, this region faced such a huge erosion which washed away dwelling places, temples, schools, litchi and mango orchards, and agricultural lands right along the river bank. More than 1,10,000 households have been identified as vulnerable to Ganga erosion. Erosion is a serious issue that needs urgent intervention. People are petrified and losing their last hope to live as they lost everything they had. I strongly demand that a permanent action should be taken to stop erosion caused by the Ganga. Along with that, I would appeal the Government to rehabilitate those homeless people who have lost everything due to erosion. The Farakka Barrage project has huge pieces of vacant land in which families who have lost their homes can be rehabilitated. Thank you.

(ends)

(1515/SK/SAN)

... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री संध्या राय) : माननीय सदस्य, आपका विषय रिकॉर्ड में आ गया है।  
श्री डी. एम. कथीर आनंदा

... (व्यवधान)

**Re: Construction of RoB at level crossing no. 81 New Town Vaniyambadi**

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Hon. Chairperson, Madam, the RuB/RoB at the level-crossing LC81 New Town in Vaniyambadi has to be constructed for the benefit of the people living in Vaniyambadi. I have raised this issue several times before, since 2019, but the Railway authorities have not fulfilled this long pending demand so far. The LC81 crossing is the only access point for those entering the town from the national highway. As more than 120 trains cross the area in both directions, it resulted in the gate being closed frequently and people living on both sides of the LC are finding it extremely hard to cross this gate. The tender too was finalised and work allotted with a promise of the RoB becoming operational in 18 months. The level crossing was closed for work on September 11, 2017 and a 20 feet trench was dug at the spot after which the work stopped completely. Even after repeated requests, the construction of the RoB has not been done. The people from all walks of life at Vaniyambadi are demanding for this RoB at LC81 for almost a decade. Therefore, I urge upon the Union Government to ensure the construction of the RoB at LC81, New Town Vaniyambadi immediately. ... (Interruptions)

(ends)



## Re: Development of Polavaram irrigation project in Andhra Pradesh

SHRI KESINENI SIVANATH (VIJAYAWADA): Hon. Chairperson, Madam, the Polavaram Irrigation Project is a true national project that will benefit six States in India. This project witnessed remarkable progress under the leadership of Chandra Babu Naidu. By 2019, an impressive 71.93 per cent of the civil works and 18.66 per cent of land acquisition and resettlement had been completed. However, from 2019 until May 2024, during the tenure of previous Government in Andhra Pradesh, only 3.84 per cent of civil works and 3.89 per cent of land acquisition tasks were accomplished. Now, with a mission-mode approach, the current Andhra Pradesh Government has taken decisive steps to get the Polavaram project back on track. The Chief Minister has declared every Monday as Polavaram Day, ensuring his personal visit to the project site. This approach promises accelerated progress and timely completion.

Thus, we earnestly urge upon the Central Government to release sufficient funds for the development of this critical project. ... (*Interruptions*) The Polavaram project is more than just infrastructure; it is the lifeline that will fuel the growth and future of Andhra Pradesh.

(ends)

(1520/MK/SNT)

## Re: Inclusion of Saran Bandh in National Highways

**डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज)** : सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में स्थित सारण बांध, जो सोनपुर से शुरू होकर सारण, गोपालगंज होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा सिसवां तक जाता है। सारण जिले के सोनपुर से डुमरिया घाट पुल तक के मार्ग को नेशनल हाइवे में शामिल कर लिया गया है, जबकि डुमरिया से सिसवां यूपी बोर्डर तक या पश्चिमी चंपारण को जोड़ने वाले मंगलपुर पुल तक बचे हेतु सारण बांध को अभी तक एन.एच. में शामिल नहीं किया गया है। बांध को भी राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल कर लिया जाता है, तो इससे इस क्षेत्र की 28 लाख जनता के विकास की नवीन ऊर्जा का संचार तो होगा, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से राजधानी पटना से निर्बाध एवं त्वरित संपर्क स्थापित होने से निकटवर्ती कई जिलों में ही नहीं अपितु समस्त क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकेगा। उक्त परियोजना के माध्यम से इस परिक्षेत्र में स्थित नारायणी नदी पर पर्यटन का विकास होगा। सड़क परिवहन बल्कि जलमार्ग से भी व्यावसायिक परिवहन को कई गुना बढ़ा देगा। इससे रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे तथा हर वर्ष आने वाली बाढ़ और उससे होने वाले जल भराव एवं कटाव की समस्या पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। मैं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि डुमरिया से सिसवां यूपी बोर्डर तक या पश्चिमी चंपारण को जोड़ने वाले मंगलपुर तक बचे हुए सारण बांध को नेशनल हाइवे में सम्मिलित किया जाए।

(इति)

### **Re: Safety of Passengers travelling in local trains in Mumbai**

SHRI ANIL YESHWANT DESAI (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Mumbai is the financial capital of the country and local trains are the life line of Mumbai. Spread over 390 KM, the suburban railway operates 2,342 train services for more than 7.5 million commuters daily. This local train network is very vast and dependable but if we compare it with the population, we found it quite inadequate. During peak hours, it is almost a herculean task to enter any compartment or come out of it. Large number of passengers lost lives every year in local train accidents. About 2,590 commuters lost their lives on Mumbai's suburban rail network in 2023, averaging seven deaths daily. Trespassing falls from trains, and accidents involving gaps or poles are some primary causes, accounting for nearly five fatalities daily. Sometimes commuting in Mumbai locals is equals to a warzone, given the higher death rate compared to soldiers on active duty in other cities. Coming to college or going to work is like going to war, as the fatalities are more than the number of soldiers dying in active duty. I, therefore, request railway authorities to ensure the safety of passengers and ensure comfortable journey for lakhs of local trains passengers in Mumbai.

(ends)

### **Re: Sanction of a dedicated entry and exit point at Mithaki Mahua in Gaya District under Bharatmala Project**

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : सभापति महोदया, भारतमाला सड़क परियोजना मेरे संसदीय क्षेत्र से 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहा है। यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के कई धार्मिक स्थल देव, गजनीधाम और श्रावणी मेला, बांके बाजार है, जिसमें हजारों-हजार की संख्या में लोग दूर-दूर से आते हैं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक उतार और चढ़ाव (डेडिकेटेड पॉइंट) मेरे संसदीय क्षेत्र में गाँव तारचुआँ के समीप मिठाकी महुआ, प्रखंड डुमरिया, जिला गया नामक स्थान पर स्वीकृत किया जाना चाहिए। इस प्रकार उतार और चढ़ाव बन जाने से सभी धार्मिक स्थलों और पूरे क्षेत्र में लाखों लोगों को विकास की नई दिशा मिलेगी। अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी से जनहित में अनुरोध है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक उतार और चढ़ाव (डेडिकेटेड पॉइंट) मेरे संसदीय क्षेत्र में गाँव तारचुआँ, प्रखंड-डुमरिया, जिला-गया के समीप मीठाकी महुआ नामक स्थान पर स्वीकृत करने की कृपा करें।

(इति)

(1525/SJN/AK)

**Re: Problems faced by fishermen community in Tirupati Parliamentary Constituency**

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): The Tirupati Parliamentary Constituency has a coastal line of 75 kms. and Pullicat Salt Lake. There are nearly 20,000 fishermen residing in my Parliamentary Constituency. They are from very poor backgrounds and mainly depend on traditional fishing methods for their livelihood by using motorboats with 5HP engines and county craft.

For the past 20 years, they have been facing issues with the fishermen from the neighbouring States of Tamil Nadu & Puducherry. The fishermen from the neighbouring States are illegally entering the Reserved Zone with their heavy mechanized boats with engine capacity of 400 to 500 HP and are damaging the local fishermen's boats and nets. The fishermen from neighbouring States are not only causing financial damage but also attacking our fishermen with weapons (iron rods, iron balls, and chains). Many of our fishermen got injured during the attacks.

It is a sensitive law and order issue between two States. I would, therefore earnestly request the Union Government for prompt action in resolving long-standing issues and for the sustainable future of our fishermen community. (ends)

**Re: Setting up of a Cardiology Department in ESI Model and Super Speciality Hospital in Kollam, Kerala**

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The insured persons depend on ESI Model and Super Speciality Hospital in Asramam, Kollam, Kerala and are facing difficulty due to lack of infrastructure and qualified doctors in Super Speciality Departments.

The vertical expansion and allied infrastructure developments are kept idle. No progress has taken place in infrastructure development. There is deficiency of doctors, paramedical staff and manpower. The cardiology treatment has been stopped. The ESIC terminated the agency engaged for Cardiology treatment in PPP model. No alternate arrangement has been made. Other Super Speciality Departments are also facing difficulty due to lack of infrastructure development and manpower. The insured persons and their dependents are facing problems due to lack of infrastructure and manpower. Urgent action is required to resolve the issues.

Hence, I urge upon the Government to initiate action for infrastructure development and setting up of a Cardiology Department, appointment of super-speciality qualified doctors in Cardiology and other super-speciality Departments.

(ends)

(1530/UB/SPS)

**Re: Need for setting up of a mega steel plant in Keonjhar**

SHRI ANANTA NAYAK (KEONJHAR): Madam, Keonjhar is part of the mineral rich Singhbhum-Keonjhar Corridor bordering the south of Jharkhand and a large part of this Corridor falls in this district. This district has one of the largest and most developed iron ore reserves in Asia with the iron ore mineral reserve of 2,500 million tonnes much of which is exported by the Government. Despite being rich in natural resources like iron ore and other minerals, this district is highly backward and there are very few employment opportunities for the youth in this area due to which the youth have to migrate to other States for employment.

For optimum utilisation of availability of high-quality iron ore, there is a need to establish a mega steel plant in this district, which will not only lead to the all-round development of the district but it will also provide employment opportunities to the youth. The necessary infrastructure like port connectivity, railway connectivity, and national highway connectivity is well placed.

Therefore, I request the Government to take immediate steps towards setting up a mega steel plant in Keonjhar so that there can be proper development of this area and the employment related problem of the youth can be solved.

(ends)

1531 hours

(Hon. Speaker *in the Chair*)**Re: Problem of drought and depleting ground water level in Karnataka**

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): Sir, Karnataka experienced one of the most severe droughts in the year 2023. The droughts have had a profound impact on almost all the *talukas* within our State with small and marginal farmers being the most severely affected. In my constituency of Chikkaballapur, and in the neighbouring Kolar and Tumkur districts which have a significant farming population, people play a crucial role in providing sustenance to the urban city of Bengaluru. Unfortunately, the groundwater levels have witnessed a significant depletion over the years. The underground water has dropped as deep as 1,500 feet. It is imperative that we find a permanent solution to address this pressing issue.

Instead of finding a permanent solution, the State Government is trying to utilise the STP water and they are filling up the ponds and lakes in these districts. We do not know the effects of using the STP water. 80 lakh people are using water for their agriculture and drinking purposes. This may be one of the rare cases in the entire country that the STP water is being utilised to fill up the tanks and use this water for agriculture and drinking purpose. One potential solution could be the transportation of at least 5 tmc of water from the Krishna River to our region through construction of canals and completion of Yettinahole Project at the earliest. Also, special river catchment improvement plans have to be enabled for Palar, Ponnaiyar, and Pennar rivers. The basin, river banks and drainage of these rivers must be protected and desilting should be done. In addition, it is crucial to revitalize and restore the village ponds and other water structures in the area. Therefore, I earnestly request the Government to consider my request for finding a permanent solution to this crisis to save the lives of not just humans but also of animals and protect the flora and fauna of the region.

(ends)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, 377 के तहत जो लिखित में होता है, वही पढ़ा जाता है। मैं सभी माननीय सदस्यों से भी ऐसा ही आग्रह करता हूँ।

(1535/MM/SRG)

## RE: BUSINESS OF THE HOUSE

**माननीय अध्यक्ष :** नियम 193 के अधीन चर्चा।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, normally the Supplementary List of Business contains some matters which require urgent attention and discussion. Today, the topic under discussion is 'preparedness for the Olympics'. It is already over and the team has already left India. What is the scope of a discussion on this topic coming under a Supplementary List of Business in this House. It means the House is taken for granted. This is not fair on the part of the Government which is coming up with a topic which is insignificant and irrelevant because the entire preparedness is already over. The team has already left India. We will pray for their victory and we are all with them. But what is the scope of having a discussion under Rule 193 that too by way of Supplementary List of Business? It is quite unfortunate on the part of the Government coming with such a discussion. We have given so many notices on issues like Agniveer, NEET, etc. There are so many notices pending under Rule 193, but you are not taking up any of the notices. Taking up this notice as a Supplementary List of Business is not fair. That is our submission. ... (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** आप सभी का सपोर्ट है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन नियम 193 के तहत इसी विषय पर चर्चा आयी और सरकार ने भी इसी विषय पर सहमति दी। आप किसी अन्य विषय पर चर्चा दें या कॉलिंग अटेंशन पर भी आप चर्चा दें तो निश्चित रूप से मुझ से मिलें। मैं सरकार से बातचीत करके उन सभी विषयों को लिया जाएगा, जिनको आप महत्वपूर्ण समझते हैं। लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य श्री प्रसून बनर्जी कह रहे हैं कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय को लेना चाहिए।

## आगामी ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों पर चर्चा

1537 बजे

**डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) :** महोदय, आपने ओलम्पिक खेलों में भारत की तैयारी पर नियम 193 के तहत चर्चा पर आपने अनुमति दी है। इसके लिए मैं ही नहीं अपितु पूरा देश आपका आभार व्यक्त करता है।

महोदय, हम अपने विरोधी दलों की पीड़ा को भी समझ सकते हैं। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि पिछले पांच वर्ष के आपके अध्यक्ष के कार्यकाल में कई बार खेलों को लेकर चर्चा हुई है और उसमें खेलों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, कैसे 'फिट इंडिया' और 'खेलो इंडिया' की चर्चा की जाए? कैसे हम अपने खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान कर सकें? कैसे हम पदक जीत सकें? इस सबकी चर्चा करके हम संसद के माध्यम से अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। हमारे विरोधियों को बिलकुल ही नहीं लगेगा कि इस तरह की चर्चा आवश्यक है।

महोदय, हमने वर्ष 2009 में भी चर्चा देखी है। वर्ष 2009 में मैं जब पहली बार सांसद बना था। कॉमनवैल्थ गेम्स के समय मैंने देखा, प्रेमचन्द्रन जी भी थे, उस समय जो चर्चा यह करते थे, वह आज भी कर रहे हैं। मैं कॉमनवैल्थ गेम्स को याद नहीं करना चाहूंगा। पिछले 50 वर्षों से हम लोग ओलम्पिक खेलों को फॉलो करते हैं। विगत वर्षों में ओलम्पिक खेलों की तैयारियों के लिए किसी तरह का जोर नहीं दिया जाता था और उस तरह से कार्य भी नहीं होते थे। ओलम्पिक का मतलब होता था कि हम पदक जीते हैं या नहीं जीते हैं। इसके अलावा ओलम्पियन बन जाना ही इस देश के एथलीट्स की उपलब्धि होती थी। हम दूसरे खेलों पर चर्चा तक नहीं कर पाते थे। लेकिन आज भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक उत्साह और उमंग के साथ हमारे एनडीए के पहले बजट में स्पोर्ट्स के लिए 1219 करोड़ रुपये रखे गए थे। विगत दस वर्षों में 3397 करोड़ रुपये का बजट स्पोर्ट्स के लिए रखा है। इसके लिए हम माननीय प्रधान मंत्री जी का और केन्द्र सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं।

(1540/YSH/RCP)

भविष्य की तैयारी करना, भविष्य की योजनाओं के साथ भविष्य के खिलाड़ियों को निकालना ही किसी भी सरकार और देश का लक्ष्य रहना चाहिए। अगर हम कहें कि आज हम ओलंपिक पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक महीने पहले चर्चा हो रही है और एक महीने में हम पदक जीत कर ले आएंगे। इसके लिए वर्षों की तपस्या होती है। खिलाड़ियों की बचपन से इसके लिए तैयारियां रहती हैं। उसमें सरकार का प्रोत्साहन होता है। सीएसआर के तहत विभिन्न लोगों का प्रोत्साहन होता है। वे व्यक्ति, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही स्पोर्ट्स के प्रति डेडिकेट किया है, जैसे लोग जब बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, तब जाकर हम कहीं ओलंपिक की उस रेखा को पार कर पाते हैं, जिस रेखा को पार करने का आज यह सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

हमारा प्रयास है कि हम पोलियम पर अपना स्थान कैसे बनाएं। आज तक इसकी चर्चा कभी भी नहीं होती थी, लेकिन विगत वर्षों में चाहे वह किरन रिजिजू जी की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो, अनुराग ठाकुर जी की हो या मनसुख भाई की हो, हम लोगों ने इस पूरी परंपरा को बदल दिया है। हमारा सारा ध्यान इस पर रहना चाहिए कि हम पदक कैसे प्राप्त कर सकें। उसके लिए हम लोगों ने अपने खिलाड़ियों पर बहुत बड़ा इनवेस्टमेंट करने का काम किया है।

अगर हम इस समय की बात करें तो हमने 470 करोड़ रुपये 16 डिसिप्लिन्स में लगाए हैं। TOPS स्कीम के तहत हमने एक-एक खिलाड़ी की व्यक्तिगत चिंता की है। उसको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? आज आप बोल रहे हैं कि खिलाड़ी आज गए हैं, लेकिन 80 प्रतिशत खिलाड़ी बहुत पहले यूरोप जा चुके हैं, क्योंकि एक्लेमेटाइजेशन भी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कि वह उस वातावरण के लिए तैयार रहे। उसके लिए सभी खिलाड़ियों को लगातार यूरोप में भेजकर लगातार तैयारी करवाने का काम यह सरकार कर रही है।

इतना ही नहीं, सरकार ने चाहे नीरज चौपड़ा हों, मनिका बत्रा हों या पी.वी. सिंधु हों इस तरह से अनेक खिलाड़ियों पर तथा नीरज चौपड़ा दोबारा इतिहास बना सके, उसके लिए 5.72 करोड़ रुपये की केन्द्र सरकार द्वारा मदद की जा रही है। उसी प्रकार से हमने इंडियन मेन हॉकी के लिए भी 41.81 करोड़ रुपये की राशि दी है। यह सब बिल्कुल ही नए ढंग से, नए वातावरण में हो रहा है। खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा फोकस रख सकें, ज्यादा से ज्यादा वे अपने खेल पर ध्यान रख सकें और उनके साथ दूसरी चीजों की जो चिंता है, चाहे वह फीजियोथेरेपिस्ट की हो, डॉक्टर की हो, फूड की हो, हर विभाग के बारे में उसके स्पेशलिस्ट से लेकर और उनके साथ खिलाड़ियों को तैयार करवाने का जो कार्य सरकार कर रही है, उसके लिए हम सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

खिलाड़ी के लिए केवल खेल के प्रति आगे बढ़ना और उसकी मेहनत ही काफी नहीं होती है। पहले यू.एस. या रूस को जो पदक मिलते थे, उसका कारण यह था कि पूरे कम्प्यूटराइजेशन से लेकर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक हर तरह से उन लोगों की प्रिपरेशन में मदद की जाती थी। आज यह सरकार इस काम को भी कर रही है। हमने ट्रेनिंग फैसिलिटी को भी विश्वस्तरीय बनाने का काम किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। पहली बार हुआ है कि माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के कार्यकाल में वर्ष 2014 के बाद से हम इंटरनेशनल कोचेस को हायर कर रहे हैं। दुनिया के जो सबसे बेस्ट कोचेस हैं और कोई खिलाड़ी इच्छा जाहिर करता है कि हमें इस देश के इन्हीं कोच से अपनी ट्रेनिंग लेनी है तो यह सरकार उस हिसाब से उस खिलाड़ी को ट्रेनिंग देने के लिए कृतसंकल्पित है। उनको उनके पसंद के कोचेस के साथ, उनके पसंद के न्यूट्रिश्निस्ट के साथ उस तरह की हर सुविधा को देने का कार्य यह सरकार कर रही है।

केवल इस पेरिस ओलंपिक की ही बात नहीं है, आगामी ओलंपिक्स की तैयारी के लिए भी सरकार खिलाड़ियों को मदद कर रही है। उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर लगातार बना रहे तथा वे विश्व में जहां जाना चाहे, खेलना चाहे तथा वहां पर ट्रेनिंग कर सके और हम उनकी हर तरह से मदद कर सके, उसकी भी चिंता की जा रही है। साथ ही मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने इस बार 'खेलो इंडिया' का बजट 1 हजार 45 करोड़ रुपये का दिया है।

(1545/RAJ/PS)

जो कभी पूरे इस देश के खेल का बजट नहीं होता था, उतना बजट सिर्फ 'खेलो इंडिया' में दिया गया ताकि नए बच्चे तैयारी कर सकें, ओलंपिक में जा सकें एवं मेडल जीत सकें। अगले आठ वर्षों में, अगले 12 वर्षों में, अगले 16 वर्षों में हमारे कौन-से बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, उनको आज से ही प्रोत्साहित करने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार कर रही है। उसी का यह नतीजा है कि पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में हम रिकॉर्ड सात गोल्ड मेडल्स जीत सके। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा संसद दिल से चाहता है कि इस बार हम पहली बार 10 का आंकड़ा पार करें। हमारे खिलाड़ी इतिहास



बनाने का काम करें। इसके लिए संसद के सभी माननीय सांसदों की सदभावना, हम सभी की शुभकामनाएं उन सभी के साथ है।

हम केवल आगामी ओलंपिक की तैयारी नहीं कर रहे हैं। यह पहली बार है कि यह देश वर्ष 2036 में होस्ट करने की भी तैयारी कर रहा है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले वर्ष आईओसी की बैठक हुई थी, उस समय अनुराग ठाकुर जी मंत्री थे और माननीय प्रधान मंत्री जी ने खुल कर कहा था कि वर्ष 2036 में ओलंपिक को होस्ट करना चाहिए, जो पूरे देश के वातावरण को परिवर्तित करने का काम करेगा। हम उसे हिन्दुस्तान के अहमदाबाद में होस्ट कर सके, उसके लिए आज एक पूरी टीम पेरिस भी गई हुई है। वे पेरिस ओलंपिक के बेस्ट प्रैक्टिसेज को लगातार देखने का काम कर रहे हैं। यह पहली बार है कि अभी ही हम लोगों ने एसओपी बना दिया है।

सरकार ने स्पेशल परपस व्हीकल भी बनाया है कि किस तरह से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिल कर ओलंपिक होस्ट करें। ओलंपिक होस्ट करने का अर्थ यह होगा कि पूरा देश एक तरह से मेडल जीतने की तैयारी में हो जाएगा। हमने कॉमन वेल्थ गेम्स में बहुत कंट्रोवर्सी देखी है, पर यह भी एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने का काम भारतीयों ने उस समय किया था। इसलिए हम लोगों को यह काम आगे बढ़ कर करना चाहिए। मैं केन्द्र सरकार के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे खिलाड़ी कैसे लगातार मेडल्स जीत सकें, इसके लिए उनको एनकरेज करना, उनको अपने साथ बुला कर बैठाना, बातें करना, मेडल्स जीतने पर और मेडल नहीं जीत पाने पर भी उनसे लगातार संपर्क कर उनको प्रोत्साहित करने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी करते हैं, उसी का नतीजा है कि हम इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आगामी ओलंपिक की तैयारियों, जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने इस सदन में नियम 193 के तहत चर्चा के लिए अनुमति प्रदान की है। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं।

(इति)

1548 बजे

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) :** अध्यक्ष महोदय, ओलंपिक की तैयारी पर चर्चा - यह अतिमहत्वपूर्ण विषय है। यह विषय तो महत्वपूर्ण है, मगर चार दिनों के बाद 26 तारीख को आंलंपिक शुरू होने जा रहे हैं। आज 22 तारीख है, तो अब हम क्या तैयारी पर सुझाव दें और क्या तैयारी हो पाएगी? अब हम केवल शुभकामनाएं दें और सदन केवल दो-चार काम ही कर सकता है। हमारे जो कंटिजेंट्स हैं, उनको हम शुभकामनाएं दे सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेडल्स आए। क्या ये वर्ष 2028 की ओलंपिक के लिए सुझाव ले रहे हैं, तब तक तो पता नहीं है कि इनकी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, किसकी सरकार रहेगी? आज यह महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे अच्छे मित्र संजय जायसवाल जी ने कहा है कि 470 करोड़ रुपए अलग-अलग जो ओलंपिक सेल - साई में किया गया था, ... (व्यवधान) उसके माध्यम से आवंटित किया गया है... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** हुड्डा जी, आप माइक ठीक कर लें।

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) :** 470 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, यह अच्छी बात है। यह और भी ज्यादा आवंटित होना चाहिए। विदेशों में कराए जा रहे ट्रेनिंग के बारे में अलग-अलग खेलवार ब्योरा दिया गया है, उस पर मुझे इतना ही कहना है कि इसमें जो आवंटित किया गया है, उसमें हॉकी और रेसलिंग का नम्बर काफी पीछे है। जबकि ये दो ऐसे खेल हैं, जो न सिर्फ हमारी धरती से जुड़े हुए खेल हैं, बल्कि इन दो खेलों से सबसे ज्यादा मेडल्स आए हैं।

(1550/VB/SMN)

उनका आवंटन ज्यादा किया जाना चाहिए था, उनका आवंटन का नम्बर 9वें और 10वें स्थान पर है। यह मैं कहना चाहता हूँ।

अगर हम ओलम्पिक और भारत देश के खेल की बात करें, तो इसमें हरियाणा का संदर्भ न लें, तो यह चर्चा अधूरी होगी। मैं अधूरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देश के इतिहास में 35 ओलम्पिक मेडल्स हमारे देश ने अर्जित किये हैं, जिनमें से 23 इंडिविजुअल खेलों के मेडल्स हैं। इन 23 मेडल्स में से 10 मेडल्स, पिछले चार ओलम्पिक में हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आए हैं। यानी लगभग 40 में से 2 प्रतिशत वाला हरियाणा, 40 से 50 प्रतिशत ओलम्पिक के मेडल्स और केवल ओलम्पिक ही नहीं, बल्कि एशियाई और कॉमनवेल्थ के मेडल्स में भी हरियाणा की हिस्सेदारी इतनी ही होती है। अभी वे कह रहे थे कि वर्ष 2014 के बाद से खेलों में इतनी बढ़ोतरी हुई, लेकिन अगर हम पिछले चार ओलम्पिक्स में देखें, चारों ओलम्पिक्स में देश के मेडल्स आए और आधे से ज्यादा मेडल्स हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आए। वर्ष 2008 में, सबसे पहले ओलम्पिक में तीन मेडल्स आए, जिनमें से 2 मेडल्स देश के लिए हरियाणा के खिलाड़ियों ने अर्जित किये। वर्ष 2012 में 6 मेडल्स आए, जिनमें से 4 मेडल्स हरियाणा के खिलाड़ियों ने अर्जित किए। वर्ष 2016 में 6 से घटकर 2 मेडल्स आए, लेकिन दो में से भी एक मेडल हरियाणा की बेटा साक्षी मलिक लेकर आई। वर्ष 2020 में, 7 मेडल्स आए, जो वर्ष 2012 के लगभग बराबर हैं, जिनमें से 3 मेडल्स हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आए।

अगर हम ओलम्पिक में जाने वाले कंटिजेंट की बात करें, तो पिछले ओलम्पिक के खेलों में 120 खिलाड़ियों में से 31 खिलाड़ी यानी 25 प्रतिशत खिलाड़ी हरियाणा से गये। इस ओलम्पिक में भी 117 में से 24 खिलाड़ी यानी लगभग 21 प्रतिशत खिलाड़ी हरियाणा से जा रहे हैं। नीरज चोपड़ा से लेकर विनेश फोगाट तक, जिन्होंने जंतर-मंतर पर सरकार के खिलाफ धरना दिया है। ये सभी ओलम्पिक के कंटिजेंट का हिस्सा हैं, जो ओलम्पिक के खेलों में जा रहे हैं।

वर्ष 2006-07 के बाद से जितने भी खेल हुए चाहे वे एशियाई खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स हों, मुझे गर्व है कि मैं हरियाणा से आता हूँ, इन सभी खेलों में 50 प्रतिशत तक मेडल्स और 25 प्रतिशत कंटिजेंट के रूप में देश को रेप्रजेंट करने का अवसर हरियाणा के खिलाड़ियों को मिला। इसलिए जब हम ओलम्पिक की बात करें, तो

जैसा कि मैंने कहा कि यह बिना हरियाणा की बात किये अधूरा होगा। ऐसा कौन-सा सिस्टम हरियाणा में बना, जिसकी वजह से आज ओलम्पिक में हरियाणा के खिलाड़ी इतना अच्छा कर पा रहे हैं, उसको जानना चाहिए, क्या ऐसी बातें हैं, जिन्हें देश के अन्य राज्य लेकर जा सकें क्योंकि खेल हमेशा राजनीति से ऊपर होना चाहिए। उसमें अब क्या कमियाँ आ गई हैं, उनके बारे में भी बताना एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हमारा कर्तव्य है।

मेडल्स तभी आ सकते हैं, जब आप सही प्रतिभा की खोज करें, प्रतिभा को प्रोत्साहन दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जब कोई मेडल लेकर आए या न आए, कोई चोटिल हो जाए, वह मेहनत करे, लेकिन एक स्तर तक पहुंच जाए, तो उसका भविष्य सुरक्षित किया जाए। खिलाड़ियों के मन से अपने भविष्य की असुरक्षा निकाल दी जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा की पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 2004-05 में खेल नीति बनाई थी, जिसे 'पदक लाओ और पद पाओ' की नीति भी कहा गया। इसके तीन पहलू थे। पहला पहलू था कि चाहे आप किसी स्तर तक पहुंचेंगे, चाहे राष्ट्रीय खेलों तक पहुंचें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों तक आप पहुंचेंगे तो आपके भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। इस नीति के तहत 500 से ज्यादा अलग-अलग पदों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति हरियाणा सरकार ने की। जिसमें डीएसपी लेवल पर चाहे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त हों, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज बिजेन्द्र सिंह हों, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट हों, इन सभी खिलाड़ियों को डीएसपी से लेकर अन्य पदों पर हरियाणा सरकार द्वारा मौका दिया गया। दुर्भाग्य की बात है कि 'पदक लाओ और पद पाओ' की जो नीति थी, जिसमें नियुक्तियाँ देने की नीति थी, वह पिछले 10 वर्षों से, जब भाजपा की सरकार है, उसने इस नीति पर रोक लगाने का काम किया है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी खिलाड़ी बेटी साक्षी मलिक को आज तक हरियाणा में कोई नियुक्ति नहीं मिली है। पिछले ओलम्पिक के हमारे खिलाड़ी, मेडल विजेता रवि दहिया और नीरज चोपड़ा को हरियाणा सरकार द्वारा अभी तक कोई नियुक्ति नहीं देने का काम किया गया है।

सर, यह तो डीएसपी और अन्य पदों की बात है, हरियाणा में ग्रुप-III और ग्रुप-IV में भी 3 प्रतिशत खिलाड़ी कोटा कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। उस खेल कोटे को भी समाप्त करने का काम मौजूदा सरकार ने हरियाणा के अन्दर किया है।

(1555/PC/NKL)

जो खिलाड़ी डीएसपी बनाए गए थे, उन डीएसपी खिलाड़ियों को इन दस वर्षों में प्रमोशन तक नहीं दी गई है। अतः आज वे खिलाड़ी धरने देने पर मजबूर हो रहे हैं।

इसके साथ-साथ जो कैश अवॉर्ड मिलता था, आज हमारे खिलाड़ी उस कैश अवॉर्ड से भी महरूम हो गए हैं, जैसे सरकार उनसे किसी बात का बदला ले रही हो कि वे मैडल लेकर आए हैं। यहां तक कि वर्ष 2021 के बाद से अभी तक, आज ही दैनिक भास्कर में खबर आई है, मानो दैनिक भास्कर को पता हो कि यह सरकार नियम 193 का डिस्कशन लेकर आएगी। 'खेलों के पदक विजेता कैश अवॉर्ड से वंचित'। वर्ष 2021 के बाद से कैश अवॉर्ड दिए ही नहीं गए।

दूसरी ओर, नेशनल और इंटरनेशनल वालों को तो आप अभी कह रहे हैं कि वंचित रखा है, मगर देंगे। वे वर्ष 2021 से वंचित हैं, लेकिन बाकियों को तो आपने कैश अवॉर्ड देना बंद कर दिया? हमारी कांग्रेस की सरकार के समय जूनियर, सब-जूनियर और यूथ-गेम्स में भी जो खिलाड़ी मैडल लेकर आते थे, उनको भी कैश अवॉर्ड दिया जाता था।

सर, एक और पहलू है। हमारी सरकार के समय जो नीति बनी थी, क्योंकि नीचे से प्रतिभा को खोजने की बात थी, तो एक पॉलिसी बनी थी – 'SPAT', जिस वजह से हरियाणा के खिलाड़ी आज इतने आगे आए हैं। 'Sports and Physical Aptitude Test', पहली क्लास से स्पोर्ट्स और फिजिकल एप्टिट्यूड टेस्ट किया जाता था। जो दस प्रतिशत बच्चे भागने, दौड़ने और फिजिकल एप्टिट्यूड में अग्रणी आते थे, उनको मासिक

पहली प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। इसकी शुरुआत हरियाणा में हुई थी। इस सिस्टम से बहुत खिलाड़ी आगे आ रहे थे।

जब भाजपा की सरकार हरियाणा में आई, तो 'SPAT' का नाम 'SPEED' में बदल दिया और फिर 'SPEED' पर भी स्पीड-ब्रेकर लगाकर उसको समाप्त कर दिया। ... (व्यवधान) इसके तो कई ऐसे पहलू हैं, जिनका मैं उदाहरण देता हूँ। अगर एससी समाज से आने वाली हमारी कोई खिलाड़ी बेटी अगर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पर पहुंचती थी, तो चालीस हजार रुपए प्रतिवर्ष की उसको प्रोत्साहन राशि मिलती थी, ताकि एससी समाज से आने वाली बेटियों की खेलों में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बने। सरकार ने आते ही, वर्ष 2016 में भाजपा सरकार ने एससी समाज की बेटियों को मिलने वाली इस प्रोत्साहन राशि को समाप्त करने का काम किया। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** हुड्डा जी, आप फिर मुझे कहेंगे कि मैं टोक रहा हूँ, वीडियो चलाओगे।

... (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) :** सर, अगर हमारा अधिकार 'बोलना' है, तो आपका अधिकार 'टोकना' है।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** यह हरियाणा की विधान सभा नहीं है, यह संसद है।

... (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) :** सर, हरियाणा का स्पोर्ट्स सिस्टम कैसे आगे जाए? जब देश में आधे मैडल्स हरियाणा के स्पोर्ट्स सिस्टम से आ रहे हैं, तो उस पर भी चर्चा हो। इसके साथ-साथ मैं इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी कहना चाहूंगा। हमारे समय में हरियाणा में 232 राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम्स बने थे और छः अंतर्राष्ट्रीय कॉम्प्लेक्स बने थे। इन स्टेडियम्स में नर्सरीज और कोचेज थे, ताकि हर ग्रामीण स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर किसी न किसी एक खेल की नर्सरी बने और उस पर हम ध्यान केंद्रित कर पाएं।

सर, मौजूदा सरकार ने इन नर्सरीज को बिलकुल ही नजरंदाज किया और पिछले दस वर्षों में एक भी कोच की भर्ती हरियाणा के अंदर नहीं हुई। स्टेडियम्स की दुर्दशा भी हुई है। रोहतक और अंबाला के स्टेडियम्स की दुर्दशा हुई है। अंबाला कैंट में तो एक ऐसा स्टेडियम है, जिसमें पिछले सात वर्षों से कंस्ट्रक्शन चल रही है। आज तक उसमें कंस्ट्रक्शन ही पूरी नहीं हुई। ऐसी व्यवस्था आप हरियाणा के अंदर देख पा रहे हैं।

सर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि खिलाड़ी का भविष्य सुरक्षित किया जाए, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, प्रतिभाओं को आगे निकाला जाए। इसके साथ-साथ एक बहुत बड़ी बात होती है - सम्मान। खिलाड़ी को सम्मान मिले। अगर आज हमारे खिलाड़ी दुनिया में जाकर अपने देश का झंडा उठाने के लिए दूसरे देशों के खिलाड़ियों से लड़ेंगे, तो उन्हें अपने सिस्टम से लड़ना न पड़े, उनको अपनी सरकार से लड़ना न पड़े। ... (व्यवधान) आप विनेश फोगाट को क्या कहेंगे, जब हमारी बहन ओलंपिक में जाएगी? कितने महीनों तक इन बेटियों को अपनी सरकार और सिस्टम से लड़ना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद एफआईआर हुई, नहीं तो सरकार ने एफआईआर भी नहीं की थी। वह बेटियों से छेड़छाड़ का मामले में क्या कारण था, हमें नहीं पता, क्योंकि एफआईआर नहीं की गई? क्या वे स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष थे या वे भाजपा के, सत्तारूढ़ दल के सांसद थे। ... (व्यवधान) जो भी कारण रहा, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए।

सर, खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए। जब खिलाड़ी मैडल्स लेकर आते हैं, उन खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए सरकार के मंत्री एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन बेटियों के साथ अगर कुछ गलत हो गया और एक नहीं, बल्कि छः - छः ओलंपिक विजेता बेटियां धरने पर बैठी हैं। जब वे मेडल जीतकर आई थीं, तो जो उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, वहां जाकर किसी ने उनकी बात तक नहीं सुनी।

(1600/CS/VR)

... (व्यवधान) महोदय, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ... (व्यवधान) मैं सरकार से यह सवाल पूछना चाहता हूँ... (व्यवधान) गंगा में मेडल बहाने की बात कही... (व्यवधान) आप ओलम्पिक मेडल्स की बात कर रहे हैं... (व्यवधान) आप ओलम्पिक खेलों में अपनी तैयारी की बात कर रहे हैं... (व्यवधान) मगर जब खिलाड़ियों ने यह कहा कि हमारे साथ इस देश में अन्याय हो रहा है... (व्यवधान) जब खिलाड़ी बेटियों ने कहा कि हमारे साथ इस देश में अन्याय हो रहा है और हम इन मेडल्स को गंगा में बहा देंगे तो कम से कम खेल मंत्री जी का बयान आना चाहिए था कि नहीं, ये देश के लिए मेडल्स लाए हैं, ये मेडल्स देश के लिए आए हैं, इनको गंगा में नहीं बहाना है और आपको न्याय मिलेगा... (व्यवधान) न्याय मिलेगा का बयान भी नहीं आया... (व्यवधान) न्याय मिलेगा का बयान भी आ जाता तो हम संतुष्ट हो जाते... (व्यवधान)

महोदय, यह देश महाभारत का देश है। मैं स्वयं ऐसे प्रदेश से आया हूँ, जहाँ कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। हमारी बहन, बेटे के मान-सम्मान पर बात आयी तो देश में कुरुक्षेत्र में महाभारत का रण हुआ। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी, आप क्या कह रहे हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री; तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया) :** कुरुक्षेत्र में... (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) :** महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ और मैं उस समय सरकार की तरफ से दिए गए बयान पढ़ रहा हूँ सत्तारूढ़ दल के आरोपी एक सांसद का बयान आया कि ये मेडल तो आप इतने रुपये में बेच सकते हैं। आप ओलम्पिक मेडल्स की बात कर रहे हैं। आप ओलम्पिक मेडल की बात कर रहे हैं और आप इस देश में उनकी कीमत लगा रहे हैं आप ऐसे स्पोर्ट्स फेडरेशन चला रहे हैं। इस पर प्रश्न उठेंगे। हरियाणा के खेल मंत्री, जो स्वयं पहले हॉकी के खिलाड़ी थे, हम उनका मान-सम्मान करते हैं। वे खिलाड़ी हैं, वे हरियाणा की भाजपा सरकार में खेल मंत्री थे... (व्यवधान) उनके ही महकमे की एक जूनियर कोच ने, एक हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने उन पर आरोप लगाया कि खेल मंत्री ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है... (व्यवधान)

**डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :** महोदय, ये वहाँ की बात यहाँ नहीं कर सकते हैं... (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) :** उसके बाद भाजपा की तरफ से यह आया, जब हमने माँग की कि इन खेल मंत्री को हटाया जाए, इनको बर्खास्त किया जाए, तो यह कहा गया कि ये खेल मंत्री रहेंगे, उनको मंत्री बनाए रखा और जिस बेटे ने, मैं हरियाणा के खेल मंत्री की बात बता रहा हूँ... (व्यवधान) जिस बेटे ने उन खेल मंत्री पर आरोप लगाया था, उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** एक मिनट रूकिए।

माननीय सदस्य, इस सदन के अंदर यह परम्परा रही है कि हम यहाँ किसी राज्य की विधान सभा की चर्चा न करें और अन्य सदन की चर्चा न करें। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) :** सर, मैं खेल मंत्रालय, भारत सरकार और ओलम्पिक्स के मेडलिस्ट्स की बात कर रहा हूँ। खैर आपने जो बात कही है, मैं उस बात पर आगे बढ़ते हुए कहना चाहता हूँ कि मेरा संदर्भ यह है कि खिलाड़ियों को मान-सम्मान, उचित प्रोत्साहन, प्रतिभा की खोज के साथ-साथ उनके भविष्य की सुरक्षा संबंधी नीति बनने की जब तक बात नहीं होगी, क्यूँ हरियाणा आज देश के आधे से ज्यादा मेडल्स लेकर आ रहा है? हर खेलों में, पिछले 10 वर्ष से नहीं, वर्ष 2008 के बाद से, जो मैंने आपको बताया है। यह तो रिकॉर्ड की बात है, आप झुठला नहीं सकते हैं कि वर्ष 2008 के ओलम्पिक में कितने मेडल्स आए, वर्ष 2012 के ओलम्पिक्स में कितने मेडल्स आए, तो हरियाणा के खिलाड़ी क्यों मेडल्स ला रहे हैं, तो कुछ न कुछ उस नीति में अच्छी बात होगी। आप उसे समझें, उसे अपनाएं, हमें खुशी होगी। आपने कुछ अच्छा कार्य किया, हम भी उसकी सराहना करेंगे, क्योंकि खेल और खिलाड़ी हर तरह की राजनीति से ऊपर होने चाहिए। आज दुःख होता है, जिस हरियाणा में नारा था, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, जय नौजवान, जय संविधान का नारा हम देते थे, उस हरियाणा के नौजवान सैनिक बनकर भारतवर्ष का झंडा सीमा पर ऊँचा करने की बात करते थे, वहाँ पर आग्निवीर योजना ले आए और खिलाड़ी बनकर दुनिया के पोजियम पर जाकर राष्ट्र गान बजवाकर झंडा ऊँचा करने की बात करते थे, आज वह हरियाणा, जो खेलों में नंबर एक था, आज वह नशे में नंबर एक बन गया है। हमें इस बात की बहुत ही पीड़ा है... (व्यवधान) आज हरियाणा में हम निराशा के साथ इस सरकार का खेलों के प्रति रवैया देख रहे हैं... (व्यवधान) ओलम्पिक खेलों की तैयारी पर जो यह चर्चा की गई है, अच्छा होता कि यह चर्चा एक साल पहले आती... (व्यवधान) सर, इनको क्या तकलीफ है?... (व्यवधान) मैंने ऐसा क्या गलत कहा है?... (व्यवधान) सर, मैंने ऐसा क्या गलत कहा है?... (व्यवधान) हमने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है, जिससे किसी को तकलीफ हो... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** इन्होंने केवल इतना ही कहा है कि इनको ऐसा लगता है।

... (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) :** सर, हमें ऐसा लगता है... (व्यवधान) सर, यही बात है... (व्यवधान)

(1605/IND/SAN)

अध्यक्ष जी, हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई आरोपी भाजपा का सांसद या भाजपा का कैबिनेट मंत्री हो, तो भाजपा को उसके पक्ष में नहीं आना चाहिए। पूरी पार्टी उसके पक्ष में आकर खड़ी हो जाए, इस बात से हमें तकलीफ है। सत्तारूढ़ दल को उसके पक्ष में नहीं आना चाहिए। पूरी पार्टी को उनके पक्ष में नहीं आना चाहिए। हमारा यह संदर्भ है कि किसी ने यदि खिलाड़ियों का शोषण किया है, तो वह अपराध है। उस अपराधी को कानून का सामना करना चाहिए। आप खिलाड़ियों का मान सम्मान कीजिए। एक कहावत थी 'पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराबा'

हरियाणा की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार ने उस कहावत को बदल कर दिखा दिया 'पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, मगर खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे लाजवाब' आपने उस कहावत का दूसरा अर्थ कर दिया 'खेलोगे कूदोगे तो बीजेपी की सरकार हो जाएगी नाराजा' दोबारा से 'खेलोगे कूदोगे तो होंगे लाजवाब' इस कहावत की तरफ कदम बढ़ाएं। हम एक-एक कदम पर आपका साथ देंगे।

(इति)

**माननीय अध्यक्ष :** संसदीय कार्य मंत्री जी।

**संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) :** अध्यक्ष जी, दीपेन्द्र हुड्डा जी ने बहुत जोशीला भाषण दिया है, मुझे अच्छा लगा। खेल मंत्री जी इसका जवाब देंगे लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया है, वे सदन में जरूर बैठे रहें क्योंकि पिछले दस सालों में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो काम हुए हैं, उनके बारे में आप जान पाएंगे। मेरा एक्सपीरिएंस रहा है कि माननीय सदस्य एलिंगेशन लगाकर सदन से चले जाते हैं। मोदी सरकार ने खेलों के संबंध में कितना ज्यादा काम किया है, उसके बारे में आप जरूर सुनें। खिलाड़ियों के लिए और खेलों के लिए मोदी जी ने कितना किया है, वह खिलाड़ियों से सुनना चाहिए। आप फेडरेशन की लड़ाई के बारे में सदन में चर्चा मत कीजिए। आप सदन में ओलम्पिक खेलों की तैयारियों के बारे में बात कीजिए। खेल संघ में पालिटिक्स होनी ही है, क्योंकि चुनाव करके ही आप उसमें प्रेजिडेंट या सैक्रेटरी बन सकते हैं। जब किसी भी फेडरेशन में चुनाव के माध्यम से प्रेजिडेंट और सैक्रेटरी बनते हैं तो वहां दो भाग होते ही हैं। आप वहां की पॉलिटिक्स को यहां लेकर मत आइए। आपने फेडरेशन पॉलिटिक्स को यहां मिक्स किया है जबकि यहां ओलम्पिक्स की तैयारी पर चर्चा हो रही है। खेल और खिलाड़ियों के लिए नरेन्द्र मोदी जी ने जो किया है, वह 75 साल में किसी सरकार ने नहीं किया है। आप यहां राजनीतिक भाषण मत दीजिए... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** दादा आप क्या बोल रहे हैं?

**प्रो. सौगत राय (दम दम) :** अध्यक्ष जी, अनुराग ठाकुर जी ने अच्छा काम किया। फिर उन्हें भी ड्रॉप किया गया। सरकार स्पोर्ट्स के बारे में क्या कर रही है? अनुराग जी को मिनिस्टर रखना चाहिए था... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री नीरज मौर्या।

1608 बजे

**श्री नीरज मौर्य (आंवला) :** अध्यक्ष जी, ओलम्पिक खेलों की तैयारी की चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

1608 बजे

(श्री पी. सी. मोहन पीठासीन हुए)

सभापति जी, हमारे देश के जो खिलाड़ी ओलम्पिक्स में शामिल होने जा रहे हैं, मैं सबसे पहले उन्हें अपनी ओर से तथा अपने क्षेत्र की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार भारत पहले के सारे रिकार्ड तोड़कर मैडल्स लाए, ऐसी हमारी शुभकामना और इच्छा है। ओलम्पिक खेलों की तैयारी पर आज जो चर्चा सदन में हो रही है, चूंकि 2024 का ओलम्पिक्स जुलाई और अगस्त में होने जा रहा है। आज खेलों की, खिलाड़ियों की जो हालत है, उसके बारे में जरूर आज यहां सदन में चर्चा हो रही है। मैं अपनी कुछ बातें इस संबंध में रखूंगा।

सभापति जी, हमारे देश में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, इस ओलम्पिक्स में मात्र 117 खिलाड़ी जा रहे हैं। वर्ष 2020 के जापान के ओलम्पिक्स में हमारे 120 खिलाड़ी गए थे। इसमें जरूर चिंतन होना चाहिए कि यह संख्या क्यों घटी है। वर्ष 1900 में पहली बार भारत ने इन खेलों में भाग लिया और आज तक मात्र 35 मेडल्स भारत को आए हैं। हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं और अगर ओलम्पिक्स की तैयारी को लेकर देखा जाए तो गांवों में सरकार के द्वारा कोई ऐसा अवेयरनेस का कार्यक्रम नहीं चलाया जाता, जिससे गांवों के नौजवान भाग ले सकें।

(1610/GG/SNT)

जहां ग्रामीण अंचलों में कहीं थोड़े-बहुत स्टेडियम भी बनाए गए हैं तो उन स्टेडियमों में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, जहां पर हमारे बच्चे खेलों की तैयारी कर सकें, ओलंपिक्स में जाने की तैयारी कर सकें।

आज यहां पर बात आई कि बजट बढ़ाया गया है। माननीय संजय जी कह रहे थे कि जब खिलाड़ी मेडल जीत कर वापस देश आते हैं, तब प्रधान मंत्री जी उनसे चर्चा करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब खिलाड़ी संकट में थे, जब खिलाड़ियों पर संकट था, मुझे लगता है कि तब भी उनको बुला कर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन तब उनसे चर्चा नहीं की गई।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी 80% लोग गांवों में रहते हैं। हम प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए हैं। पहले प्राइमरी स्कूलों में पीटी होती थी, दौड़ लगाई जाती थी, खेल होते थे। वहीं, आज बहुत ही खराब स्थिति है। सरकार को इस ओर जरूर चिंता करनी चाहिए। क्योंकि जब तक बच्चे खेल-कूद कर खेलों में आगे नहीं आएंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर प्राइमरी स्कूलों से ही यह तैयारी शुरू करवाई जाए, तो मैं समझता हूँ कि भारत हर ओलंपिक में पहले नंबर पर आएगा, जबकि पिछली बार हम मात्र 48वें नंबर पर थे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 2024 का यह जो ओलंपिक्स होने जा रहा है, इसको ले कर तैयारी के बारे में उधर से जो बातें बताई गई हैं या बताई जा रही हैं, हम लोग उनको सुन ही सकते हैं। अगर इस विषय पर सदन में चर्चा होनी थी तो हम लोगों को पहले अवसर दिया जाता, ताकि हम लोग और तैयारी कर के आते और जो हमारे खिलाड़ी भी यहां की बात को सुन रहे होंगे, उन तक



पूरे सदन का सुझाव पहुंचता और वे और ज्यादा मेहनत करते। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यही आग्रह करूंगा कि 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में और खिलाड़ी कैसे निकलें, इस पर सरकार कार्य करे। साथ ही, खेलों में जो राजनीति घुस रही है, उसको भी खेलों से दूर किया जाए। अगर खेलों से राजनीति को दूर नहीं किया जाएगा तो जो जंतर-मंतर पर हुआ है, मुझे लगता है कि यही होता रहेगा। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि खेलों में राजनीति किसी भी सूरत में बर्दाश्त न की जाए। आज बहुत सारे ऐसे लोग, जो खेल के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन उन खेलों के फेडरेशन में बैठे हुए हैं, उन खेलों के अध्यक्ष बने हुए हैं। अगर अध्यक्षता भी किसी को देनी है, किसी को इसमें लाना है, तो उस क्षेत्र के लोगों को ही वहां मौका दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे देश के खेलों में सुधार हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, हम इस बार ओलंपिक खेलों में 117 खिलाड़ी भेज रहे हैं। इस बारे में भी कोई योजना होनी चाहिए कि हम और प्रतिभाओं को कैसे आगे लाएं। हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि लोगों को अवसर नहीं मिलता। अवसर इसलिए नहीं मिलता, क्योंकि हर जगह पर राजनीति घुसी हुई है। जब राजनीति घुसी होगी तो लोगों के पास इतनी सिफारिश नहीं है, जो लोग गांवों में रहते हैं, भोले-भाले लोग हैं, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वे कैसे वहां तक पहुंचें। इसलिए इस पर बल देते हुए कि आने वाले समय में सरकार खेलों में, चाहे कोई फेडरेशन हो, चाहे कोई अन्य संस्थान हो, वहां पर अगर उसी क्षेत्र के लोगों को बिठाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि भारत हर ओलंपिक खेलों में नंबर एक आएगा और जो भी अंतर्राष्ट्रीय खेल होंगे, उनमें भारत आगे निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय सभापति जी, मैं खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए सरकार से यह उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि हमारे जो खिलाड़ी वहां पर जा रहे हैं, उनको हर तरह की सुविधा दी जाए, उनका हर तरह से ध्यान रखा जाए। उनका मनोबल यह सदन भी बढ़ाए कि इस बार सात मेडलों का रिकॉर्ड तोड़ कर हमको 70 मेडल्स लाने हैं। हमको यह काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि चार दिनों में इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है।

(1615/MY/AK)

मुझे जानकारी मिली है कि इस ओलंपिक में लगभग 329 मेडल्स हैं। इन 329 मेडल्स में से अगर 70 मेडल्स भी भारत लाएगा तो हम सब लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं पुनः भारत के खिलाड़ियों को शुभकामना देता हूँ। मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूँ कि वे हमारे देश का नाम रोशन करेंगे।

महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे ओलंपिक्स जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1615 बजे

**श्री कीर्ति आज़ाद (बर्धमान-दुर्गापुर) :** धन्यवाद सभापति जी। खेल और खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती, न उसका कोई मजहब होता है। राजनीतिक पार्टियाँ खेल को शायद उतना महत्व नहीं देती, जितना देना चाहिए, लेकिन मैं पश्चिम बंगाल के अपने मुख्यमंत्री का सहृदय धन्यवाद करना चाहूंगा। कला, खेल, संगीत सहित सब क्षेत्रों से आपको इस संसद के अंदर व्यक्ति मिलेंगे, जो अपने क्षेत्र की आवाज को उठा सकते हैं। मैं अपनी ओर से अपनी मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सभी क्षेत्रों से लोगों को पार्लियामेंट में बुलाकर उनकी आवाज उठाने का अवसर दिया।

सभापति जी, चूंकि खेल और खिलाड़ी की कोई जाति और मजहब नहीं होती है, इसलिए राजनीतिक लोग भी इसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। संजय जयसवाल जी अभी हैं या चले गए?... (व्यवधान) वह चले गए। वह बोल रहे थे कि जब हम तैयारी की बात करेंगे तो विपक्ष को दर्द होगा। मुझे मालूम नहीं कि उनको या उनकी पार्टी को तब दर्द हुआ था, जब हमारी महिला कुश्ती की बेटियों और बहनों के साथ अत्याचार हुआ था और वे त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रही थीं। तब किसी की आवाज नहीं उठी थी।

मुझे याद है, जब मैं छोटा था। मैं भी भारत के लिए क्रिकेट खेला हूँ। हमने वर्ष 1983 में विश्व कप जीता। हमारे साथ युसुफ पठान बैठे हुए हैं, जो वर्ष 2012 में विश्व कप भारत के लिए जीते। फुटबॉल के हमारे कप्तान प्रसून बनर्जी सर बैठे हैं। इनको पदमश्री भी मिला हुआ है। मुझे भी याद है, जब मैं छोटा था और उस समय क्रिकेट में पैसा नहीं था। हम लोग ट्रेन के थर्ड क्लास बोगी में जाया करते थे। सामान टॉयलेट में पड़ा हुआ होता था। इसी तरह से हम लोग बैठे रहते थे और खेलने के लिए जाते थे। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया तो शायद अपना ही है, किरेन रिजिजू जी मंत्री रहे हुए हैं। वही एसजीएफआई हमें ले जाया करती थी।

सभापति महोदय, आज भी वही परिस्थिति हमारे एथलीट्स की है, क्रिकेट की तो नहीं, लेकिन हमारे एथलीट्स की है। आज भी हमारे जो खिलाड़ी हैं, उनकी यही हालत है। वे जनरल बोगी में जाते हैं, टॉयलेट के सामने बैठते हैं और टॉयलेट में उनका सामान होता है। जब वे खेलने के जाते हैं तो उबड़-खाबड़ मैदानों पर खेलते हैं। उनको खाने के लिए ढंग से कुछ भी नहीं मिलता है। वे डॉरमेट्री में रहते हैं और टॉयलेट के सामने उनका खाना बनता है। यह मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि यह टेलीविजन पर एक बार नहीं, अनेकों बार देखा गया है। हम बात करते हैं कि हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है! अगर आपको ओलंपिक्स की तैयारी की बात करनी है तो वर्ष 2028 की तैयारी अभी करनी चाहिए, न कि जब आपकी टीम चली गई हो। ओलंपिक्स की तैयारी और खेल के बारे में लोग समझते हैं कि खेल ऐसे ही है। जब से टेलीविजन पर यह खेल आना शुरू हुआ है और 30 कैमरों से क्रिकेट को अलग-अलग एंगल्स से दिखाया जाता है, लोग मुझे सिखाने लगे हैं कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। उनको मालूम नहीं कि जब थॉमसन 100 की स्पीड पर गेंद करता था, सुनील गवास्कर सामने होता था, जब सचिन तेंदुलकर एक तरफ हो और ब्रेटली दूसरी तरफ हो तो प्वाइंट 42 सेकेंड्स गेंद

को निकलने में, बल्लेबाज तक पहुंचने में और प्वाइंट 38 सेकेंड्स बल्लेबाज को तय करने में कि मैं फ्रंट फूट पर जाऊं, बैक फूट पर जाऊं, हुक करूं, कट करूं, पुल करूं, क्या करूं, लेकिन लोग हमको सिखाते हैं। यानी यह बॉल छुट्टी और यह बैटसमैन के पास आई, बस यही समय है। इन दो चुटकियों के बीच का खेल है। उसको संभवतः लोग समझेंगे नहीं, बहुत आसानी से लेते हैं कि यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। मुझे बड़ी खुशी है कि जब कुश्ती की हमारी महिला खिलाड़ी आई थी तो प्रधानमंत्री जी ने उनका स्वागत किया था, सम्मान किया था। बहुत प्रसन्नता हुई थी, जब वह उनके साथ खा रहे थे। लेकिन, तब दुख हुआ था, जब उन महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार हुआ था, तब उन्होंने मौन व्रत धारण करके रखा था। हम अपनी महिलाओं के लिए बोलते हैं कि बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ। हमारी बेटियाँ जो बाहर से स्वर्ण और दूसरे पदक लेकर आती हैं, यह सदन के लिए शर्म की बात है कि यदि हम उनको अपनी तरफ से संरक्षण नहीं दे सकते हैं तो यह बड़े खेद की बात है। आज बात करते हैं कि हमने नीरज चोपड़ा को भेजा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब तक नीरज चोपड़ा ने भल्ला फेंकने (जैवलीन) में स्वर्ण पदक नहीं जीता था, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था।

(1620/CP/UB)

अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने पहला स्वर्ण पदक शूटिंग के अंदर जीता, उसके पहले सरकार ने उनके लिए क्या किया था या एसोसिएशन फेडरेशन ने उनके लिए क्या किया था? कर्णम मल्लेश्वरी, जिनका नाम टीम से हटा दिया गया था, मैं उस समय पहली बार सांसद बनकर वर्ष 1999 में पार्लियामेंट में आया था, यह वर्ष 2002 की बात है, तब उनको निकाल दिया गया था। जब वे वापस आईं, तो उन्होंने उस समय कांस्य पदक जीता। सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। किसी ने उनका नाम नहीं सुना था, तब उनको खूब अलग-अलग उपहार मिले थे।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि ओलम्पिक्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भेजने से पहले आप उनके लिए क्या करते हैं? जीत के आने के बाद तो आप न जाने क्या-क्या चीजें उनको देते हैं, जो उन्हें मिलनी भी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक अच्छा खिलाड़ी, जैसे अभिनव बिंद्रा बनाने के लिए, नीरज चोपड़ा बनाने के लिए, पी.वी.सिंधु बनाने के लिए, साइना नेहवाल बनाने के लिए, सानिया मिर्जा बनाने के लिए सरकार ने क्या-क्या किया? सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि कौन सी प्रिपेयर्डनेस है? आज एक बार कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की, हमारे देश की बेटी या बेटा अच्छा करके जब बाहर से आता है तो आप सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन, कैसे वह अच्छा बनकर आगे बढ़े, इसके लिए आप क्या करते हैं? साईं में, भारतीय खेल प्राधिकरण में कहां हैं कोचेज़, कहां हैं प्रशिक्षक? आपने खेलो इंडिया शुरू किया, यह बहुत प्रसन्नता की बात है। जो भी आए, वह इसमें खेल सकता है। जो भी खेलने आएंगे, उनमें एकलव्य की प्रतिभा की तलाश कौन करेगा? क्या इसके लिए कोई व्यवस्था है? इसकी व्यवस्था नहीं होती है। इसकी व्यवस्था इसलिए नहीं होती, क्योंकि वहां 70 प्रतिशत से अधिक जगह प्रशिक्षकों की खाली पड़ी हुई हैं।

मुझे याद है, मैं जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में जाता था, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला था, जहां पर कोचेज तैयार किए जाते थे। इस नेशनल स्टेडियम के अंदर क्रिकेट, हॉकी, फुटबाल, बॉस्केटबॉल, बैडमिंटन, सभी खेल खेले जाते थे और सभी के प्रशिक्षक होते थे। हम लोगों को प्रशिक्षण मिलता था। हम लोग वहां सीखते थे और सीखने के बाद आगे खेलते थे। आज वह परिस्थिति कहां है?

मैं अधिक बातों को न कहते हुए, अपनी बात जल्दी समाप्त करूंगा। अभी रिजीजू जी ने कहा कि खेल संघ वाले हैं, वे आपस में चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी आपस में लड़ाई तो होगी ही। आप यहां खाक मारने के लिए बैठे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किसलिए बैठी हुई है? यदि आप उन लड़ाइयों को सुधार करके जो प्रतिभावान लोग हैं, उनको आप आगे नहीं भेज सकते, तो फिर आपका फायदा क्या है? ऐसी बातें कहते हुए आदमी को जरा सोच लेना चाहिए।

याद रखिए, हर एक व्यक्ति में एक खिलाड़ी रहा है। बचपन से जब बड़े हुए हैं तो हमने कोई न कोई खेल खेला है, चाहे गुल्ली-डंडा खेला है, चाहे खो-खो खेला है, चाहे हॉकी खेला है, हमने कोई न कोई खेल खेला है। ... (व्यवधान) हम सभी के अंदर एक खिलाड़ी का दिल होता है। एक खिलाड़ी के दिल में यह बात होती है कि वह खेल और खेल की भावना को साथ में रखता है। वह जाति और मजहब की बात नहीं करता है। ये लोग बेटी बचाने वाली बात करेंगे, जिन्होंने सीता मां का आज तक कोई भी सम्मान नहीं किया। जो कभी सीता-राम नहीं बोलते, वे बेटी का सम्मान करेंगे। ऐसी अपेक्षा मैं इनसे नहीं रखता।

मैं आशा करता हूँ कि अगले सत्र में वर्ष 2028 में ओलम्पिक्स में क्या करेंगे, उसकी तैयारी के बारे में यहां आकर बताएं, तब मैं समझूंगा। हालांकि ये तब तक रहेंगे या नहीं रहेंगे, इनकी हालत दुनिया जानती है। साथ में ललन जी बैठे हुए हैं, इन्होंने डिमांड कर दी है। दुकान के बाहर नाम लिखने की जो बात आ रही है, इसके लिए डिमांड चालू कर दी है कि इसे हटाओ। मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

(इति)

1624 hours

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, the modern Olympic Games are leading international sports events featuring summer and winter sports competitions in which thousands of athletes from around the world participate. India has the world's largest population which is one-sixth of the global population and India is the 9<sup>th</sup> largest economy. We also have the biggest democratic existence. The question arises, despite having a population of over a billion, why India lags behind in the race of Olympic glory.

(1625/SRG/NK)

Every self-respecting Indian knows that India's strike rate at the Olympics has been less than encouraging.

After a century since its first participation in Olympics, India, a nation with a population of 1.3 billion has merely 28 medals to its name. The United States of America, on the other hand, leads the medal tally with 2,522 medals. This clearly is not the case of population of a country which can be said is directly proportional to the number of medals.

India has managed to put a man in space, led many scientific discoveries, forced the world to acknowledge India's stride in the field of defence and science & technology. Indian cricket team is considered to be one of the world's best teams. Why are we not able to bring the same dedication and integrity to sports in general and the Olympic Games in particular? In fact, being the second most populous and the most democratic country in the world hinders our attempts to harvest a rich haul of medals at the Olympics.

Now let me discuss this in detail. Where does India lack in the Olympic competition? We give a lot of importance to cricket. We, as a country, are obsessed with a singular sport and that is cricket. It is only during major events like Olympics when other sports are given a part of the limelight and fan cheering. For the rest of the year, we stay ignorant of who's who of other sports. They are promoted less and there are fewer sponsors for the other sports. There are even less fans hooting and cheering them to do better.

Sir, we do lack proper infrastructure, and sports infrastructure in particular, for training and practice sessions of athletes that could make them more competent and well equipped to deal with world class competitors. It would have

been far better if our athletes could get access to better infrastructure and get to play all across the country to stay practised.

Heads of sports organizations are simply people favoured by the Ruling Party. They have no idea of the sports or their necessities and have chosen to leave the people who are serious about sports.

There is lack of encouragement. Right from the very beginning, youth in India are discouraged from pursuing a career in sports. Our parents are obsessed with the likes of medical and engineering education. And for girls, the scenario is even worse with the list of drawbacks and hindrances they have to face before they could persuade their parents to allow them to play. Most of them are forced to quit sports in order to do something that would give them better job security.

Sir, athletes do not receive proper funding to meet their needs. Sportsmen do not have constant source of income and no help is given by the Government in their early stages of training. Some researches prove that the athletes of the leading nations are genetically and physically fitter than our people. They get proper nutrition that is required for a sportsperson with all the necessary elements while our athletes rely on their own little efforts to stay strong and fit.

Sir, poor administration is also another reason. No proper governing of administrative issues is the prime concern with Indian sports. Non-involvement of ex-sportsmen in administrative staff is also a major reason why India lacks in this sector. Our economy has been prospering and allotment of funds to different fields of development has been improving with each year's budget. However, there is still relatively very less allotment of funds for sports given the sheer number of youths who are willing to take up sports seriously. We have got IITs and IIMs, but when will we get a dedicated sports university?

We, as a nation are corrupt to the core regarding sports. Corruption in sports ensures that affluent candidates score over talented candidates and that is what refuses to recognize dedicated and talented sportsmen from smaller cities.

Now, I will list out the improvements required that can be done to put our India on the top edge of the Olympic awards. Khelo India Youth Games, held annually in January or February, are the national level multidisciplinary

grassroots games in India held for two categories, namely under-17 years school students and under-21 college students. Every year nearly about 1,000 kids are given scholarship from Rs. 5,00,000 to Rs. 8,00,000 which is not sufficient.

(1630/RCP/SK)

India, being a developing country, cannot invest a major part of its economy in sports. India has a huge number of industrialists and businessmen who can easily take up responsibilities to encourage these talented athletes. We see a lot of marriages and public events sponsored by great business people. We have business magnates in India. But when it comes to sports, the sponsorship is lacking.

There is another big reason why our sportsmen are not achieving. It is because of criticism. There is a lot of criticism about the performance of Indian athletes over the years. This decreases their morale. The point is that if we cannot support them, let us not criticize them. You do not know their stories, their food facility, coaching, support and money. Still, they made it to the Olympics to compete with the ones who were trained, supported and recognized well by their respective country or the Government.

We might have a lot of Dhonis, but it is difficult to find more Mary Koms and Sania Nehwals owing to the gender discrimination that has paved its way into sports. Sports and women are the two opposite ends of a pole. The society does not encourage girls to be an active part of sports. Moreover, they are considered to be delicate creatures and their potential in sports is questioned. This should be stopped. There should be special policies to encourage participation of women in sports.

We are lacking in having transparency in the system. The selection process of players and Board members needs to be more transparent. The head post of sports-governing body should be given to an ex-sportsman. This will create job opportunities for sportsmen as well. Players should be only judged upon their performance and not on any other factors. More than the nation, the States have to participate a lot in development of the sports.

In Tamil Nadu, our Sports Minister Shri Udhayanidhi has been a favourite Minister among the youth in Tamil Nadu. He has been promoting all the games

in Tamil Nadu. He hosted Khelo India Youth Games which brought great joy to Tamil Nadu. He hosted a number of national and international sporting events since 2021, including the 44<sup>th</sup> Chess Olympiad, the Squash World Cup 2023 and the Chennai Open Challenger.

The Tamil Nadu Government is also planning to construct six stadiums for para-athletes, which is happening for the first time in the country. Setting up of Olympic academies in Chennai, Tiruchi, Madurai and Nilgiris, and the establishment of the Tamil Nadu Sports Science Centre at Jawaharlal Nehru Stadium in Chennai are among the effective measures being taken by the Government to improve sports in the State. Tamil Nadu's traditional sport of Silambam has also been included and taken up by the Government, which is a welcome initiative.

Our Sports Minister Shri Udhayanidhi has also hosted the Chess Olympiad which has triggered a lot of youth and they have all started practising chess. Tomorrow, we will have a lot of chess competitors, participants to take part in international competitions. In Tamil Nadu, all our party members, including DMK, and also Members of Parliament as well as MLAs, are distributing sports kits. Our Youth Minister has instructed us to promote sports in various areas.

To conclude, I would like to appreciate this Government also because I came to know that this is the first time that the Ministry of Defence has announced that 22 male and two female athletes from the Defence sector are participating in the upcoming Olympic Games. This is a great news to us because participation of Defence sector in the Olympic Games has to be applauded.

Encouragement has to be given from the Indian Government. Olympics is not just sports. It is not only participation, but it is also an exhibition of talent. There are a number of youths in villages, in cities, in every nook and corner of India where they have to be found out and they have to be trained. I am a horse rider.



(1635/PS/MK)

I know how good an equestrian sport is. When you take up horse riding, there are two parts in it. One part is the training for the riders and another one is the training for the horses. We have a lot of good riders but we lack in trainers for the horses. Good horses have to be procured. Where is the training academy for the equestrian sport in India?

When we talk about academies, a lot of academies have to be promoted. Who is going to sponsor for young athletes who are going for the Olympics or any other National Game? So, the Government has to find it out. We have to leave away our politics aside. When it comes to India, it has to have an international value.

Definitely, our Indian team will perform well in the upcoming Olympics, and I hope they will claim more medals in honour of India. Secondly, in the upcoming Olympics, definitely, our youth have to participate, and these youths have to be identified.

The Government has to take up the responsibility of identifying youth in each and every corner of India, and they have to be trained and they have to be put across in the Olympic competition. If it is done, they will definitely bring laurels to India.

Thank you for giving me the opportunity.

(ends)

1636 hours

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): Hon. Chairperson, Sir, today, I stand before you with immense pride and joy as we celebrate and send our heartfelt congratulations to the Indian contingent heading to the Paris Olympics 2024. Under the leadership of our hon. Prime Minister Narendra Modi ji, we have seen a remarkable transformation in Indian sports especially with regard to sports infrastructure and development.

On behalf of our Party leader Shri Nara Chandrababu Naidu ji and Telugu Desam Party, I would like to begin by congratulating all our sportspersons who are representing our nation at the Olympics to be held in Paris. I am sure that all of us here, along with the rest of our brothers and sisters in India and across the world, will cheer and support our sportspersons as they bring even more glory to our country.

Our country has a long and vibrant association with Olympics. Right from its modern-day *avatar* in 1900s when a sole sportsperson and that too a Britisher represented India to the current contingent of 117 sportspersons, our country has grown tremendously and is currently on the right track to become one of the leading nations in the Olympics. I am extremely proud of all the athletes especially those from Andhra Pradesh such as, Satwik Sairaj from Amalapuram in badminton; Dhiraj from Vijayawada in archery; and Jyotika from Tanuku and Jyothi from Visakhapatnam in athletics.

Andhra Pradesh has a proud history when it comes to Olympics with sportspersons such as Karnam Malleswari ji – first Indian woman to win an Olympic medal, P.V. Sindhu and various others. Each and every one of them has made us extremely proud.

As the MP from Amalapuram, it fills me with immense pride to see our Satwik Sairaj representing India. Our Chief Minister Chandrababu Naidu ji has always been a staunch believer in the power of sports and a relentless enabler of athletic talent. The glory of Indian badminton is a testament to his visionary support for sports. The foundations laid and the support given to badminton during his tenure, have resulted in remarkable achievements we see today.

Hon. Chairperson, Sir, I firmly believe that to harness the true potential of our Indian sportspersons, we must continue to establish and enhance sports infrastructure across the nation. The Modi Government has made significant

strides in the direction over the last decade. The 'Khelo India Initiative' which identifies and nurtures sports talent from schools is a commendable step. However, to build a long-term vision for Indian sports, we need to accelerate our efforts. For example, under the 'Khelo India Initiative', our State was to have ten sports infrastructure projects, of which only two have been completed; four are under progress; and four are yet to start. In our people's capital, Amravati, our Chief Minister Nara Chandrababu Naidu ji has planned an ambitious sports city. (1640/SMN/SJN)

This city is envisioned to be a hub for nurturing talent and will include a world-class sports university. Our HRD Minister, Nara Lokesh Garu, has been a vocal advocate for sports education and the integration of technology into it. He believes that the future of sports infrastructure lies in combining cutting-edge technology with the state-of-the-art facilities to provide world class training for our youth.

Nara Lokesh Ji's vision for sports education, integrated with technology, is paving the way for a brighter future for our athletes. It is crucial that our Government invests in States like Andhra Pradesh which have a clear vision for sports and are aligned with the aspirations of a new India. By doing so, we can ensure that our athletes receive the best possible support and resources to excel on the world stage.

Sir, allow me to speak about my Constituency Amalapuram. I have had the privilege of interacting with many local sports persons at the GMC Balayogi Stadium which is named after my beloved father. He always envisioned state of the art sports facilities for the rural youth to nurture the talent at the grass root level.

Sir, the passion and talent these young athletes possess are truly immense and inspiring. Being a young MP from Andhra Pradesh, I understand the importance of sports in overall development. It is vital that we create opportunities for our youth, not just for their athletic careers but for their personal growth as well.

Moreover, sports are essential for maintaining good health. In a time where sedentary lifestyles are becoming increasingly common, promoting physical activity through sports can help combat various health issues. Encouraging our youth to participate in sports from an early age instils healthy

habits that can last a lifetime. I firmly believe in the importance of sports for the overall development of our youth and shall stand in support of any and all initiatives at the Central and State level for the growth of Amalapuram, Andhra Pradesh and India as a whole.

Respected Sir, I also would like to make specific requests to the State of Andhra Pradesh. We urge the Central Government to support the establishment of a Sports University in Amaravati. This university will be pivotal in providing world class training and education to our athletes, integrated with advanced technology as envisioned by HRD Minister Nara Lokesh Garu.

Andhra Pradesh has a rich history of hosting successful international events, such as the Afro-Asian Games in 2002 under the leadership of Chandrababu Naidu Ji. We request the Central Government to consider Andhra Pradesh as the host for the upcoming National Games, showcasing our State's capabilities and commitment to sports.

Finally, I would also request that my constituency is the home to many passionate and talented athletes. To nurture this talent, we seek funds to update and build sports infrastructure in Amalapuram, particularly enhancing facilities at the GMC Balayogi Stadium.

To conclude, Sir, as we prepare for the Paris Olympics 2024, let us pledge to continue supporting our athletes, building robust sports infrastructure and fostering a culture of sportsmanship and excellence. Gold medals are not made of gold; they are made of sweat, determination, and hard to find alloy called guts. I am sure our current Olympic contingent has an abundance of this alloy and my best wishes are with them.

Thank you and Jai hind.

(ends)

1644 बजे

**श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) :** माननीय सभापति महोदय, नियम 193 के तहत 'आगामी ओलंपिक खेलों के लिए भारत की व्यापक तैयारियां' नामक विषय पर चर्चा चल रही है। खेलों में जो-जो कमियां हैं, उनकी तैयारियों पर यहां निश्चित रूप से चर्चा होगी। भारत के हर एक क्षेत्र में जितने भी खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों के भविष्य के लिए निश्चित रूप से केन्द्र और राज्य सरकार निर्धारित लक्ष्य रखकर कार्रवाई करेगी। मैं ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा। मैं यहां पर सिर्फ दो-चार सुझाव दूंगा।

माननीय खेल मंत्री मांडविया जी इस चर्चा को सुनने के लिए यहां आए हैं। जब मांडविया जी किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी लेते हैं, तो वे पूर्ण रूप एवं अच्छी तरह से काम करते हैं।

(1645/SPS/SM)

मैंने दस साल में देखा है, जिन-जिन मंत्रियों के पास खेल विभाग था, जिनमें किरेन रिजिजू जी, अनुराग ठाकुर जी और अभी मांडविया जी हैं, जिन्होंने इस विभाग को सम्भाला है, इस मंत्रालय को न्याय दिया है और मैं आगे न्याय देने की अपेक्षा करता हूं।

इस देश में ज्यादातर ओलम्पिक में जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या बहुत सारी है, लेकिन मेडल मिलने की संख्या कम है। इस पर प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों से मिलकर विभाग द्वारा जो-जो कमियां हैं, उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। जो खिलाड़ी हैं, उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं सरकार से होती हैं, चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो। जिस उम्र में वे खेलते हैं, तैयारी करते हैं, उनमें कई गरीब परिवार के खिलाड़ी होते हैं, उनको सुविधाओं का अभाव होता है और फाइनेंशियली अभाव रहता है। अगर इस पर सरकार ने ध्यान दिया और पूरी तरह से सपोर्ट किया तो मुझे लगता है कि 140 करोड़ के देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्समैन तैयार हो जाएंगे।

महोदय, भारत को कुश्ती में पहला ओलंपिक कांस्य पदक खाशाबा जाधव ने दिया था। उनके परिवार और उनकी खुद की कई सारी अपेक्षाएं सरकार से थीं, लेकिन वे अपेक्षाएं ही रह गईं। मुझे लगता है कि खेलों में सभी पार्टियां, चाहे वह कोई भी पार्टी हो, उन पार्टियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। खेल एक खेल होता है और हर खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, देश को सामने रखकर खेलता है तो उसमें कोई भी राजनीति न करे। ज्यादातर जो खिलाड़ी होते हैं, वे बाद में राजनीति में आते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में आगे चलकर ओलम्पिक हो या अन्य खेल हों, उनमें खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा सरकार से मदद की अपेक्षा रखता है।

महोदय, मैं सदन को यह भी कहना चाहता हूं कि दस सालों में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अच्छा काम किया है। प्रधान मंत्री के कार्यकाल

में ओलम्पिक खेल वर्ष 2016, जिसे रियो ओलम्पिक के नाम से जाना जाता है, उसमें भारत को दो पदक मिले, जिसमें एक रजत और कांस्य पदक था। वर्ष 2020 में टोक्यो में ओलम्पिक हुए, उसमें सात पदक मिले थे, जिनमें एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की अच्छी स्थिति रही है। उसमें 66 पदक मिले थे, जिसमें 26 स्वर्ण पदक थे। इस तरह से पूरे दस का कार्यकाल देखा जाए तो मोदी सरकार के कार्यकाल में ज्यादा से ज्यादा इस पर ध्यान देकर खेलों के प्रति अच्छा काम हुआ है। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर फौरन योजना बनाने की आवश्यकता है।

महोदय, ग्रामीण इलाकों के कई खिलाड़ी होते हैं, जिनको ग्राउण्ड उपलब्ध नहीं होता है, जिनको ज्यादातर सहायता नहीं मिलती है, जिला परिषद से मिलने वाली सहायता नहीं मिलती है। मैं सरकार से स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट रखने की मांग करता हूँ। सब अपेक्षा रखते हैं कि ओलम्पिक या अन्य खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने में ज्यादा से ज्यादा मेडल मिल जाएं।

सभी सरकारें, चाहे राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो या केन्द्र में किसी भी पार्टी की सरकार हो, उनके द्वारा आगे चलकर ज्यादा से ज्यादा खेलों के प्रति प्रावधान किया जाए। जो खिलाड़ी खेलता है, उसको आश्वासन होना चाहिए और उसको सरकार से उसको अच्छा भविष्य मिलना चाहिए कि खेलों के प्रति खेलने के बाद उनके लिए नौकरी हो, अन्य साधन हों, एक अलग से कोटा रखा जाना चाहिए। हमें सरकारों के साथ मिलकर ऐसा करना चाहिए।

मुझे लगता है कि सभी खेलों में जो-जो कमियां हैं, उन पर इस चर्चा के द्वारा केवल चर्चा न करके एक अच्छा कार्यक्रम बनाकर खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश की जाए। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

धन्यवाद।

(इति)

(1650/MM/RP)

1650 बजे

**श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) :** सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे ओलंपिक्स की चर्चा पर भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, सबसे पहले मैं पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। यह देश और खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। हम उनका पुरजोर समर्थन करते हैं। हम आशा और उम्मीद ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास रखते हैं कि हमारे खिलाड़ी देश के लिए अनेक मेडल लेकर आएंगे।

महोदय, मैं एक-दो बातों का जिक्र यहां करना चाहूंगा। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहते हूँ कि जो बच्चे-बच्चियां हमारे देश के लिए मेडल लाने का काम करती हैं, उन्हें अपने ही देश में इंसाफ पाने के लिए रोड पर बैठना पड़ता है और उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे देश को लज्जित होना पड़ता है।

महोदय, 'खेलो इंडिया' के तहत 1047 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया है। 'खेलो इंडिया' के माध्यम से हम सरकार से और माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि जब 'खेलो इंडिया' की बात आ रही है तो खेलो इंडिया का बजट देश की सभी पंचायतों में जाना चाहिए। सभी जगह खेल के लिए केन्द्र सरकार का योगदान हो ताकि हमारे सुदूर इलाके से, हमारे गांव से, बच्चे-बच्चियां अपनी प्रतिभा को, जो गांव में दबकर रह जाती है, उसे राज्य और देश में दिखाने का अवसर प्रदान हो।

महोदय, हम एक बात और कहना चाहते हैं, जैसा कि संजय जायसवाल जी ने कहा कि ओलंपिक गेम्स होस्ट के लिए अहमदाबाद में सर्वे करवाया जा रहा है। हमारा एक आग्रह होगा कि हम पिछड़े राज्य बिहार से आते हैं। यह इंटरनेशनल जगह है। राजगीर में स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा है और वहीं, बगल में, बोधगया है, जहां मगध यूनिवर्सिटी भी है और बड़ा खेल का मैदान भी है। अगर उस जगह का चयन सरकार ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए करे तो मैं समझता हूँ कि पिछड़े राज्य के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।

महोदय, दूसरी बात है कि जिस राज्य से मैं आता हूँ मुझे यह देखकर दुख होता है कि पेरिस ओलंपिक्स में वहां से एक भी खिलाड़ी नहीं है। यह मेरे राज्य में खेलों की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। कहां पर कमी है? स्टेडियम का निर्माण सभी जगह पर हो रहा है। हाल ही में बिहार के एक स्टेडियम की तस्वीर वायरल हुई, क्योंकि यह स्टेडियम बहुत ही खराब स्थिति में था। ये बातें सिर्फ बिहार की ही नहीं हैं। यह अमूमन सभी जगह है। हमें पूरे देश में खेल के मैदानों, स्टेडियमों और प्रशिक्षण सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव करने की आवश्यकता है। हमें अनुभवी प्रशिक्षकों और कोचों की नियुक्ति करने और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए आधुनिक प्रशिक्षण विधियों में निवेश करने की आवश्यकता है। हमें स्कूलों और समुदायों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार का 'खेलो इंडिया' के तहत जो बजट है, देश के सूबों की पंचायतों तक जाए। खासकर महिलाओं की इसमें अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

(1655/YSH/NKL)

1655 बजे

**श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) :** महोदय, यह विषय एक न्यूट्रल विषय है। इसमें राजनीति की कितनी गुंजाइश है, यह मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इस विषय को राजनीति से बाहर रखने का प्रयास करूंगा।

सबसे पहले मैं सोच रहा था कि हम जो ओलंपिक्स कहते रहते हैं, यह शब्द आया कहां से है? इसमें भी ईश्वर की प्रेरणा है और मुझे पता चला कि ग्रीस में एक गोडेस थीं और वह क्वीन ऑफ गोडेस कहलाती थीं। उनकी स्मृति में वहां पर हर चार सालों में खेल होता था और वहीं से यह शब्द उभरकर आया। आहिस्ते-आहिस्ते इसकी परिभाषा बदलती चली गई। वह खेल प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। वह गुणवत्ता के नाम से देखा जाने लगा। एक तरह से सौम्यता का वातावरण पैदा करने के लिए दुनियाभर में एक मानक स्थापित हुआ। वहीं से बढ़ते-बढ़ते इसी भगवान की प्रेरणा से लगभग 776 बी.सी. में पहले ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया और उसके पश्चात लगभग कई हजार वर्षों तक ओलंपिक्स नहीं हुआ। उसके पश्चात पहला ओलंपिक्स जो पूरी दुनिया में हुआ, वह 1896 में हुआ। वह सिर्फ यूरोपियन देशों के लिए था। उसके बाद उसमें अमेरिका का प्रवेश हुआ और फिर धीरे-धीरे पूरी दुनिया के लिए वह खोला गया। आज एक खास कैलेंडर पूरे भारतवर्ष के सामने भी है और पूरी दुनिया के सामने भी है। सन् 1896 में पहला ओलंपिक्स हुआ। उसके बाद दूसरा ओलंपिक्स सन् 1900 में पेरिस में हुआ। उसके पश्चात तीसरा ओलंपिक्स भी पेरिस में हुआ और अब जो हो रहा है, 124 वर्ष के बाद फिर से पेरिस में हो रहा है। आप देखिए कि कितने दशक निकल गए हैं। **So many generations have passed, and the ethics of Olympics remain the same.**

पूरी दुनिया में ओलंपिक्स दो या तीन बार नहीं हो पाया। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय नहीं हो पाया था और दो बार जब ओलंपिक गेम्स नहीं हुए, वह वर्ल्ड वॉर - टू का समय था। लगभग सन् 1940 और सन् 1944 में ओलंपिक गेम्स नहीं हुए। दुनिया के इतिहास में मात्र तीन बार ओलंपिक गेम्स नहीं हुए हैं। उसके बाद ओलंपिक्स की श्रृंखला में भी परिवर्तन आया। फिर ओलंपिक्स एक ही समय में दो स्थानों पर हुआ करता था। पहला, जहां पर गर्मी होती थी, उसी समय होता था। दूसरे क्षेत्र में जहां ठंड होती थी, वहां विंटर ओलंपिक्स के नाम पर एक ही समय में दो स्थानों पर होने लगा। उसके बाद सन् 1994 में यह प्रथा बदल दी गई। इस प्रथा को बदलने के बाद उसमें यह तय हुआ कि हर दो साल में ओलंपिक्स होंगे। समर ओलंपिक्स भी दो साल के अंतराल में होगा और विंटर ओलंपिक्स भी दो साल के अंतराल में होगा।

अभी हमारे मित्र लोग कह रहे थे कि हमारी तैयारी नहीं है। हो सकता है कि हमारी तैयारी न हो, लेकिन कम से कम अगली बार जो विंटर ओलंपिक्स होने वाला है, उसमें हम सब लोग मिलकर अच्छी तैयारी करवा देते हैं तो शायद आप सब भी चलेंगे। हम सब लोग सदन में बैठेंगे तो कम से कम हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी और हम विंटर ओलंपिक्स की तैयारी अच्छी करवा लेंगे।

भारत की भागीदारी ओलंपिक्स में कब से है? यहां पर जब अंग्रेजों का राज था तो सबसे पहले भारत की ओलंपिक्स में भागीदारी अंग्रेजों के शासन के दौरान सन् 1900 में हुई थी। यानी कि आज से लगभग 124 साल पहले हुई थी। उस समय भी एथलेटिक्स में नॉर्मन नाम का व्यक्ति था, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था और उसे एक सिल्वर मेडल मिला था। आप सोचिए कि सन् 1900 में जब हमारा देश आजाद नहीं था और इतना ही नहीं, आजादी के पहले भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल मिला था। आजादी के तुरंत बाद सन् 1948 में भी भारत को गोल्ड मेडल मिला था।



(1700/RAJ/VR)

अब हमें वर्ष 1948-50 के बारे में सोचना होगा। अब आप कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं। वर्ष 1950 से लेकर वर्ष 2014 तक हॉकी में कभी गोल्ड मेडल लेकर नहीं आए। उस समय हमारा शासन नहीं था। अब आप यह कहेंगे कि उनका शासन था, इनका शासन था। मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहते हूँ। हम सवा सौ करोड़ भारतीय देश में एक स्थान पर बहुत आगे थे, लेकिन उसके बाद से हम लोग नीचे चलते आए। हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। हम लोग जमशेद जी टाटा के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग भारत में सबसे पहले उस व्यक्ति का स्मरण जरूर करें, जो टाटा परिवार का शीर्ष हुआ करते थे। वर्ष 1920 में, यह बात कहने योग्य है कि आजादी के पहले इस देश में दोराब जी टाटा, जो जमशेद जी टाटा के समृद्ध पिता थे, उन्होंने ओलंपिक्स कमेटी का गठन किया। जिमखाना क्लब पुणे में ओलंपिक्स के खिलाड़ियों का सबसे पहले ट्रायल किया गया। सबसे पहले भारत के पांच लोगों के कंटिन्जेन्ट्स इंटरनेशनल ओलंपिक्स में गए। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए। कई बार मैं पॉलिटिक्स के बारे में सोचता हूँ कि हम नेताओं के साथ क्या कमी है और कई बार हम कहते हैं कि प्रशासक हम पर हावी है। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम पर प्रशासक हावी नहीं है। वह क्षेत्र स्पोर्ट्स का है। जितने ओलंपिक एसोसिएशंस, जितने स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं, ये किसी अधिकारी के हाथ में नहीं हैं। ये सब नेताओं के हाथ में हैं, जो हमारे और आपके जैसे लोग स्पोर्ट्स एसोसिएशंस से जुड़े हुए हैं। यही कारण होता है कि कई बार हम लोग पॉलिटिक्स में पीछे छूट जाते हैं और जब हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी ब्यूरोक्रेसी पर बढ़ जाती है। यही मूल कारण है कि आज जब हम स्पोर्ट्स को देखते हैं, तो एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि आपकी सरकार क्या कर रही है, उसको यह करना चाहिए। एक क्षेत्र नेताओं के हाथ में है। हम नेताओं के ऊपर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। अभी हम लोग सबसे बड़ा स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स करके आए हैं। हम चुनाव में चुन कर यहां आए हैं। यहां कोई गुजरात से है, कोई सूरत से है, कोई पुडुचेरी से है, कोई अमृतसर से है, कोई दमन-दीव से है, कोई केरल से है, कोई लक्षद्वीप से है, कोई कोल्लम से है। हम सब पूरे भारतवर्ष में ओलंपिक्स करके आए हैं। सब अपने-अपने तरीके से यहां आए हैं। न तो मैं इनकी भाषा जानता हूँ, न ही मैं तेलगू, मलयालम, गुजराती और न बंगाली बोल सकता हूँ और न ही आप भोजपुरी और मैथिली बोल सकते हैं। दुनिया का एक ही प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ा ओलंपिक्स का भारत में जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, वह भारत का इंडियन पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट में शायद लोग समझ न पाएं, लेकिन जिनकी भाषा अलग हो, जिनकी बोली अलग हो, जिनका रहन-सहन अलग हो, जिनका पारिवारिक परिवेश अलग हो, पूरे भारत के प्रतिनिधि यहां आकर बैठते हैं। दुनिया में ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं होगा, जहां 125 करोड़ के प्रतिनिधि, आप कन्नड़ बोलते हैं, आप तेलगू बोलते हैं, आप गुजराती बोलते हैं, आपका खान-पान अलग है, लेकिन हम सभी एक-दूसरे की बात सुनने के लिए यहां आते हैं। अगर यह प्लेटफॉर्म हमारे बीच में से एथलेटिक्स नहीं तैयार करके ओलंपिक्स खेलों में पहुंचा सके, तो शायद चिंता का विषय है और उस पर सब लोगों को विचार करना चाहिए।

महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि कई सारे ऐसे विषय हैं कि स्पोर्ट्स के मामलों में हम सब लोगों के बीच में राजनीति कुछ अधिक है। जब हमें वर्ष 1947 में आजादी मिली तो उस समय पहली बार हमारे 86 लोगों का कंटिन्जेंट गया। उसमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, हॉकी, फुटबॉल, स्वीमिंग और वाटर पोलो थे, तब इस देश में इतने सारे स्पोर्ट्स थे, लेकिन उसके बाद हम उसको गति नहीं दे

पाए। इसलिए हमें थोड़ी चिंता जरूर होगी। हम सभी को कुछ आंकड़े अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि हम सब बच्चों के बीच में बैठते हैं, स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, तो प्रेरणा देने के लिए बातें कहनी ही पड़ेंगी। उनका उत्साह बढ़ाना ही होगा। अब आप इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। हमारी सरकार लगभग 10 साल और पांच साल आगे और आगे न जाने कितने वर्ष रहेगी, हम लोगों ने आजादी के बाद से आज तक मात्र 26 मेडल्स जीते हैं। वर्ष 2014 के बाद 9 मेडल्स, मैं नहीं कहता हूँ कि यह बहुत बढ़िया है, लेकिन समकक्ष रूप से हमारे देश में स्पोर्ट्स का विस्तार हो रहा है और हमारे खिलाड़ी अच्छा भी कर रहे हैं।

1705/VB/SAN)

हम सब लोगों को याद रखकर कहीं-न-कहीं तुलना भी करनी होगी और वह तुलना इस प्रकार से है। जमैका, जिसकी आबादी 28 लाख है, वह लगभग 88 मेडल्स ले जा चुका है, जिनमें से 26 गोल्ड मेडल्स हैं। इथियोपिया की आबादी 126 मिलियन है, वह हमारे बिहार से भी छोटा देश है, वहाँ लगभग 58 मेडल्स आए हैं, जिनमें से 23 गोल्ड हैं। साउथ अफ्रीका, जिसकी आबादी 60 मिलियन है, वह हमारे जिले से, यानी सारण से लगभग दो गुना साइज़ का होगा, वहाँ लगभग 91 मेडल्स आए, जिनमें से 27 गोल्ड हैं। ताइवान की आबादी 23 मिलियन है, जिसने 120 मेडल्स लाए हैं, जिनमें से 28 गोल्ड हैं। आप अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रशिया आदि देशों का छोड़ दीजिए क्योंकि यह सूची अलग है। हम लोग अपने आप को कई बार कमजोर भी महसूस करते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आने वाले दिनों में हमारे बीच में जो प्रतिस्पर्धाएं हैं, उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे।

महोदय, इसका एक वाणिज्यिक दृष्टिकोण भी है। अगर आप एक ओलम्पिक्स की तैयारी करते हैं, तो उस देश में जो निवेश आता है, अगर हम लोग लंदन ओलम्पिक्स को देखें, तो तीन साल के भीतर सवा लाख करोड़ रुपए का निवेश आया, रियो का देखें, जहाँ ओलम्पिक्स हुआ, वहाँ लगभग 1 लाख 12 हजार करोड़ रुपए का निवेश आया, टोकियो ओलम्पिक्स में एक लाख सात हजार करोड़ रुपए का निवेश आया। इस तरह से, ओलम्पिक्स में बहुत निवेश आता है। इसके साथ-साथ, आने वाले दिनों में कई चीजों का विस्तार भी होता है।

कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, उसमें कमियाँ हुई होंगी, जाँच कमेटी बैठी होगी, लोग जेल गये होंगे, लेकिन अंततोगत्वा हमें इस बात का तो स्मरण करना ही होगा कि एक बड़े इवेंट के आने के कारण, मुझे याद है जब मैं वाजपेयी जी की सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर था, उस समय बात हो रही थी। यह कॉमनवेल्थ गेम्स शायद वर्ष 2010-11 में हुआ था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गया, तो मैंने उनसे कहा, उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स की चर्चा शुरू हो गई थी, उस समय ब्रजेश मिश्रा उनके प्रिंसिपल सेक्रेट्री हुआ करते थे, उनके सामने बात हो रही थी। मैं उस समय भारत सरकार में नया-नया मंत्री बना था और मेरे पास सिविल एविएशन का प्रभार था। जब मैंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, उसमें हमें नये एयरपोर्ट्स की जरूरत होगी, तो वाजपेयी जी ने उस विषय को सुना। उन्होंने कहा कि रूड़ी जी यह क्या कह रहे हैं, मैंने कहा- साहब, बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए इन्हें प्राइवेटाइज करना होगा। उस समय वर्ष 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि रूड़ी जी जो बात कह रहे हैं कि अगर देश को बढ़ाना है, देश में कॉमनवेल्थ गेम्स होगा, देश में ओलम्पिक्स होगा, तो हमें खूबसूरत हवाई अड्डों की जरूरत पड़ेगी। उसी दिन चाहे दिल्ली या मुंबई का हवाई अड्डा हो या बंगलुरु-देवनाली हवाई अड्डा हो या शमसाबाद-हैदराबाद हवाई

अड्डा हो, उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी नींव रखी क्योंकि उन्हें लगा कि आने वाले दिनों में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्ष 2036 के लिए ओलम्पिक गेम्स का बिड करना चाहते हैं। भारत में गुजरात भी है, बिहार भी है... (व्यवधान) आपने कहा बिहार में, हमारे मित्र वहाँ बैठे हुए हैं। मेरा चुनाव तो राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध था। उससे आप चार लोग जीतकर आए हैं। मैं भी पिछले 40 सालों से उसी पार्टी से लड़ रहा हूँ। लेकिन थोड़ी पढ़ाई-लिखाई तो जरूर करनी चाहिए और अपने राज्य के प्रतिभाओं को पहचानना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार से ओलम्पिक्स में कोई भी खिलाड़ी नहीं गया है। महोदय, आपसे विनती है कि हमारी एक बेटी है, जो बिहार में एमएलए है, उसका नाम श्रेयसी सिंह है, वह पेरिस ओलम्पिक्स में ट्रैप शूटिंग में जा रही है। इसलिए आप उसमें संशोधन कर लीजिए। आप भूल गये हैं। वह हमारी बेटी है। दिग्विजय सिंह सांसद हुआ करते थे, वह उनकी बेटी है। वह ट्रैप शूटिंग में परफॉर्म करती है और वह हमारे यहाँ एमएलए है, जो वहाँ जा रही है। इसलिए आप थोड़ा संशोधन कर लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा पढ़ाई-लिखाई शुरू कीजिएगा तो ठीक-ठाक रहेगा।

लेकिन राजनीति में इतना चलता है। कोई बात नहीं है। हम लोग थोड़े सीनियर हैं, आप लोग आए हैं, तो हम लोग गाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-बहुत तो चलता ही है।

आप लोग मेरिट की बात कहते हैं। हमारे सामने टोपी पहनकर एक व्यक्ति बैठे हैं, हाउस में किसी को पता ही नहीं है, इस सदन में भी तो ओलम्पियन बैठा हुआ है। यहाँ पर प्रसून बनर्जी साहब बैठे हुए हैं, ये भी ओलम्पिक्स के खिलाड़ी हैं, इनको बधाई देनी चाहिए। इसके साथ ही असलम शेर खान हैं, जो मंत्री भी रहे, वे हॉकी खेलते थे और वे भी ओलम्पियन रहे हैं। पी. टी. ऊषा हमारे बीच आईं, वे एथलेटिक्स में आईं, वह भी ओलम्पियन रही हैं। हमारे बीच में डॉ. करणी सिंह, जो वर्ष 1952 से 1977 तक यहाँ रहे, वे बीकानेर से थे।

(1710/PC/SNT)

छ: बार इन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है। रेस्लिंग में 1960 में दारा सिंह जी को कौन नहीं पहचानता? हमारे बीच में राज्यवर्धन जी थे, जो कल तक भारत सरकार में मंत्री थे, आज बड़ी अच्छी सरकार में, जयपुर में हैं। वे वहाँ मंत्री हैं, वे भी ओलंपियन रहे हैं। मैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बारे में कह रहा हूँ। हमारे यहां नेताओं में हुनर का अभाव कहाँ है? लेकिन लोग कई बार छोटी राजनीति में पड़ जाते हैं। अभी तो अगले चुनावों में पांच साल का समय है। थोड़ी बड़ी राजनीति करके इस देश को हम अगले ओलंपिक्स में आगे लेकर चलें। ललन बाबू सामने बैठकर बिहार के बारे में सोच ही रहे हैं। श्री दिलीप तिकी को क्या हम सब भूल गए होंगे? वर्ष 1996 में, वर्ष 2000 में एटलांटा में और वर्ष 2004 में एथेंस में, ये सब लोग ऐसे हैं, जिन लोगों ने यह काम किया है।

अगर राजनीतिक रूप से विश्लेषण किया जाए, तो आप आरोप लगा देते हैं कि दौड़ते क्यों नहीं हो? ओलंपिक्स में बहुत आगे क्यों नहीं हो? 40-50 साल तो तुमने मेरे पैरों में जंजीर बांधकर रखी हुई थी। अब हमने इन दस सालों में जंजीर को खोला है, तो तेज गति से दौड़ने में थोड़ा समय लगता है। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.C. MOHAN): Please conclude the speech.

... (Interruptions)

**श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) :** श्रीमान, आज तो पहला ही दिन है, पांच साल खींचना है। ... (व्यवधान) मेरा आपसे अनुरोध है कि दाएं-बाएं मत सुनिए, आप सीधे मेरी ही बात सुनिए। ... (व्यवधान) दाएं-बाएं सुनने से गड़बड़ हो जाती है। मैं अपनी बात खत्म करने वाला हूँ। अभी तो थोड़ा ही समय हुआ है, अभी तो पांच साल काटने हैं। थोड़ा-थोड़ा करके इंट्रोडक्शन तो होने दीजिए।

सभापति महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं यह कहूंगा कि यह सदन अपने आप में एक ऐसा सदन है, जहां हम सब लोग बहुत मेहनत के बाद आते हैं। ईश्वर की असीम कृपा होती है, जनता की कृपा होती है, तब हम यहां आकर बैठते हैं। लगभग 250-275 ऐसे सदस्य थे, जो हमारे साथ बैठते थे। राजनीति पर इसलिए बोलना जरूरी है, क्योंकि बाकी सब चीजों में फेयरवेल होता है। अफसर रिटायर होते हैं, तो फेयरवेल होता है। टीचर्स रिटायर होते हैं, तो फेयरवेल होता है। पॉलिटिक्स ऐसी जगह है, जहां अगर आप हारे, तो दोबारा आपका दर्शन नहीं हो पाएगा, आपका फेयरवेल नहीं हो पाएगा। जो कैबिनेट मिनिस्टर हारकर चले गए, जो कल तक आगे बैठते थे, जो माननीय सांसद, वरिष्ठ लोग थे, वे हारकर चले गए। अतः यहां किसी का फेयरवेल नहीं होता है। अतः जिस सदन में फेयरवेल नहीं होता है, उसमें कम से कम बोलने की पूरी अनुमति तो देकर रखिए। ... (व्यवधान) लोक सभा, राज्य सभा में थोड़ा माइग्रेशन होता है, लेकिन पॉलिटिक्स में फेयरवेल नहीं होता है, बस 'समाप्त' होता है। चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद जीरो हो जाते हैं, कोई फेयरवेल नहीं होता है।

अतः अधिकारियों से हम लोगों की जब तुलना होती है, तो मार्जिन बड़ा कम होता है। लेकिन जिसका फेयरवेल नहीं होता है, उसकी मान्यता अधिक होती है, क्योंकि हम लोग बड़ा रिस्क लेकर आते हैं, बड़ी मेहनत करके आते हैं। हम पांच-दस सालों तक गांवों-देहातों में उन शब्दों को सुनकर आते हैं। अभी मैंने अपने यहां एक कॉम्पिटिशन कराया, जो कि देश का पहला कॉम्पिटिशन था। मेरे यहां देश का सबसे सुंदर तालाब है, हमने उसको सजाया और उसमें ग्रामीण क्षेत्र की तैराकी प्रतियोगिता कराई। हमारे स्विमर्स वहां दिखाई दे रहे थे, हुनर वहां दिखाई दे रहा था, लेकिन 0.1 प्रतिशत अगर हम लोग पैसा खर्च करेंगे, पैसे का अभाव है, सरकार की अन्य कमिटमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी हम विश्वास दिलाते हैं कि भारत की सरकार, हमारा मंत्रिमंडल, हमारे देश के प्रधान मंत्री की 2036 की तैयारी है। हम सबको मिल जुलकर दुनिया में एक अभियान चलाना चाहिए। मांझी जी, हमें ऐसा अभियान चलाना चाहिए कि पूरी दुनिया में भारत की जो पहचान बनी है, 2036 का ओलंपिक्स भारत में हो, चाहे कहीं भी हो, गुजरात में हो, औरंगाबाद में हो, बिहार में हो, लेकिन यह प्रेरणा और मोमेंटम पूरी दुनिया में हमें बनाना चाहिए।

आज देश में प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा वातावरण बना है। हम सभी सांसदों को खेल के मामले में आगे बढ़-चढ़कर इस देश के उस गौरव को प्राप्त करने के लिए कदम उठाने होंगे। वर्ष 2036 में हममें से कितने लोग यहां रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आज हम योजना बनाएंगे और 2036 की बिड लेंगे, तो शायद यह आपकी और हमारी बात आने वाली तैयारी का गौरव बढ़ा सकेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

धन्यवाद।

(इति)

(1715/CS/AK)

1715 बजे

**मोहम्मद रकिबुल हुसैन (धुबरी) :** माननीय सभापति महोदय, थोड़ी देर पहले हमारी पार्टी ने हमें बोलने के लिए कहा कि आपको खेल के बारे में कुछ बोलना है। हमने सोचा कि अचानक ऐसा क्या आ गया, हम तो एजेंडा देखकर आये थे। बाद में देखा कि सप्लीमेंटरी लिस्ट ऑफ बिजनेस में Discussion under Rule 193 में लिखा है कि Discussion on India's preparedness for the upcoming Olympic games. हमने पार्टी से कहा कि हमें इस पर बोलने के लिए क्यों बोला है? हमसे बोला गया कि आप खेल से जुड़े हुए आदमी हैं, आप खिलाड़ी थे। हम ओलम्पिक असम में ट्रेजरार थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे और जब तरुण गोगोई जी चीफ मिनिस्टर थे, उस समय हम लोगों ने अच्छा करके वहाँ पर स्टेट गेम्स किए थे। उस समय दुनिया के बड़े-बड़े खेल में लगे हुए आदमी आकर बोले थे कि असम जैसे एक छोटे से राज्य में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने कैसे तैयार किया। उस समय फाइनेन्शियल क्राइसिस भी था। हम खेल के लगे हुए आदमी हैं। असम से दो ऑफिशियल और दो खिलाड़ी अभी ओलम्पिक्स में जा रहे हैं। हम उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देकर आए हैं। यहाँ आकर हमने देखा है कि "... preparedness for the upcoming Olympic games". It means that we are not prepared. सरकार से हम दरखास्त करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि यह हेडलाइन थोड़ा गलत है। आप थोड़ा इसे देखिए। यह ऐसा होना चाहिए था : "Best wishes to the participants of the upcoming Olympic games". टीम जा रही है, उसके बाद अगर अभी प्रीपेयर नहीं हैं, आजकल सोशल मीडिया में दुनिया इसे देखेगी तो वे क्या सोचेंगे कि हम लोग प्रीपेयर नहीं हैं। इसीलिए हम आपके जरिये सरकार से दरखास्त करते हैं कि यह जो India's preparedness for the upcoming Olympic games के बारे में लिखा है, उसे चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, उसे आप देखिए।

सर, हमने बोला है कि हम खेल से जुड़े हुए आदमी हैं, इसीलिए हम सिर्फ बेस्ट विशेषज्ञ देंगे, प्रीपेयर्डनेस के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि all are prepared. हम लोग जानते हैं कि इंडिया की परफॉरमेंस अच्छी होगी, मेडल्स भी हम लोग अच्छी तरह से जीतेंगे, यह हम लोगों की बेस्ट विशेषज्ञ हैं। हम अपने को खेल से जुड़ा हुआ आदमी बार-बार बोल रहे हैं, इसीलिए हम एक बात बोलना चाहते हैं। हम अभी ओलम्पिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम जो बोलना चाहते हैं, वह विषय हिन्दुस्तान के आम आदमी के खेल के बारे में है। हम गरीब लोगों के खेल के बारे में बोलना चाहते हैं, जिसकी हिन्दुस्तान में उत्पत्ति हुई। हम ऐसे एक खेल के बारे में बोलना चाहते हैं। उस खेल का नाम कैरम है। बहुत लोग कैरम के ऊपर हँसते हैं। आज कैरम की चर्चा होने के बाद हमारे जो गरीब लड़के हैं, जो गाँव में अच्छा कैरम खेलते

हैं, उन लोगों को भी थोड़ा अच्छा खेलकर घर चलाने का एक माहौल बनाने का अवसर मिलेगा। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि कैरम खेलने के बाद नौकरी मिलती है। नौकरी कहाँ-कहाँ मिलती है, एयर इंडिया में कैरम के खिलाड़ी को नौकरी मिलती है, बीएसएनएल में नौकरी मिलती है, कैंग में नौकरी मिलती है, डीएसएसएसबी में मिलती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में मिलती है, इरिगेशन में मिलती है, एलआईसी, एसबीबीपी में मिलती है, मेजर पोर्ट्स पर नौकरी मिलती है, नाबार्ड, स्पोर्ट्स एंड कल्चर में नौकरी मिलती है, पीएसयूज में मिलती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मिलती है, एएआई, आदि में मिलती है। इसे गरीब लड़का, लड़की खेलते हैं। यह भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं, हम जानते हैं कि कैरम खेलकर अर्जुन अवार्ड भी मिलता है। तमिलनाडु के मरिया इरुदयम को अर्जुन अवार्ड मिला है। आप जरा चेक कर लीजिए।

(1720/IND/UB)

सभापति जी, मैं इसीलिए आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रिप्रेशन्स की गई हैं, वे ठीक होंगी।

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.C. MOHAN): Other hon. Members are also there to speak. Please conclude.

मोहम्मद रकिबुल हुसैन (धुबरी) : सभापति जी, हमारी पार्टी से एक आदमी बोला है।

माननीय सभापति : अभी दो और माननीय सदस्य भी बोलेंगे। Two more hon. Members are there to speak.

मोहम्मद रकिबुल हुसैन (धुबरी) : सभापति जी, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ। ओलम्पिक्स में जो खेल होता है, वह केटेगिरी-3 में होता है। यह टेक्टिकल बात है। फर्स्ट केटेगिरी को हाई प्रॉयोरिटी कहते हैं। सैंकेंड केटेगिरी को सैंकेंड प्रॉयोरिटी कहते हैं और थर्ड को अदर्स कहते हैं। कैरम खेल अभी तक प्रॉयोरिटी लिस्ट में नहीं है। आपने ज्यादा समय नहीं दिया है, इसलिए अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ। आपने जो क्राइटीरिया रखा है, कैरम उसे फुलफिल करता है।

1721 बजे

(श्री जगदम्बिका पाल पीठासीन हुए)

Sir, despite All India Carrom Federation fulfilling all the criteria of priority category, carrom is still in 'Others' category.

HON. CHAIRPERSON: You have already taken two minutes. Please conclude.

MD. RAKIBUL HUSSAIN (DHUBRI): I request the Government to include carrom as a priority game.

(ends)

1722 बजे

**श्री मलविंदर सिंह कंग (आनंदपुर साहिब) :** सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे एक अहम विषय पर बोलने का अवसर दिया है। हमारे देश की ओलम्पिक्स के लिए जो टीम जा रही है, उन सभी प्लेयर्स को मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश की ओलम्पिक्स में जो परफोर्मेंस रहेगी, वह बेहतर रहेगी।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से दो-तीन बुनियादी चीजें सदन के सामने रखना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी सदन में बैठे हैं। मैं स्वयं स्पोर्ट्स मैन रहा हूँ। जब हम ओलम्पिक्स के लिए पूरे इंटरनेशनल मॉडल को स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि चाइना ने बहुत बेहतर परफोर्म किया है। हमारे यहां जब कोई प्लेयर नेशनल और यूनिवर्सिटी लेवल पर मेडलिस्ट बन जाता है, तब उसे ओलम्पिक्स के लिए प्रीपेयर करते हैं। नर्सरी लेवल पर, कम आयु में यदि हम प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करें तो स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारे देश में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह का टैलेंट है। जेनेटिक का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है, डाइट का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ट्रेनिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर हम पूरे देश के अलग-अलग हिस्सों में जाएं, तो देखेंगे कि कहीं हाइट बहुत ज्यादा है और कहीं किसी अन्य प्रकार का टैलेंट है। यदि हम नार्थ-ईस्ट की बात करें तो वहां फुटबाल का टैलेंट बहुत है। पंजाब की बात करें, तो एक समय ऐसा था कि फुटबाल और हाकी के मैक्सिमम प्लेयर पंजाब से ही रहे हैं। बॉस्केट बाल में हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है। मेरे संसदीय क्षेत्र में बलाचौर एक छोटा-सा विधान सभा क्षेत्र है। हर साल वहां से चार से पांच प्लेयर्स हमारे देश को वॉलीबाल में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक मालपुर शहर है। वर्ष 1970 के दशक में पूरी फुटबाल टीम मालपुर कस्बे की थी, लेकिन वहां भी इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं नहीं हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि छोटी उम्र में पूरे देश में एक ऐसा कार्यक्रम चलाएं और छोटे-छोटे बच्चे आइडेंटिफाई करके, जिनमें टैलेंट है, उनकी ट्रेनिंग, डाइट आदि का खयाल रखें ताकि वे नेशनल, इंटरनेशनल लेवल का कम्पीटिशन लड़ सकें। हम वर्ष 2036 के ओलम्पिक्स के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ और हमारी इच्छा है कि हमारे देश को नुमाइंदगी मिले और भारत उसमें बेहतर प्रदर्शन करके ज्यादा मेडल प्राप्त करके पदक तालिका में दुनिया में पहले तीन देशों में आए।

(1725/GG/SRG)

दूसरा, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, चूंकि स्पोर्ट्स के प्लेयर्स बेसिकली रियल हीरो होते हैं। पंजाब से बलवीर सिंह सीनियर हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए लगातार तीन गोल्ड मेडल्स जीते हैं। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि जो हमारे रियल हीरो हैं, इन लोगों को भारत रत्न देना चाहिए। बलवीर सिंह सीनियर को भारत रत्न देना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिले।

तीसरा, किसी ज़माने में जब हम इंटर-यूनिवर्सिटी खेलने जाते थे या इंटर-स्कूल खेलने जाते थे, तब हमारी भारतीय रेल पूरा रिज़र्वेशन स्पोर्ट्स टीम को देती थी। सर, वह प्रोविज़न भी पिछले कुछ सालों में बंद कर दिया गया है।

चौथा, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो हमारे एसोसिएशंस हैं, मैजोरिटी ऑफ एसोसिएशंस में नॉन-प्लेयर्स अथॉरिटी के हेड बने हुए हैं, जिनको स्पोर्ट्स की बहुत ज्यादा गंभीरता से समझ नहीं है। यह पूरा तौर-तरीका भी बदलने की जरूरत है कि जो रियल प्लेयर्स हैं, वे एसोसिएशंस को भी हेड करें। सर, हो क्या रहा है कि बहुत सारे एसोसिएशंस के मसले हाई कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में लीगल लड़ाई लड़ी जा रही है और हमारे प्लेयर्स उसमें पिस रहे हैं।

**माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) :** आप कृपया संक्षिप्त में सुझाव दे कर अपनी बात समाप्त करें।

... (व्यवधान)

**श्री मलविंदर सिंह कंग (आनंदपुर साहिब) :** सर, मैं कनक्लूड कर रहा हूँ। यह मेरी मेडन स्पीच है। मैं फर्स्ट टाइम हूँ।

\*Sir, this is my maiden speech. I appeal to you to kindly give me more time.

Sir, the 2036 Olympic Games should be hosted by India. Government should do the needful in this matter. Separate clusters of separate regions in the country should be made and local talent should be identified, trained and encouraged. Players who are below 10 years or 15 years should be trained.

I hope that 2036 Olympic Games will be allotted to India and Arvind Kejriwal ji will be the Prime Minister at that time. In Punjab, CM Bhagwant Mann ji has undertaken an initiative. Till, 2000, Punjab was No. 1 in sports. पिछले 20 सालों में अकाली और कांग्रेस सरकारों ने स्पोर्ट्स के लिए कुछ नहीं किया।

The Bhagwant Maan Government is providing jobs to all sportsmen and sportswomen from Punjab who win medals for the country. So, our players who win medals in international games must be provided with jobs. This must be ensured. मेरी भारत सरकार से यही विनती है। धन्यवाद।

(इति)



1728 बजे

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) :** सभापति महोदय, आपने मुझे ओलंपिक्स की तैयारी पर नियम-193 के तहत हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। काफी लोगों के सुझाव आ चुके हैं। ओलंपिक्स की तैयारी के लिए सरकार के द्वारा जो चर्चा कराई जा रही है, उसके लिए मैं मंत्री जी को भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ। हम लोग चौथी बार के सांसद हैं और ओलंपिक खेल होने जा रहे हैं, उस पर चर्चा करने का जो अवसर मिला है, उसके माध्यम से मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ। जब से मोदी जी की सरकार पिछले दस सालों से हैं, तब से 'खेलो इंडिया' के तहत हर गांव, हर प्राथमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल व कॉलेज तक 'खेलो इंडिया' की छाप हर जगह है। हम लोग भी सांसद हैं। लगातार 'खेलो इंडिया' के तहत जहां भी खेल होते हैं, बच्चे और बच्चियां कई तरह के खेल खेलते हैं। उत्साह इससे बढ़ा है। लेकिन पिछले दशक के बारे में अभी रूडी जी विस्तार से चर्चा कर रहे थे कि आजादी से पहले और बाद हम कितना आगे बढ़े हैं, मतलब पीछे हैं, अभी आगे बढ़े नहीं हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग अब वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की तैयारी करें। अगर वर्ष 2024 में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहे तो वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की तैयारी करें। अगर पूरे देश के सांसदों का प्रयास भरपूर रहेगा तो अगले ओलंपिक्स में निश्चित रूप से चार चांद लगेंगे, इसका मुझे भरोसा और विश्वास है। अभी जो लगभग 117 खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए चयनित हुए हैं, उनमें बिहार की भी एक बेटा है। मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग देश के लिए मेडल लेकर आइए। हम लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। खेलों के प्रति लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यह काम सिर्फ भारत सरकार के करने से ही नहीं होगा।

(1730/MY/RCP)

सभी राज्य सरकारों के साथ बैठ कर प्रयास करना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय से लेकर इंटरमीडिएट स्कूलों तक इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलेज और स्कूल में खेलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं। बहुत सारे स्कूलों में खेल का मैदान नहीं है। वहां खेलने की जगह नहीं है। सरकार को इसकी व्यवस्था करने की जरूरत है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि ओलंपिक्स में 117 लोग जा रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि और लोग भी जाएं तथा वहां से मेडल्स लेकर आए। आज जिस तरह से लोगों में उत्साह है, इस उत्साह के लिए बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक खेल नीति बनायी है। अभी हमारे साथी हरियाणा के बारे में बता रहे थे। वहां तो बहुत पहले से ही मेडल्स आ रहे हैं। खेल की नीति बनानी चाहिए कि मेडल्स लाइए और

नौकरी पाइए। यह हमारे बिहार में भी चल रहा है और कई लोगों को नौकरी मिली है। मुझे लगता है कि हजारों लोगों को नौकरी मिली है। वहाँ बच्चों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस तरह से हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को काम करने की जरूरत है। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में मेडल्स लेकर आएंगे तो देश का नाम रोशन होगा। हमारे खिलाड़ी देश के लिए काम करते हैं। वह पूरी तरह से मेहनत करते हैं। चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, वे समर्पित होकर मेहनत करते हैं।

महोदय, हम लोग छोटे खिलाड़ी रहे हैं, हाई स्कूल और कॉलेज के खिलाड़ी रहे हैं। वहाँ हम लोग देखते थे कि खिलाड़ी को पूरे परिवार से कोई मतलब नहीं होता था। वे खेलने में पूरा समय देते थे। जो लोग खेल के प्रति जागरूक हैं, जिनमें खेल के प्रति लगन है, उनको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। हर क्षेत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। कई तरह के आरोप लग रहे थे, आज आरोप लगाने की जरूरत है, बल्कि सरकार, चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की हो, सबको साथ-साथ चलना चाहिए। हमें एक साथ होकर अपने-अपने क्षेत्रों में खेल के प्रति बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हम सब लोग समर्पित हो। इससे हमारा लक्ष्य पूरा हो सकता है। हमारा अगला लक्ष्य वर्ष 2036 का ओलंपिक्स है। निश्चित रूप से खिलाड़ी ज्यादा मेडल्स हमारे देश में आएंगे। इससे हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे। वे निश्चित रूप से देश के लिए काम करेंगे।

महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा। हमारे संसदीय क्षेत्र में जहां अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, उसी के बगल में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है, एकैडमी बन रहा है। इन सभी चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए हम सरकार से आह्वान करते हैं। केंद्र में हमारी सरकार है और बिहार में भी हमारी सरकार है। हमें खेल के प्रति लोगों को सजग करने की जरूरत है। निश्चित रूप से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सरकार हर चीज से लैस करे। इससे गांव के हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। यही बात कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1733 बजे

**श्री चंदन चौहान (बिजनौर) :** धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदय, इस ऐतिहासिक लोकतंत्र के मंदिर में आपने मुझे बोलने का आपने मौका दिया।

मान्यवर, नियम 193 के तहत आज ओलंपिक्स खेलों में भारत की तैयारियों पर चर्चा करने के इस मौके पर आपने प्रथम बार चुनकर आए सदस्य को बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मान्यवर, मैं बिजनौर लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूँ। यहां हमेशा से, चाहे पूरा एनसीआर का एरिया हो, चाहे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया हो, चाहे ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो या देश के लिए कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, हमेशा देश का झंडा बुलंद करने का काम हमारे क्षेत्र के युवाओं और नागरिकों ने किया है। खेलों के विकास के लिए हमारे समाज ने और यहां बैठे सभी लोगों ने स्पोर्ट्स खासकर इस महत्वपूर्ण विषय पर जब चर्चा चल रही है, इस सदन के अंदर भी अगर हम सब मिलकर स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएंगे तो निश्चित रूप से समाज में एक बड़ा संदेश जाने का काम होगा।

मान्यवर, आपके माध्यम से पूरे सदन की भावना आज यहां देखने को मिली है। खेलों में हमारे खिलाड़ी देश के लिए मेडल्स जीत कर लाते हैं। यह सब पूरे देश का गौरव है। इससे पूरे देश के लिए समर्पित होने का काम होता है।

(1735/CP/PS)

आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी ने यहां इसके बारे में अपनी बात कही। हम सब तो इनको देखकर बड़े हुए हैं, चाहे कीर्ति आजाद जी हों, बनर्जी साहब हों, यूसुफ पठान साहब हों, पी.टी. ऊषा जी हो, सचिन तेंदुलकर जी हों, मैरी कॉम जी हों, इन सब लोगों ने इस देश का गौरव बढ़ाने के साथ-साथ सदन का गौरव बढ़ाया है। ये लोग जिम्मेदारी से यहां बैठे हैं। आज जब यहां यह सकारात्मक चर्चा हो रही है, तो आदरणीय प्रधान मंत्री जी की गम्भीरता यहां देखने को मिलती है कि इस विषय पर सरकार कितनी गम्भीर है। चाहे वर्ष 2024 के ओलम्पिक्स हों या आने वाले समय में, जब भारत वर्ष 2036 के ओलम्पिक्स के लिए बिड करने जा रहा है, हम एक राय बनाकर पूरे सदन से संदेश देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश समाज और पूरे विश्व में जाने का काम करेगा।

मान्यवर, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहां स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी बनाने का काम हो रहा है। प्रधान मंत्री जी खुद उस यूनीवर्सिटी का उद्घाटन करके आए थे। यह उनकी गम्भीरता को दर्शाता है। जो प्रतिभायें हमारे देश में गलियों, गांवों में छिपी बैठी हैं, उनको निखारकर आगे लाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता इससे दिखाई देती है। ऐसे समय में अगर उस यूनीवर्सिटी के लिए स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर केंद्र भी गम्भीरता के साथ विचार करेगा,

तो निश्चित रूप से इस कार्य को भी गति मिलने का काम होगा। मैं आपके माध्यम से सदन को इस भावना को अवगत कराना चाहता हूँ।

मैं अपने नेता आदरणीय जयन्त चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर मैं गलत न हूँ तो शायद वे पहले सदस्य होंगे, जिन्होंने अपनी पूरी सांसद निधि खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए समर्पित करने का काम किया। जो राज्य सभा के मंत्री हैं, जितनी भी निधि उन्हें पूर्व में मिली है, उन्होंने सब खिलाड़ियों के उत्थान के लिए दी। उन्होंने हमेशा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। चाहे जगह-जगह, गांव-गांव जाकर प्रोत्साहित करने का काम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे खिलाड़ी जीतकर आए हों, ऐसे समय में हम एक सामाजिक भावना बनाकर चलेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है कि इस पहल पर हम सब मंत्री एकमत होकर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

आप सब लोग सकारात्मक हैं और इस चर्चा में मैं यह कहना चाहूंगा कि बिना द्रोणाचार्यों के एकलव्य निकलकर नहीं आएंगे। यह सच्चाई है कि जो परख डायमंड्स ढूंढने की जौहरी की होती है, वह सभी की नहीं होती। हमारे क्षेत्र में एक से एक द्रोणाचार्य हैं, उनकी परख भी हमें करनी पड़ेगी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि समय की भी सीमा है और यह प्रथम बार है। ऐसा कोई विषय नहीं है, जिसे यहां बैठे सदस्य न जानते हों या कोई नया विषय हो।

खेलो इंडिया की योजना में लगभग 147 करोड़ रुपये बताए गए। हम विकसित भारत के लिए कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी 2047 का विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। भारत को निश्चित रूप से इन मैडल्स की संख्या के साथ-साथ अपना परफार्मेंस बेटर करना पड़ेगा, तभी हम उस संकल्प को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं।

मान्यवर, कोई भी खिलाड़ी जो निपुण होता है, वह बेहतर अवसर कराए जाने से मिलता है। अच्छे मुकाबले मिलना और भव्य मंच अपने खिलाड़ियों के लिए सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। एंड ऑफ दी डे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 'Practice makes a sportsman perfect'.

(1740/NK/SMN)

इस चीज पर ध्यान देते हुए और अपने खिलाड़ियों का जो ओलंपिक्स में जा रहे हैं, मैं उन सभी पार्टिसिपेंट्स का मनोबल बढ़ाते हुए इस सदन को एक भावना और हिम्मत के साथ एक ध्वनि मत से हम सभी को समर्थन करना चाहिए। इस आशा के साथ समर्थन करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा मेडल विश्व पटल पर जीत कर आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

(इति)

1740 बजे

**श्री नवीन जिंदल (कुरुक्षेत्र) :** माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा कंटिजेंट 117 खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। यह हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। इसमें 17 बेटे और 47 बेटियाँ इसमें हिस्सा ले रही हैं। मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा पूरे देश का केवल दो प्रतिशत जनसंख्या है, लेकिन इस कंटिजेंट के अंदर दो प्रतिशत जनसंख्या का योगदान बीस प्रतिशत है। उसमें भी बहुत खुशी की बात है यह है कि इन 24 खिलाड़ियों में 117 का बीस प्रतिशत बनता है, उसके अंदर 14 बेटियाँ हैं, 10 हरियाणा के बेटे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अभी बहुत सारे माननीय सांसदों ने बहुत सारे विचार और सुझाव दिए।

आज की चर्चा का मुद्दा केवल पेरिस ओलंपिक्स का है। मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ, मैं एक सपना देखता था कि मैं भी एक दिन ओलंपिक में जाऊंगा। मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई भी देश अपने खिलाड़ियों को ओलंपिक्स में ऐसे ही नहीं भेज सकता। ओलंपिक्स में जाने के लिए आपको एक कोटा जीतना पड़ता है। वरना हमारा इतना बड़ा देश है, हम 117 की जगह एक हजार भी भेज सकते थे। लेकिन आपको कोटा जीतना पड़ता है, तभी ओलंपिक में जाने के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ओलंपिक में जाना ही एक बहुत बड़ी बात है।

इस संसद के अंदर बहुत सारे ओलंपियन्स अभी भी बैठे हैं, यह भी हमारे लिए गर्व की बात है। इस ओलंपिक्स के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सब मिलजुकर काम कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो खिलाड़ी हैं, उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाएं। उनको अच्छे से अच्छे कोचेज उपलब्ध कराएं जाएं। दर्जनों फॉरेन कोचेज काम कर रहे हैं, फिजियोथेरपिस्ट्स काम कर रहे हैं, साइकॉलोजिस्ट्स उनकी मदद कर रहे हैं, मस्सेर्स साथ जा रहे हैं, ओलंपिक्स के जो खिलाड़ी जा रहे हैं, उनको हर तरह की सुविधा मिले, उनको हर तरह का सपोर्ट मिले।

माननीय सभापति जी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम के अंदर जितने भी एलीट स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन सभी को हर तरह की सुविधा दी गई है, जो वह चाहते थे। अगर वह बाहर कोचिंग के लिए जाना चाहते थे, बाहर प्रैक्टिस के लिए जाना चाहते थे, उनको किसी विदेशी कोच की आवश्यकता थी, उनको सब कुछ उपलब्ध कराया गया है। इसी के अंतर्गत स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक 'मिशन ओलंपिक्स सेल' भी बनाया है, जो डेडिकेटेड बॉडी है, जिसको डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेड करते हैं। सभी के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को हर संभव सपोर्ट दी जाए। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत योगदान लिया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत खेलों को

प्रोत्साहित करने के लिए काम किया है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, इसमें खासकर जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने इन्सपायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बनाया है, उसके अंदर बीस खिलाड़ी सीधे-सीधे सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 21 शूटर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसी के तर्ज पर ओलंपिक्स गोल्ड क्वेस्ट फाउन्डेशन है, जो बजाज फाउन्डेशन चला रहा है, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। इसी तरह से रिलायंस फाउन्डेशन, बीसीसीआई सभी अपना-अपना योगदान दे रहे हैं कि किस तरह से हमारा प्रदर्शन खेलों में अच्छा हो। खेलों के लिए देश के अंदर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

(1745/SK/SM)

हम बहुत बार खेलों को इतना प्रोत्साहन नहीं देते। यह बात भी सही है कि बच्चों को बहुत कम उम्र से खेलों के प्रति उत्साहित करने की आवश्यकता है। मैं दिल्ली और पूरे देश में भी देखता हूँ कि स्टेडियम्स तो बना देते हैं लेकिन इनमें खेलने का सामान नहीं होता है, कोचिस नहीं होते हैं, इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि हमें वर्ष 2028, 2032 और 2036 के लिए तैयारी करनी है। मैं समझता हूँ कि वर्ष 2024 के लिए बहुत अच्छी तैयारी की गई है। हम आशा करते हैं कि हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा होगा।

महोदय, जब हम खेलों की चर्चा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि खेल के लिए हमारी सर्वसहमति होनी चाहिए ताकि हम सब मिलजुलकर देश का गौरव बढ़ा सकें। कई बार मैं सुनता हूँ कि खेलों को लेकर राजनीति शुरू कर देते हैं, एक-दूसरे पर कटाक्ष शुरू कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के कटाक्ष करने से खेलों या खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। मेरा मानना है कि इसके लिए हम सब एकजुट होकर काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'खेलो इंडिया' की शुरुआत की है, मैं समझता हूँ कि यह बहुत अच्छा कदम है। इसके तहत हम खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा 'कीर्ति प्रोजेक्ट' में बचपन से ही टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पर काम किया जा रहा है, यह बहुत आवश्यक भी है। ये सब चीजें की जा रही हैं, लेकिन इसका रिजल्ट आने में समय लगता है।

महोदय, माननीय मंत्री मनसुख भाई जी ने जिस तरह से कोविड के दौरान अहम भूमिका निभाई थी, मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी उसी तरह से खेलों के प्रति भी बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। इससे आने वाले समय में ओलंपिक्स में खेलों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे तो आने वाले समय में देश को आगे बढ़ा सकेंगे। खेल हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं समझता हूँ कि 140 करोड़, जो कि देश जनसंख्या है, सभी की शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं खिलाड़ियों के साथ होंगी जब ये पेरिस में प्रदर्शन करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

(इति)

1748 hrs

\*SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam.

I thank you for allowing me to take part in this Discussion held under Rule 193 for ensuring the success of Indian sportspersons in the world's mega sports extravaganza, the Olympics. India having the largest population of the world is also having talented human resources. But there is a sea of difference when we compare the medals won by India in Olympics *vis-a-vis* the population of India. Hockey has brought us so many gold medals. In Olympics, India has so far won 8 Gold Medals through Hockey. But during the last 40 years we were unable to fetch not even a single medal. After finding the reason for this debacle, this Government has not included Abha Khatua, holder of world ranking of 21 in shot-put, in the Indian contingent for Olympics although she won Gold in the Asian Athletic Championship held in 2023 under shot-put by creating a record throw of 18.60 metre. How Indian athletes are selected for taking part in Olympics? This Government should say openly how these sportspersons are selected. There is no transparency in this selection process. Talented should be selected to take part in Olympics representing India.

We should ensure more participation by India in the forthcoming Olympics and ensuring the winning tally of more Medals for India. This discussion aimed to bring repute to India in world sports is really appreciable. But I wish to register that

---

\* Original in Tamil

how this Government had handled the Olympic medallists in the past. How this Government has handled the Olympic Medallists who staged agitations alleging sexual abuse by the then President of Wrestling Federation ... *(Not recorded)*

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): No name will go on record.

\*SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): I wish to remind you as to how the police personnel under the Union Government have handled the agitating sportspersons including the women wrestlers. Even the International Olympic Committee has condemned the way these wrestlers were treated and that Committee even had called for an unbiased enquiry into this matter. Unfortunately, other than Cricket all other games are not considered important in this country. In the past there were incidents where there was no ceremonial welcome accorded at the airports to those sportspersons returned home after winning international medals in games at international level. We should agree that even major sporting talent has not been yet identified. Especially in rural and backward areas, the sporting talent is yet to be identified which is really unfortunate. Government has the responsibility to identify them and take them to international arena. If they win medals, it is not only for them, it is a pride for the entire country as well.

Therefore, I urge that this Government should take part in nurturing these talents very well. Thank you.

(ends)



1752 hours

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Thank you very much, Sir. I will be very brief.

I join everybody in wishing the 117 athletes who are going to Paris to represent our great nation. I wish them very well. There is an interesting start. The top four States which have sent athletes to Paris are Haryana, Punjab, Tamil Nadu, and Uttar Pradesh. There is, actually, a strange commonality among all these four States. All these four States, actually, voted for the I.N.D.I Alliance in the recently concluded elections.

Sir, India has won a total of 35 medals in all the Olympics put together but a small country like Croatia, which only came into existence in 90s, has won 41 medals. The population of Croatia is about 38 lakhs, equal to the size of two Lok Sabha constituencies. So, if we really want to be an Olympic power, a couple of things need to be done. One, we need to broad-base sports participation and access to sporting facilities. The way to do it is to make sports a compulsory subject in Board Exams and make sure that participation in sports is compulsory. Until and unless sports is made compulsory in the educational system which is so examination-oriented it will be very difficult to broad-base sports. There are many schools which do not have playground. We cannot have a single school which does not have a playground to be recognised. If we do these two things, sports will be broad-based.

The second thing is that we need to focus on our elite sportsmen and I do compliment the Government on its top scheme but they need to allocate a lot more funds and to give the opportunity for sportsmen to travel, train, and hire the coaches of their own choice. If we do this, we can, definitely, become a significant player in the Olympics. I know, there is a lot of chatter and this Government particularly is taken in by vanity projects but please do not host the Olympics. I know, this is contrary to what I say. The two countries just similar to us, Greece and Brazil, which conducted the Olympics, faced severe hardships after conducting the Olympics. The Olympics is a great drain. It is better to put the money into development of athletes and not get into eager projects.

Sir, I finally conclude. May the spirit of Olympics “faster, higher, stronger – together” prevail. I wish the 117 athletes all the very best.

Thank you, Sir.

(ends)

(1755/NKL/SJN)

1755 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, Mr. Chairman Sir, for giving me this opportunity. I also take this opportunity to wish all the best to the Indian contingent which is in Paris. I hope, they come out with flying colours after the Olympics.

Sir, this is an important issue. I think, 'sports and games' is one of the best areas by which we are able to build up our nationhood, unity and integrity of India, beyond all castes, religion, and everything. It is the best way or the medium by which we can build up our nation. But it is quite unfortunate to note that India is the second most populous country in the world and has the lowest rank in terms of medals per capita. It is disappointing that a country that has world-class talent in various disciplines has not been able to produce champions in the area of sports.

Sir, compared to previous years, 2016 witnessed a large participation in Olympics. However, India has been able to bag only two medals. Our performance in Olympics over the past 60 years has shown limited improvements in terms of medals won, peaking only in the London 2012 Olympics. This had been achieved on account of increased investment in the field of sports infrastructure.

Sir, it is astonishing to note that so far, during our past 104 years of Olympics experience, we could only have 35 medals, out of which there are only 23 individual medals and rest of them are team medals. Just now, Mr. Karti Chidambaram has rightly pointed out that a country which is having less than 35 lakh or 40 lakh population is able to bag more medals. We have to take that point into account. We have to introspect ourselves that despite having 1.4 billion population, why we are not able to have a significant mark in international sports and games.

Sir, I would like to place some suggestions. We have to hunt the talented sports personnel from the school days onwards. I would like to quote a document of NITI Aayog. In September 2016, NITI Aayog published a document titled 'Let's Play', setting a target of 50 Olympic medals, providing a 20-point action plan, divided into short-term, medium-term and long-term plans.

Sir, now, NITI Aayog's expectation is that 50 medals will be bagged by our team. This 20-point action plan is divided into short-term, medium-term and long-term plans. So, what preparedness has the Government done for this purpose? The Government has to reply to this.

My suggestion to the Government is that you have to hunt the talented sports personnel from the school days. Moreover, there should be coaching of international standards. I have a suggestion that in each and every Parliamentary constituency, a full-fledged stadium has to be constructed for which all the facilities should be provided. Moreover, the privileges and benefits should be given to sports personnel, thus providing them employment opportunities.

Sir, the last suggestion I would like to make is to depoliticize sports. Who is administering sports in our country? India's sports administration is dominated by politicians and bureaucrats who have a hegemony to look at, leaving sportspersons' interests to take a secondary place. The latest confrontation in the Wrestling Federation is a typical example of this. So, depoliticize sports; let us have the sportsman spirit in a true sense, so that we can have a long-term plan to achieve in the international arena. With these words, I conclude. Thank you very much.

(ends)

1759 बजे

**एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) :** माननीय सभापति जी, आपने मेरा नाम आखिरी में लिया है। मैं तो साढ़े तीन घंटे से इंतजार कर रहा था कि मुझे बोलने का अवसर मिलेगा।

**माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) :** आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको बोलने का अवसर मिल रहा है।

**एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) :** महोदय, आप चेयर पर बैठे हैं और हमें बोलने का अवसर न मिले, यह कैसे हो सकता है? आप तो नए मेंबर्स के लिए अवसर पैदा करते हैं।

महोदय, मैं सबसे पहले आपके और इस सदन के माध्यम से पेरिस ओलंपिक खेलों में जाने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ, मंगलकामनाएं करता हूँ।

(1800/SPS/VR)

मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। हम ग्रामीण अंचल से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में न तो स्टेडियम्स हैं, न स्पोर्ट्स कॉलेजेज़ हैं, न यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्रतिभा का कोई मोल ही नहीं है। हम खुद अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन अवसर ही नहीं मिला। हमें यहां आने में भी बहुत समय लगा और सड़कों पर संघर्ष करना पड़ा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसके लिए सरकार को योजना चलानी चाहिए। अभी क्या योजना है? ... (व्यवधान)

**माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) :** आपकी स्पीच खत्म होने तक सदन की कार्यवाही बढ़ाई जाती है। आपकी स्पीच पूरी होने तक सदन की कार्यवाही चलेगी। अभी 6 बज रहे हैं, अधिकांशतः इस समय तक सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है, लेकिन आपकी स्पीच शुरू हो गई है तो आपकी स्पीच खत्म होने तक सदन की कार्यवाही बढ़ाई जाती है। कृपया आप अपनी बात पांच मिनट में कन्क्लूड कीजिए।

**एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) :** सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना भी चाहता हूँ कि ग्रामीण अंचल में एससी, एसटी तथा ओबीसी के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं एवं इस संबंध में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है? क्या उप श्रेणी खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा अलग से कोई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है? उक्त खेलों में अलग-अलग स्पर्धाओं में उक्त श्रेणी के कुल कितने खिलाड़ियों को भेजे जाने का प्रस्ताव है? इन सब खिलाड़ियों का श्रेणीवार कुल कितना प्रतिनिधित्व रहेगा?

महोदय, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि खेल में जाति और धर्म नहीं होता है, लेकिन जाति तो है। बच्चे के नाम के साथ सरनेम लगा होता है और उस देश में जाति न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे आज भी याद है कि जब हिमा दास मेडल लेकर आई थीं तो सबसे पहले उसकी जाति सर्च की गई थी। वंदना कटारिया, जो हॉकी की एक एससी प्लेयर बच्ची है, उसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी उसके घर के बाहर उसे बेइज्जत करने का प्रयास किया गया। इसके साथ-साथ साक्षी और विनेश के साथ क्या हुआ, हम लोग यह भी नहीं भूले हैं। ... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** दादा, आप बीच में बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except the speech of Shri Chandra Shekhar.

... (Interruptions) ... (Not recorded)

**एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) :** मान्यवर, आप मेरी तरफ देखिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वह नगीना, सहारनपुर है। मैं उस क्षेत्र के गांवों में जाता हूँ। वहां पर बहुत प्रतिभा है, लेकिन अवसर नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि वह देखे कि गांव में प्रतिभा की कमी नहीं है और इनको कुचला न जाए, क्योंकि इसमें पक्षपात होता है। इस पक्षपात को खत्म किया जाए। कब तक एकलव्य का अंगूठा कटता रहेगा? अब तो हमें अवसर मिलने चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। आपने मुझे मौका दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।

(इति)

**माननीय सभापति :** सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 23 जुलाई, 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1802 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 23 जुलाई 2024 /1 श्रावण 1946 (शक)  
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।